

पूँजीवाद का आम-संकट

लेखक

वी० त्रेपेत्कोव

अनुवादक

जुगमंदिर तायल



राजस्थान पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा) लि
छमेनीवाला मार्केट, एम. आर्द्ध. रोड, जयपुर 302001

General Crisis of Capitalism
का हिन्दी अनुवाद

English Edition

- © Progress Publishers, Moscow
In arrangement with
Mezhdunarodnaya Kniga, Moscow

हिन्दी संस्करण

- © राजस्थान पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा०) लि०
चमेलीवाला मार्केट, एम० आई० रोड,
जयपुर-302001

1985 (RPPH 5)

मूल्य : 6.00

अनुक्रम

	5
अध्याय : 1 : पूँजीवाद के आम-संकट की उत्पत्ति और उसका सारतत्त्व	9
पूँजीवाद के आम-संकट की ऐतिहासिक अनिवार्यता	9
पूँजीवाद के आम-संकट का सारतत्त्व	14
अध्याय : 2 : विप्लव का दो विरोधी सामाजिक-व्यवस्थाओं में विभाजन और उनके बीच संघर्ष	20
रूस में महान अक्टूबर समाजवादी क्रान्ति की विजय और विश्व का दो व्यवस्थाओं में विभाजन	20
दो विरोधी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष और पूँजीवाद के आम-संकट का गहरा होना	25
अध्याय : 3 : साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था का संकट और पतन	32
उपनिवेशी व्यवस्था का पतन पूँजीवाद के आम-संकट की एक अभिव्यक्ति	32
नव-उपनिवेशवाद	40
विकासशील देशों की अर्धव्यवस्थाओं के विद्रिष्ट मरण	47
अध्याय : 4 : पूँजीवादी अर्धव्यवस्था की बढ़ती हुई अस्थिरता और पतनशीलता	64
उत्पादन-दक्षताओं का स्थायी अपूर्ण-उपयोग	64
बहुमध्य बेरोजगारी की दूरानी बीमारी	66
अर्धव्यवस्था का सैम्ब्रीकरण	68
आर्थिक-संकट	71
बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति और लीज बने-जघन	73

अध्याय : 5 : राज्य-इजारेदार पूंजीवाद का विकास

इजारेदार पूंजीवाद का राज्य-इजारेदार पूंजीवाद
रूप में विकास

राज्य-इजारेदार पूंजीवाद के प्रमुख रूप

राज्य-इजारेदार पूंजीवाद और समाजवाद के नि
परिस्थितियों का निर्माण

अध्याय : 6 . पूंजीवादी राजनीति और विचारधारा का
बढ़ता हुआ संकट

पूंजीवादी देशों में बढ़ा हुआ राजनैतिक प्रतिक्रिया
पूंजीपति वर्ग की विचारधारा का गहरा होता सं

प्रस्तावना

जिस ऐतिहासिक युग में हम जी रहे हैं, उसकी मूल विशेषता पूंजीवाद से समाजवाद की ओर क्रांतिकारी संक्रमण है। मार्क्स-एंगेल्स और लेनिन ने जिस सामाजिक परिवर्तन का पूर्व-अनुमान किया था, वह अब सब हो रहा है। पूंजीवादी दुनिया की नींव चरमरा रही है और सारे संसार में समाजवाद की स्थिति अधिक-से-अधिक मजबूत होती जा रही है।

सामाजिक विकास के वस्तुगत नियमों की खोज करते हुए मार्क्सवाद-लेनिनवाद पूंजीवाद के भीतरी अंतर्विरोधों का उद्घाटन करता है और यह बताता है कि समाज में क्रांतिकारी विस्फोट तथा एक नयी सामाजिक-संघटना में समाज का संक्रमण अवश्यभावी है। मार्क्स और एंगेल्स ने पूंजीवाद से समाजवाद की ओर क्रांतिकारी संक्रमण की ऐतिहासिक आवश्यकता की सैद्धांतिक-आधारभूमि को प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि अन्य सभी पूर्ववर्ती सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओं के समान पूंजीवादी उत्पादन-शक्ति भी ऐतिहासिक दृष्टि से अल्पकालिक है और जैसे पहले आदिम जनजातीय व्यवस्था का स्थान दास-स्वामियों के समाज ने, दास-स्वामियों के समाज का स्थान सामन्तवाद ने तथा सामन्तवाद का स्थान पूंजीवाद ने लिया था वैसे ही पूंजीवाद का स्थान अनिवार्य रूप से साम्यवाद लेगा।

पूंजीवादी उत्पादन-शक्ति की प्रमुख विशेषता ऐसा अंतर्विरोध है जिसका समाधान नहीं हो सकता, जो अनिवार्य रूप से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तनों को जन्म देता है तथा एक नयी सामाजिक-संघटना की ओर क्रमिक रूप से ब-क़दम-ब-क़दम आगे बढ़ता है। मार्क्स और एंगेल्स के युग में अर्थात् 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाजवादी क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक वस्तुगत ब-आत्मगन परिस्थितियाँ पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई थीं। 1915 में लेनिन ने लिखा था : 'अर्धशताब्दी पहले सर्वहारा बर्ग बहुत कमजोर था। समाजवाद की सफलता के

लिए वस्तुगत परिस्थितियाँ तब तक परिपक्व नहीं हुई थीं। वे परिस्थितियाँ 19वीं शताब्दी के अंतिम तथा बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में विकसित हुईं जब पूँजीवाद ने अपने विकास के इजारेदार-पूँजीवादी दौर में प्रवेश किया।

पूँजीवाद के (जिसकी प्रमुख विशेषता मुक्त प्रतियोगिता है) साम्राज्यवाद के रूप में विकसित हो जाने के परिणामस्वरूप पूँजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था व राजनीति में गहरे परिवर्तन हुए। सर्वहारा के बढ़ते हुए संघर्षों ने मार्क्सवादी दृष्टि से इन परिवर्तनों के अध्ययन की बलपूर्वक माँग की। मार्क्स व एंगेल्स के कार्य को जारी रखते हुए यह ऐतिहासिक कार्य लेनिन ने पूरा किया। अपने अध्ययन-कार्य के दौरान तथा 19वीं शताब्दी के अंतिम व बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों की पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों की जानकारी देने वाली विशाल तथ्यात्मक-सामग्री का सैद्धांतिक-सामान्यीकरण करते हुए लेनिन ने मार्क्स की शिक्षाओं का विकास किया और उन्हें आगे बढ़ाते हुए साम्राज्यवाद के नये सिद्धांत का निर्माण किया।

साम्राज्यवाद के आर्थिक सारतत्व का विश्लेषण करते हुए लेनिन ने बताया कि मुक्त प्रतियोगिता के क्षेत्र को कम करके बीसवीं शताब्दी के आरंभ में पूँजी तथा उत्पादन के केन्द्रीकरण व सँकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया ने अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा जमा लेने वाले पूँजीपतियों के शक्तिशाली गठबंधनों को जन्म दिया। इस प्रक्रिया ने इजारेदार बैंकिंग पूँजी का इजारेदार औद्योगिक पूँजी में विलय करके वित्तीय पूँजी तथा वित्तीय कुलीन तंत्र को भी जन्म दिया और इसके साथ पूँजी के निर्यात को भी तेजी से बढ़ाया। इसके परिणामस्वरूप न केवल राष्ट्रीय बल्कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियों का निर्माण हुआ जिनमें पूँजीवादी देशों के अनेक समूह शामिल थे। इन इजारेदारियों ने विश्व का (जिसका सबसे बड़े पूँजीवादी देशों के बीच क्षेत्रीय विभाजन पहले ही हो चुका था) आर्थिक विभाजन शुरू किया। पूँजीवाद का मूल सक्षण—इजारेदारियों का आधिपत्य—इन नियमों के अतर्गत विभिन्न रूपों में प्रकट होता है।

लेनिन पूँजीवाद की इजारेदारी-अवस्था के रूप में साम्राज्यवाद के आर्थिक सारतत्व को स्पष्ट करने तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने यह भी बताया कि पूँजीवाद की मूल विशेषताओं के विकास तथा उनकी निरंतरता के रूप में ही साम्राज्यवाद का उदय हुआ है, तथा यह पूँजीवाद उत्पादन-मंडति की ही एक विशिष्ट अवस्था है। इसकी विशेषताएँ तीन हैं—(1) साम्राज्यवाद अवलंब्य अथवा परजीवी व मरणामन्न इजारेदार पूँजीवाद है, (2) मुक्त प्रतियोगिता वाले पूँजी-

1. वी० आई० लेनिन—मार्क्सवाद और मुद्द : मुद्द के प्रति सभी सामाजिक वर्गों की बलपूर्वक माँग का दृष्टिकोण। सर्वप्रथम रचनाएँ, भाग 21, पृष्ठ 313, प्रथम प्रकाशन, मार्च 1974 (दूसरी सं.)

वाद के सदर्भ में यह पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है और इसके साथ, (3) यह पूंजीवाद की अंतिम अवस्था व समाजवादी क्रांति की पूर्ण सध्या भी है।

लेनिन ने साम्राज्यवाद को मरते हुए पूंजीवाद के रूप में विवेचित किया और यह रेखांकित किया कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद के समस्त अंतर्विरोधों को तीव्रतर कर देता है। उन्होंने लिखा: "अंतर्विरोधों का यह तीव्रीकरण इतिहास के उस संक्रमण-काल की सबसे अधिक बलवान व गतिशील-शक्ति होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय वस्तीय पूंजी की अंतिम विजय के साथ आरंभ होता है।" पूंजीवाद के समस्त अंतर्विरोधों का यह अत्यंत तीव्रीकरण ही (जोकि साम्राज्यवाद के युग की विशेषता है) पूंजीवाद के पतन व समाजवादी क्रांति के विजय की ऐतिहासिक अनिवार्यता को निश्चित करता है।

साम्राज्यवाद के नियमों के विश्लेषण से लेनिन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पूंजीवाद के पतन के भीतर सर्वहारा समाजवादी क्रांति की विजय की परिस्थितियाँ परिपक्व हो चुकी हैं और संसार ने पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश व समाजवादी क्रांति और राष्ट्रीय मुक्ति क्रांतियों के युग में प्रवेश कर लिया है। इतिहास ने लेनिन के इन निष्कर्षों को पुष्ट किया है कि समाजवादी क्रांति सामाजिक-विकास के वस्तुनिष्ठ नियमों के अनुसार होती है और पूंजीवादी समाज के भीतरी अंतर्विरोध इसके मुख्य कारण होते हैं। समाजवादी क्रांति की सफलता इस पर निर्भर होती है कि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की परिपक्वता किस स्तर पर है।

भूमंडलीय स्तर पर पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना का क्रांतिकारी परिवर्तन एक ऐसे ऐतिहासिक युग में होता है, जिसमें पूंजीवाद आम-संकट से घिरता जाता है। पूंजीवाद के आम-संकट के सारतत्त्व व इसके विकास के संपूर्ण दौरों की समझ, लेनिन के साम्राज्यवाद के सिद्धांत तथा इस सिद्धांत पर आधारित समाजवादी क्रांति के सिद्धांत के द्वारा ही संभव है। पूंजीवाद का आम-संकट पूंजीवाद के विकास की साम्राज्यवादी अवस्था में उसके तमाम अंतर्विरोधों के लगातार तीव्र होते जाने का अनिवार्य परिणाम है। साम्राज्यवाद का ऐतिहासिक स्थान निश्चित करते हुए लेनिन ने उसके साथ-साथ पूंजीवाद के आम-संकट के सिद्धांत की आधार-शिलाओं का भी विकास किया।

पूंजीवाद के आम-संकट के संबंध में लेनिन ने जो कुछ लिखा है वह मार्क्स-वादी-लेनिनवादी दलों के सामान्य क्रियाकलाप और सभी देशों में सर्वहारा के क्रांतिकारी संघर्षों के लिए बहुत मूल्यवान है। लेनिन ने एक नये ऐतिहासिक युग—साम्राज्यवाद व सर्वहारा क्रांति का युग तथा पूंजीवाद से समाजवाद की ओर संक्रमण व साम्यवादी समाज के निर्माण का युग—के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत

1. थो० आई० लेनिन—'साम्राज्यवाद : पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था', सवित्त रचनाएँ, भाग 22, पृ० 300 (अध्याय 10)

का प्रयोग के विरुद्ध विचार ।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रस्तावों, कम्युनिस्ट तथा सहज रूप से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और सामाजिक-वैज्ञानिक दलों के प्रस्तावों में पूर्वी-पश्चिम के आस-सफा के संबंध में सोवियत के विचार का और अधिक स्पष्टतापूर्ण विचार किया गया है ।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 25वीं कांग्रेस के आयोजन से हुए विद्योत्पन्न संशोधन के अलावा 'पूर्वी-पश्चिम के संबंध में' की योजना का कम्युनिस्ट विचार-प्रणाली के लिए बहुत दूर की सीमा है । पूर्वी-पश्चिम के बीच अभी जारी आरंभित संघर्ष है । इस भी, हमारे देशों की अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था का प्रभाव है कि पूर्वी-पश्चिम एक अर्थव्यवस्था-संशोधन का अर्थव्यवस्था है ।¹

हमारे समय में लड़ने वाले पूर्वी-पश्चिम के आस-सफा को पूर्वी-पश्चिम के विचार की सामाजिक विशेषताओं के अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था है । यह प्रक्रिया सामाजिकवाद के भीतरी अर्थव्यवस्था और नये अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के एक में हो जाने के कारण हो रही है ।

निरंतर बढ़ता हुआ पूर्वी-पश्चिम का आस-सफा आज के एक ही वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं—सामाजिकवाद और राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों—के बीच अर्थव्यवस्था के एक में परिवर्तित नये अर्थव्यवस्था के एक में ही प्रकट नहीं होगा है, बल्कि विद्योत्पन्न पूर्वी-पश्चिम देशों में निरंतर बढ़ती आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भी प्रकट होगा है । ये नारी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के एक अर्थव्यवस्था में संघी है । ये वैज्ञानिक-अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में भी प्रकटित हैं जो अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था को बढ़ाती है तथा साथ ही पूर्वी-पश्चिम के सामाजिक संघर्षों का और अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था पर पुनरर्थव्यवस्था करती है ।

1. सियोलिट बोसोव—सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की एक और गृह व विदेश नीति में पार्टी के तारकालिक कार्यक्रम, मोस्कोली प्रेस एजेंसी प्रकाशन 1976, पृष्ठ 34 (अंग्रेजी में)

पूँजीवाद के आम-संकट की उत्पत्ति और उसका सारतत्त्व

पूँजीवाद के आम-संकट की ऐतिहासिक अनिवार्यता

पूँजीवाद का आम-संकट इसके भीतरी विरोधी अन्तर्द्वंद्वों से जो पूँजीवादी विकास की इजारेदारी अवस्था में तीव्रतम हो जाते हैं, उत्पन्न होता है। जैसा कि निन ने बताया है, पूँजीवाद का आम-संकट कोई संयोगजन्य घटना नहीं है, बल्कि पूँजीवाद के पतन और शय के दौरान अवश्यभावी तथा प्राकृतिक अवस्था है। निन ने जोर देकर कहा है, 'पूँजीवाद का शासन इसलिए मष्ट नहीं होता है कि अन्य कोई व्यक्ति सत्ता पर कब्जा करने के लिए तत्पर है' 'यदि पूँजीवादी देशों का समस्त आर्थिक विकास पतन की ओर अग्रसर नहीं हो तो पूँजीवादी-शासन का पतन करना असंभव होगा' 'यदि पूँजीवाद इतिहास के द्वारा अशक्य और निर्बल ही बना दिया जाये तो कोई भी शक्ति इसे मष्ट नहीं कर सकती।'¹

उत्पादन-शक्तियों के समातार विकास के कारण, उत्पादन-साधनों के निजी स्वामित्व पर आधारित पूँजीवादी उत्पादन-संबंध पुराने होने लगने हैं। पूँजीवादी उत्पादन-संबंध सामाजिक-आर्थिक विकास में अधिक-से-अधिक बाधा डालने लगने हैं। 19वीं शताब्दी का अंत होने तक इजारेदारों के आधिपत्य और पूँजीवादी संबंध आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हो जाने के कारण, उत्पादन शक्तियों व पूँजीवादी उत्पादन संबंधों के बीच अंतर्विरोध बहुत ही तीव्र हो गये। अब तक अज्ञान, उत्पादन का अप्रभूतपूर्व मकेंद्रीकरण और विग्व-अर्थव्यवस्था के ढाँचे में बहुत से देशों के शामिल हो जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन-शक्तियों की ऐसी आन्तरिक-विकासक अभिवृद्धि हुई कि पूँजीवादी उत्पादन संबंध उत्पादन-शक्तियों के विकास में

1 श्री० आर्० लेनिन, 'यूट और क्रांति', पृ० 14 (27) 1917 को दिया गला कृपण, लकनौ एचकार्ड, भाग 24, पृ० 43 (अध्यायी के)

प्रेरक शक्ति बनने के स्थान पर बेटी बन गये। मानवता के सामने प्रबल उत्पादन-शक्तियों को स्वतंत्र करने तथा उनके भावी विकास के लिए पूरा क्षेत्र प्रदान करने तथा समाज के हित में उनका उपयोग करने की जरूरत उत्पन्न हो गई। यह जरूरत उत्पन्न हो गई कि क्रांति के द्वारा, जो पूँजीवादी उत्पादन संबंधों को नष्ट कर देगी, इस द्वंद्व का समाधान किया जाये।

इजारेदारी आधिपत्य विश्वस्तरीय पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के निर्माण, जो कि साम्राज्यवाद के अंतर्गत पूर्ण हुई, ने पूँजीवादी उत्पादन की सामाजिक प्रकृति को अधिक तीव्र और गहन किया। लेनिन ने लिखा है—“पूँजीवाद अपनी साम्राज्यवादी अवस्था में, उत्पादन के परिपूर्ण समाजीकरण की ओर सीधा भागे बढ़ता है और पूँजीपतियों को, उनकी इच्छा व चेतना के विरुद्ध कुछ नये प्रकार की सामाजिक व्यवस्था—पूर्ण मुक्त प्रतियोगिता से पूर्ण समाजीकरण की ओर सक्रमण की व्यवस्था—में धींच लेता है।”¹ किन्तु उत्पादन का समाजीकरण निजी पूँजी द्वारा उत्पादन के सारे लाभों को ग्रहण किये जाने के विरोध में है। साम्राज्यवाद के अंतर्गत करोड़ों मजदूरों के सामूहिक परिश्रम का लाभ शक्तिशाली उद्योगपतियों का एक छोटा समूह उठाता है। उत्पादन के सामाजिक चरित्र तथा लाभ ग्रहण करने की निजी संपत्ति वाली व्यवस्था के बीच अंतर्विरोध पहले कभी इतना तीव्र व गहरा नहीं होता है जैसा पूँजीवादी विकास की इजारेदारी अर्थात् साम्राज्यवादी अवस्था में होता है।

उत्पादन का समाजीकरण यह प्रकट करता है कि स्वयं पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर अर्थव्यवस्था के लोक-नियंत्रण की परिस्थितियाँ परिपक्व हो रही हैं और निजी पूँजीवादी-स्वामित्व की व्यवस्था इसके सारतत्त्व के अनुकूल नहीं रह गई है। उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को लोक-स्वामित्व में बदलना आवश्यक हो जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि कुल मिलाकर पूँजीवाद से समाजवाद की ओर क्रांतिकारी सक्रमण की वस्तुनिष्ठ भौतिक परिस्थितियाँ परिपक्व हो गयी हैं।

साम्राज्यवाद के अंतर्गत पूँजी और श्रम के बीच अंतर्विरोध तीव्र हो जाते हैं। इजारेदार पूँजीपति इजारेदारी-मूल्य, जो शोषण का एक नया साधन है, लागू करते हैं। इसमें उन्हें न केवल अनिश्चित मूल्य ही, बल्कि श्रम की कीमत का एक भाग भी मिलने लगता है। आधुनिक तकनीक व उत्पादन की अभियांत्रिक प्रकृति के प्रयोग में इजारेदार-समूह श्रम को सघन बनाने तथा शोषण को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। परिणाम स्वरूप सर्वहारा के रोष में वृद्धि होती है।

1. वी० आई० लेनिन, साम्राज्यवाद - पूँजीवाद की उत्पन्न अवस्था, संकलित रचनाएँ, भाग 22, पृ० 205 (बेबी वे)

इजारेदार पूंजीपति वर्ग तथा अन्य वर्गों व सामाजिक सस्तरो—किसान, व मध्यम पूंजी वाले शहरी वर्ग, बुद्धिजीवी—के बीच अंतर्विरोधों का बढ़ना रहता है। इससे समाज के नातिकारी रूपांतरण के सघर्ष को विकसित करने एवं मजदूर वर्ग के नेतृत्व में समस्त जनवादी शक्तियों के एक साम्राज्यवादी गठजोड़ में एकताबद्ध होने की परिस्थितियाँ बनती हैं।

साम्राज्यवादी देशों के भीतर सामाजिक अंतर्विरोधों के निरंतर बढ़ते जाने से राष्ट्रीय अंतर्विरोध, प्रमुख रूप से साम्राज्यवादी देशों के इजारेदार पूंजीपति पराधीन देशों की शोषित जनता के बीच अंतर्विरोध बढ़ने लगते हैं। साम्राज्यवादी देशों के इजारेदार पूंजीपति पराधीन देशों की कीमत पर अपने अंतर्विरोधों को दूर करने व अधिक-से-अधिक लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। पूंजी का निर्यात करके और वस्तुओं के असमान विनिमय के द्वारा इजारेदार पूंजीपति वर्ग पराधीन देशों की जनता द्वारा उत्पन्न भारी मूल्य को हड़पते हैं। उत्पीड़न और शोषण का अनिवार्य परिणाम प्रतिरोध है। जन-समूह दृढ़-व्यय से संपूर्ण राजनीतिक व पूंजीपति वर्ग और उपनिवेशी व पराधीन देशों की ता के बीच अंतर्विरोधों की अभिवृद्धि, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के विकास परिपक्वता के लिए वस्तुनिष्ठ आधारशिला का काम देती है। इसका अर्थ यह है कि साम्राज्यवादी ढाँचे के भीतर ही उपनिवेशी व पराधीन देश इजारेदारी के आरक्षित-क्षेत्र बदलकर सर्वहारा क्रांति की प्रभावी शक्ति बन जाते

साम्राज्यवाद के अंतर्गत साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच आपसी अंतर्विरोध बढ़ जाते हैं। हरेक इजारेदार-समूह विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दूमरे देशों इजारेदार-समूहों की स्थिति को निर्वसल करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए प्रयत्नशील होता है। वे ऊँचे मुनाफे कमाने, बाजारों व कच्चे माल के स्रोतों पर अधिकार व पुनर्वितरण और लाभदायक विनियोग क्षेत्रों के लिए आपस में प्रयत्नशील रूप से लड़ाई लड़ते हैं। परिणाम यह होता है कि साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच तीव्र रूप में बढ़े हुए अंतर्विरोध सामने आते हैं। इसमें साम्राज्यवाद की शक्ति कमजोर हो जाती है और वस्तुनिष्ठ रूप से राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन व समाजवादी क्रांति की सफलता की संभावनाएँ बढ़ती हैं।

साम्राज्यवाद के युग की विशेषता, पूंजीवाद से समाजवाद की ओर मजबूत रूप से बढ़ती वस्तुनिष्ठ (भौतिक और सामाजिक) परिस्थितियों का परिपक्व होना नहीं है, बल्कि आवश्यक आत्मनिष्ठ परिस्थितियों की रचना भी है। इसे मजदूर वर्गों की बढ़ती चेतना व संगठन, सामूहिक क्रांतिकारी कार्यवाही के लिए हमची परतता, मजदूर वर्ग व पैर-सर्वहारा जनसमूहों (विशेष रूप से मेहनतकश किसान) के बीच मजबूत गठबंधन, मार्क्सवादी-लेनिनवादी दलों के बढ़ते प्रभाव और राष्ट्रीय

मुक्ति आंदोलनों, जो समाजवादी क्रांति के पक्ष में प्रभावी शक्ति हैं, के विकास के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, पूंजीवाद में समाजवाद की ओर संक्रमण के लिए वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ परिस्थितियों के परिणाम होने की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न देशों में एक साथ तथा एक समान रूप में नहीं होती है। यह तथ्य लेनिन द्वारा रचित साम्राज्यवाद के युग में पूंजीवाद के आर्थिक-राजनीतिक अग्रगण्य विभाग होने के वस्तुनिष्ठ नियम की विजातीयता का संदर्भ है।

इजारेदार पूंजीवाद की अवस्था में आर्थिक विकास गिरावट अग्रगण्य ही नहीं होता है (अग्रगण्य-विभाग हमारे पूर्व भी पूंजीवाद की विशेषता होती है) बल्कि अनियमित भी होता है। साम्राज्यवाद के युग में पूंजीवादी देशों का अग्रगण्य आर्थिक विकास उनके अग्रगण्य राजनीतिक विकास से निश्चय से जुड़ा है। 1916 में लेनिन ने लिखा था—“पूंजीवाद का विकास विभिन्न देशों में अलग-अलग रूप में आगे बढ़ता है” हमारे असाध्य रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि समाजवाद सभी देशों में एक साथ विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यह पहले एक या दो देशों में विजयी होगा जबकि अन्य देश कुछ समय के लिए पूंजीवादी या पूर्व-पूंजीवादी अवस्था में बने रहेंगे।” अतः विभिन्न देशों में समाजवादी क्रांति की परिस्थितियाँ विभिन्न रूपों में विकसित होती हैं। इस कारण समाजवादी क्रांति पहले उस देश में होती है जहाँ उसके लिए परिस्थितियाँ सबसे जल्दी परिपक्व होती हैं। पूंजीवाद की इजारेदारी अवस्था में होने वाला अनियमित विकास पूंजीवादी देशों के बीच तीव्र अंतर्विरोधों तथा द्वंद्वों को जन्म देता है। इससे विश्व पूंजीवादी व्यवस्था समग्रतः कमजोर होती है और कुछ देशों में समाजवादी क्रांति की सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन जाती हैं। इस प्रकार पूंजीवाद के आम-संकट के उदय और उसके गहराने से समाजवाद द्वारा पूंजीवाद के क्रांतिकारी प्रतिस्थापन की ओर वस्तुनिष्ठ रूप से प्रगति होती है। किंतु यह प्रतिस्थापन एक साथ नहीं होता, यह एक पूरे ऐतिहासिक दौर में जीवित रहता है और इसके मुख्यात की घोषणा एक देश में समाजवादी क्रांतिकारी की विजय से होती है।

पूंजीवाद के आम-संकट की पूर्वपिछाएँ इजारेदार पूंजीवाद में अंतर्निहित अंतर्विरोधों के उभरने के साथ ही प्रकट व एकत्र होना शुरू कर देती हैं। पहला महायुद्ध, जो साम्राज्यवादी देशों के बीच विश्व के क्षेत्रीय पुनर्वितरण की इच्छा के कारण उस समय मौजूद अंतर्विरोधों के स्वतः विस्फोट का परिणाम था, पूंजीवाद के आम-संकट की मुख्यात को सामने लाया। इजारेदार पूंजीपति वर्ग ने सोचा था कि

1. वी० आई० लेनिन, 'सर्वहारा क्रांति का सैनिक कार्यक्रम', संकलित रचनाएँ, भाग 23, पृ० 79 (अध्याय 3)।

वे शक्ति-प्रयोग द्वारा अपने हितानुसार विश्व का पुनर्विभाजन कर सकते हैं और साथ ही क्रांतिकारी आंदोलन का दमन करके साम्राज्यवाद की स्थिति को मजबूत भी बना सकते हैं। लेकिन युद्ध का उल्टा नतीजा सामने आया—उमन पूंजीवादी समाज के भीतरी व बाहरी अंतर्विरोधों का समाधान तो नहीं ही किया, उन्हें तीव्र और उग्र कर दिया। हमने भारी मात्रा में भौतिक नुकसान किया, विशाल मात्रा में मानव-जीवन की हानि की और मेहनतकशों की गरीबी तथा पीड़ा को उस समय चरम सीमा पर पहुँचा दिया। इसके साथ युद्ध ने इजारेदारों को भारी मात्रा में समूह होने में सहायता भी दी। अमेरिका के पूंजीपतियों ने विशेष रूप से भारी लाभ कमाया क्योंकि सैनिक सामान की बिक्री में उनके मुनाफे शान्तकाल की तुलना में तीन-चार गुना ज्यादा हो गये।

पहले महायुद्ध ने पूंजीवादी अंतर्विरोधों को बहुत अधिक बढ़ाया अतः पूंजीवादी देशों में क्रांतिकारी विस्फोटों को जन्म दिया। उत्पीड़ित जनसमूहों के राष्ट्रीय-मुक्ति आंदोलनों को जाग्रत किया। उस समय लेनिन ने लिखा था— यूरोपीय महायुद्ध एक भारी ऐतिहासिक संकट है। एक नये युग की शुरुआत है। अन्य किसी संकट के समान युद्ध ने गहराई में दबे विरोधों को बढ़ा दिया है और उन्हें धरातल के ऊपर ला दिया है।¹

पहले महायुद्ध ने संपूर्ण साम्राज्यवादी व्यवस्था को शक्ति को कम किया और साम्राज्यवादी जजूर को, उसके सबसे कमजोर हिस्से पर तोड़न में सहायता दी। वास्तव में साम्राज्यवादी व्यवस्था में वह कड़ी और उससे समस्त अंतर्विरोधों का केन्द्र-बिंदु रूस सिद्ध हुआ। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में रूस समाजवादी क्रांति के लिए आवश्यक वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ परिस्थितियों का उपयुक्त म्यान हो गया था। समाजवादी अक्टूबर क्रांति (1917) ने रूस में समूची दुनिया के लिए महत्त्व की ऐतिहासिक प्रक्रिया—समाजवाद द्वारा पूंजीवाद की प्रतिस्थापना की प्रक्रिया—आरंभ की।

पहला महायुद्ध और महान् समाजवादी अक्टूबर क्रांति ने पूंजीवाद के आम-संकट की शुरुआत को रेखांकित किया। पहले महायुद्ध के संघर्ष में लेनिन का यह मूल्यांकन था कि सामाजिक क्रांति की तुलना में यह एक छोटा संकट था एक पूंजीवादी-साम्राज्यवादी संकट था। उन्होंने आसन्न समाजवादी क्रांति को बढ़ा संकट माना। इसका अर्थ यह है कि महान् समाजवादी अक्टूबर क्रांति ने पूंजीवादी व्यवस्था के विनाश और समाजवादी-व्यवस्था की ओर सन्नमन के युग की शुरुआत की।

1. वी० आर्० लेनिन, 'युग अंधकारवाद और जीवन समाजवाद इतरनेशनल की पुनर्स्थापना कैसे हो सकती है', संकलित रचनाएँ, भाग 2। पृ० 94 (अंग्रेजी में)।

दूगने महादुःख का अंत विचार-समाजवादी व्यवस्था के जन्म और उनके सबूत होने के साथ हुआ। इसके साथ सबदूर वर्ग व राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों में अस्ति-शामी उधार आया और सामाजवाद की उपनिवेशी व्यवस्था का निर्माण बन हुआ। राष्ट्रों का एक बड़ा समूह, जिनमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, अब अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ देशों ने विकास के क्षेत्र-पूँजीवादी रास्ते को चुना है और वे व्यापक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक सुधार कर रहे हैं। इन देशों के भीतर मार्क्सवादी व पूँजीवादी शोषण संबंधों के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है। इन देशों की विदेश नीति साम्राज्यवाद विरोधी है।

पूँजीवाद के आम-संकट का तीव्र विनिष्ट सक्षण साम्राज्यवादी देशों के भीतरी अंतर्विरोधों का बढ़ जाना और आर्थिक ध्वंसना का तीव्र शय हो जाना है। यह विकास-दरों के तीव्र उतार-चढ़ाव, अममान आर्थिक विकास, बढ़ती दरों में बार-बार आते सबूत, उत्पादन क्षमता का समाप्त कम उपयोग, दीर्घकालीन बेरोजगारी, तेजी से बढ़ती मुद्रास्फूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय मीट्रिक संबंधों में मकट, वर्ण-व्यवस्था के संगीकरण आदि के रूप में प्रकट होता है। राजकीय इजारेदार पूँजीवाद—जो पूँजीवादी व्यवस्था के निर्वहन हो जाने और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इजारेदार पूँजीवाद द्वारा राज्य-शक्ति के प्रयोग की इच्छा का परिणाम है, पूँजीवाद के अंतर्विरोधों को दूर करने में अममर्ष है और अंत में उन अंतर्विरोधों को जटिल व उष बनाना है।

पूँजीवाद के आम-संकट का चौथा प्रमुख सक्षण पूँजीवादी राजनीति व विचार-धारा का संकट है। पूँजीवादी विचारक—जो इजारेदार पूँजीवाद के हितों को व्यक्त करते हैं, जीवन-मयार्थ द्वारा उभारे गए सवालों का जवाब देने में अममर्ष हैं। वे ऐसे विचार आगे लाने में अममर्ष हैं जो मेहनतकशों का मन जीन सकें। बढ़ते हुए वर्ग-संघर्ष का सामना करने के लिए, कुछ देशों में वित्तीय अत्यन्त कठोर राजनीतिक प्रतिक्रियावाद का सहारा नेता है, वह पूँजीवादी-जनवादी स्वतंत्रताओं को समाप्त करके, तानाशाही फ्रांसिस्ट अर्ध-फ्रांसिस्ट शासनों को स्थापना कर देता है।

पूँजीवादी आम-संकट की ये सभी विशेषताएँ सार-रूप में एक ही प्रक्रिया के विभिन्न रूप हैं। ये आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं। पूँजीवाद के आम-संकट की मूलभूत अभिव्यक्तियों का वैज्ञानिक विश्लेषण आधुनिक युग—जो भूमंडलीय स्तर पर पूँजीवादी से समाजवाद और साम्यवाद की ओर क्रांतिकारी संक्रमण का युग है—की अंतर्वस्तु का अधिक गहरा ज्ञान पाने में सहायक होता है।

पूँजीवाद के आम-संकट की अवस्थाएँ—पूँजीवाद के आम-संकट के विकास। विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं और हर अवस्था के अपने विशेष सक्षण होते हैं।

के आम-संकट की वर्तमान तीसरी अवस्था के प्रमुख लक्षणों का निर्धारण करता है।

तीसरी अवस्था का एक अन्य प्रमुख लक्षण राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों में शक्तिशाली नये उभार के कारण उपनिवेशी व्यवस्था का पूर्ण विखंडन है।

तीसरी अवस्था की एक विशिष्टता यह है कि इसका जन्म महायुद्ध के कारण नहीं हुआ है, बल्कि दो व्यवस्थाओं के बीच सह-अस्तित्व और आर्थिक-प्रतियोगिता के फलस्वरूप हुआ है। यह तथ्य पूंजीवादी सिद्धांतकारों द्वारा रचित इस सिद्ध को खंडित कर देता है कि मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद का विनाश युद्ध के द्वारा होगा और इसलिए मार्क्सवादी-लेनिनवादी युद्ध में रुचि रखते हैं। पूंजीवाद का पतन इसके भीतरी परस्पर प्रतिकूल अंतर्विरोधों के कारण होगा, इसलिए समाजवाद तब ही विजयी हो सकता है जब दो व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की स्थिति हो।

आठवें दशक के आरंभ में सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के प्रयत्न से अंतर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य की पक्षधर प्रवृत्तियाँ निरंतर मजबूर हुईं। उन वर्षों की विशेषताएँ थीं—समाजवादी समुदाय की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में दृढ़ता, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की सफलता और तनाव-शैथिल्य का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रभावी प्रवृत्ति बन जाना। सोवियत संघ व अन्य समाजवादी देशों की समन्वित विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में सामान्य स्थिति लाने के लिए शान्तिकामी शक्तियों का संघर्ष सफल हुआ।

किन्तु 1980 के दशक के आरंभ में साम्राज्यवाद व प्रतिक्रियावाद की शक्तियाँ अधिक सक्रिय होने लगीं। वे स्वतंत्र देशों तथा जन-समूहों को बर्षित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे शास्त्र-दौड़ को बढ़ा रहे हैं और अन्य देशों के घरेलू मामलों में सूत्रे तीर से हस्तक्षेप कर रहे हैं।

विश्व के जनगणों को यह अवश्य समझना चाहिए कि परमाणु-युद्ध के रण्य भीर परिणाम होंगे। आज का अति-आवश्यक कार्य शांति की रक्षा है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस में प्रस्तुत केंद्रीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया था—“शांति की रक्षा करते हुए हम केवल आज जीवित मनुष्यों और अपने बेटे-पुत्रों की रक्षा के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, हम दुर्बलों भावी पीढ़ियों की खुशियों के लिए भी काम कर रहे हैं।”¹ रिपोर्ट में इस दावे के झूठ को प्रबल किया गया है कि सोवियत संघ अफ्रीका से और वारसा-मध्य के देश नाटो-देशों के ऊपर सैनिक-भेद्यता वाले को कोशिश कर रहे हैं। “हमने दूतारे पक्ष पर सैनिक-भेद्यता नहीं की है और न हम ऐसा चाहते हैं। यह हमारी नीति नहीं है, लेकिन इस

1. 'परमाणु और शांति', सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस, कम्स. 23 दिसम्बर—3 मार्च, 1981, पृ. 40।

अपने ऊपर ऐसी श्रेष्ठता पाने की अनुमति भी नहीं देंगे। इस तरह के प्रयत्न और हमसे 'शक्ति की स्थिति' से बातचीत करने की कोशिश पूरी तरह व्यर्थ होगी।"¹ सोवियत विदेश नीति की मुख्य दिशा सदैव युद्ध के खतरे को कम करना और— शस्त्र दौड़ पर रोक लगाना रही है।

1. दस्तावेज और प्रस्ताव—सोवियत राष्ट्र की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस, मास्को, 23 फरवरी-3 मार्च, 1981, पृ० 25-30।

के भाव-मंचट की वर्तमान सीमरी अवस्था के प्रमुख सत्यों का निर्धारण करता है।

सीमरी अवस्था का एक अन्य प्रमुख सतत राष्ट्रीय मुक्ति सत्यों के शक्तिशाली नये उभा के कारण उत्तमवर्गी अवस्था का पूर्ण विघटन है।

सीमरी अवस्था की एक विशेषता यह है कि इसका जन्म महायुद्ध के उत्तर नहीं हुआ है, बल्कि दो अवस्थाओं के बीच सह-अस्तित्व और अतिरिक्त-प्रतिरोध के फलस्वरूप हुआ है। यह तथ्य पूँजीवादी मिजाजकारों द्वारा रचित इन सिद्ध को ग्रहण कर देना है कि मार्क्सवाद के अनुसार पूँजीवाद का विनाश युद्ध के द्वारा होगा और इसलिए मार्क्सवादी-लेनिनवादी युद्ध में रुचि रखते हैं। पूँजीवाद का पतन इसके भीतरी परस्पर प्रतिकूल अन्तर्विरोधों के कारण होगा, इसलिए समाजवाद तब ही विजयी हो सकता है जब दो अवस्थाओं के बीच शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की स्थिति हो।

आठवें दशक के आरंभ में सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के प्रत्यक्ष से अंतर्राष्ट्रीय तनाव-सौमिल्य की पृथग् प्रवृत्तियाँ निरंतर मजबूर हुईं। उन सत्यों की विशेषताएँ थीं—समाजवादी समुदाय की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में दुर्बला, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की सफलता और तनाव-सौमिल्य का अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की प्रभावी प्रवृत्ति बन जाना। सोवियत संघ व अन्य समाजवादी देशों की समन्वित विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में सामान्य स्थिति साने के लिए शक्तिशाली शक्तियों का संघर्ष सफल हुआ।

किन्तु 1980 के दशक के आरंभ में साम्राज्यवाद व प्रतिक्रियावाद की शक्तियाँ अधिक सक्रिय होने लगी। वे स्वतंत्र देशों तथा जन-समूहों को बर्षित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे शस्त्र-दौड़ को बढ़ा रहे हैं और अन्य देशों के बलु मामलों में खुले तौर से हस्तक्षेप कर रहे हैं।

विश्व के जनसत्यों को यह अवश्य समझना चाहिए कि परमाणु-युद्ध के क्या गंभीर परिणाम होंगे। आज का अति-आवश्यक कार्य शांति की रक्षा है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस में प्रस्तुत केंद्रीय समिति की रपट में कहा गया था—“शांति की रक्षा करते हुए हम केवल आज जीवित मनुष्यों और अपने बेटे-प्योती की रक्षा के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, हम दुर्बलों भावी पीढ़ियों की खुशी के लिए भी काम कर रहे हैं।”¹ रपट में इस दावे के शूट को प्रकट किया गया है कि सोवियत संघ अमरीका से और बारसा-संधि के देश नाटो-देशों के उत्तर सैनिक-श्रेष्ठता पाने की कोशिश कर रहे हैं। “हमने दूसरे पक्ष पर सैनिक-श्रेष्ठता नहीं चाही है और न हम ऐसा चाहते हैं। यह हमारी नीति नहीं है, लेकिन हम

1. 'शस्तावेज और प्रस्ताव', सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस, मस्को, 23 फरवरी—3 मार्च, 1981, पृ. 40।

के आम-संकट की वर्तमान तीसरी अवस्था के प्रमुख लक्षणों का निर्धारण करता है।

तीसरी अवस्था का एक अन्य प्रमुख लक्षण राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों में शक्तिशाली नये उभार के कारण उपनिवेशी व्यवस्था का पूर्ण विखंडन है।

तीसरी अवस्था की एक विशिष्टता यह है कि इसका जन्म महायुद्ध के कारण नहीं हुआ है, बल्कि दो व्यवस्थाओं के बीच सह-अस्तित्व और आर्थिक-प्रतियोगिता के फलस्वरूप हुआ है। यह तथ्य पूंजीवादी सिद्धांतकारों द्वारा रचित इस सिद्धांत को खंडित कर देता है कि मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद का विनाश युद्ध के द्वारा होगा और इसलिए मार्क्सवाद-लेनिनवादी युद्ध में रुचि रखते हैं। पूंजीवाद का पतन इसके भीतरी परस्पर प्रतिकूल अंतर्विरोधों के कारण होगा, इसलिए समाजवाद तब ही विजयी हो सकता है जब दो व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की स्थिति हो।

आठवें दशक के आरंभ में सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के प्रयत्न से अंतर्राष्ट्रीय तनाव-शीथिल्य की पक्षधर प्रवृत्तियाँ निरंतर मजबूर हुईं। उन वर्षों की विशेषताएँ थी—समाजवादी समुदाय की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में दुर्गा, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की सफलता और तनाव-शीथिल्य का अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की प्रभावी प्रवृत्ति बन जाना। सोवियत संघ व अन्य समाजवादी देशों की समन्वित विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में सामान्य स्थिति लाने के लिए शांतिवादी कर्तव्यों का संघर्ष सफल हुआ।

विन्तु 1980 के दशक के आरंभ में साम्राज्यवाद व प्रतिक्रियावाद की शक्तियाँ अधिक सक्रिय होने लगीं। वे स्वतंत्र देशों तथा जन-मजदूरों को बर्बर करने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे शस्त्र-दौड़ को बढ़ा रहे हैं और अन्य देशों के सोवियत मामलों में शूने तौर से हस्तक्षेप कर रहे हैं।

विश्व के जनघणों को यह अवश्य समझना चाहिए कि परमाणु-युद्ध के क्या खतरा परिणाम होंगे। आज का अति-आवश्यक कार्य शांति की रक्षा है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस में प्रसन्न केंद्रीय समिति की राय के बजाए कहा गया था—“शांति की रक्षा करते हुए हम केवल आज जीवन मनुष्यों को बचाने बेटे-सोने की रक्षा के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं, हम दुश्मनों वाली शक्तियों की शक्ति के लिए भी काम कर रहे हैं।” राय में इस दावे के झूठ को प्रकट किया जा रहा है कि सोवियत संघ अमेरिका से और वारसा-अधि के देश नाटो-देशों के डार-हेंड-खेप्टना जाने की कोशिश कर रहे हैं। “हमने दूसरे पक्ष पर हीन-खेप्टना और न हमें मरना चाहते हैं। यह हमारी नीति नहीं है, लेकिन हम

अपने ऊपर ऐसी श्रेष्ठता पाने की अनुमति भी नहीं देंगे। इस तरह के प्रयत्न और हमसे 'शक्ति की स्थिति' से आतपीत करने की कोशिश पूरी तरह व्यर्थ होगी।" सोवियत विदेश नीति की मुख्य दिशा सदैव युद्ध के खतरे को कम करना और— शस्त्र दौड़ पर रोक लगाना रही है।

करते हैं : धातु-वस्तुओं के उत्पादन का 80-95 प्रतिशत भाग प्रोदमेत सिन्डीकेट के हाथों में संकेन्द्रित था, कोयला-उद्योग पर पूरी तरह प्रोदुमोन सिन्डीकेट का आधिपत्य था, इक्षिण रुस के खनिज-सोह उत्पादन के 80 प्रतिशत भाग का नियन्त्रण प्रोदुमेट सिन्डीकेट करता था, और देश के तांबा उत्पादन का 75 प्रतिशत भाग मेद सिन्डीकेट द्वारा नियंत्रित था। उच्च-स्तर का यह इजारीकरण रुस की अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी स्पष्ट था। इसके अलावा रुस के इजारेदार पूंजीवाद में राज्य-इजारेदार पूंजीवाद के रूप में विकसित होने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती थी। इस प्रकार रुस में उत्पादन का उच्च-स्तरीय समाजीकरण हो गया था जो समाजवादी क्रान्ति के लिए वस्तुनिष्ठ परिस्थितियाँ प्रदान करता था।

इन वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों के अलावा आवश्यक आग्निष्ठ परिस्थितियाँ भी परिपक्व हो गयी थी—मजदूर और विश्व के एक सर्वाधिक जातिकारी मजदूर वर्ग का उदय हो चुका था। रुस में पूंजीवाद के विकास की लगभग आधी शताब्दी में औद्योगिक मजदूर-वर्ग की संख्या में 300 प्रतिशत वृद्धि हुई थी और शताब्दी के आरंभ में इनमें से आधे से ज्यादा बड़े उद्योगों में संकेन्द्रित थे, जहाँ मजदूरों ने उच्चतम स्तर की राजनैतिक कार्यवाही की। रुसी मजदूर वर्ग सभी बर्ष-समयों में फौसारी हुआ था और मनीजमन उच्च-स्तर पर संगठित व राजनैतिक रूप में बहुत बेगन था। यह सभी प्रकार के शोषण व उत्पीड़न का बटूर दुश्मन था। क्रान्ति और शांति में रुसी मजदूर वर्ग के बहुत से शांति-विरोध रूप से मेटनका किसान—ये।

इस प्रकार अकतूबर क्रान्ति की विजय रुस के समस्त सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रगति के द्वारा निश्चित हुई थी। क्रान्ति की विजय बीसवीं शताब्दी की प्रमुख घटना थी। यह ऐसी घटना थी जिसने समस्त विश्व के विकास के मार्ग में परिवर्तन निश्चित कर दिया। समाजवादी अकतूबर क्रान्ति इजारेदार पूंजीवाद के अन्तर्गत बर्ष-समय और सामाजिक विकास का स्वाभाविक परिणाम थी। इसकी विजय में विश्व के प्रथम समाजवादी राज्य की जन्म दिया। विश्व का सबसे बड़ा देश—जो सतार में जनसंख्या की दृष्टि में तीसरे और कुल औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि में पचासवें स्थान पर था—पूंजीवादी व्यवस्था में बाहर निष्कल आया। समाजवादी क्रान्ति ने रुस की जनता को साम्राज्यवादी दुष्ट में बाहर निकाल लिया और उन्हें विदेशी पूंजी द्वारा दास बनाये जाने के भय में बचा लिया।

विश्व-पूंजीवादी व्यवस्था में रुस का अचानक साम्राज्यवादी विदेशी पूंजी के हितों पर भारी आघात था। अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद के श्रेष्ठ व सफल होने के साथ औद्योगिक उत्पादन का एक महत्वपूर्ण बाजार और पूंजी-विकसित का क्षेत्र भी खो दिया। 1914 में रुस की मजदूर संख्या 47 प्रतिशत पर विदेशी पूंजी का निर्यात था। यह महत्वपूर्ण वर्ग के लक्ष्य 60 प्रतिशत, लेन-उत्प्रेष के

और निर्णयों से अधिक बलशाली एक और शक्ति है। यह शक्ति विश्व के आम आर्थिक सवध हैं जो उन्हें हमसे संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर करते हैं।”¹ समाजवादी व पूंजीवादी राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, उत्पादक-शक्तियों के विकास व ऐतिहासिक रूप से रचित धर्म के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन के कारण निर्मित वस्तुनिष्ठ आवश्यकता के रूप में उत्पन्न होता है।

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का लेनिनवादी सिद्धांत, देशों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक उपाय के रूप में युद्ध की अस्वीकृति की सबसे पहले मांग करता है। विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले देशों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की पूर्वपिछाएँ हैं—प्रत्येक देश (छोटे और बड़े दोनों) की क्षेत्रीय अर्धडता, समानता व सार्वभौमिकता के सिद्धांत की परस्पर स्वीकृति व उसकी पारिपालना और अन्य जनगणों के मामलों में अहस्तक्षेप। इसमें, सब राष्ट्रों द्वारा अपने लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार का सम्मान और धनमुल्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का वातचीत द्वारा समाधान तथा इसके साथ पूर्ण समानता व परस्पर लाभ के आधार पर आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग का विकास भी शामिल है।

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति, जिसका समाजवादी देशों द्वारा पालन किया जा रहा है, उनके अपने हितों को ही प्रकट नहीं करती है बल्कि संपूर्ण रूप में मानव-जाति के हितों को प्रकट करती है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व समाजवादी-व्यवस्था की आर्थिक शक्ति में विकास के लिए अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का निर्माण करता है, मजदूर वर्ग के सधर्ष की दशाओं में सुधार करता है और उत्पीडित जनगणों के लिए उनके अपने राष्ट्रीय मुक्ति-सधर्ष की समस्याओं से निपटने के कार्य को आसान बनाता है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि व युद्ध की भाग को भड़काकर साम्राज्यवादियों द्वारा अपने आंतरिक अतिविरोधियों पर क्रावू पाने के प्रयत्नों को रोकता है।

इस नीति का अर्थ दो विरोधी विश्व-व्यवस्थाओं के बीच विरोध की समाप्ति नहीं है। पूंजीपति व सर्वहारा तथा समाजवाद व साम्राज्यवाद के बीच सधर्ष जारी रहेगा। साम्राज्यवादी युद्धों के खतरे के विरुद्ध शांति के लिए सधर्ष इस सधर्ष का अनिवार्य भाग है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जीवन के सभी क्षेत्रों—अर्थव्यवस्था, राजनीति, विचारधारा व संस्कृति—में समाजवाद व पूंजीवाद के बीच द्वंद्व का सर्वाधिक तर्क-संगत और वांछनीय रूप है।

दो व्यवस्थाओं के बीच मुकाबले में आर्थिक-प्रतियोगिता का केन्द्रीय स्थान

1. बी० आई० लेनिन, 'शोशितों की नयी अद्विज शक्ति कायेत, दिसम्बर 23-28, 1921', सकलित रचनाएँ, भाग 33, पृ० 155।

है। काफ़ी पहले मई 1921 में लेनिन ने कहा था—“अब हम अपनी आर्थिक नीति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रांति पर अपने मुख्य प्रभाव का प्रयोग कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सघर्ष अब विश्वव्यापी हो गया है। यदि हम इस समस्या को सुलझा लेंगे, तो निश्चित व अंतिम रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत जाएँगे।”

दो व्यवस्थाओं के बीच आर्थिक प्रतियोगिता से यह प्रकट होता है कि कौन उत्पादक-शक्तियों का अधिक तेज़ी से विकास कर सकता है। विकास-दर, प्रति-व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, धम उत्पादकता, वैज्ञानिक-तकनीकी विकास का स्तर और सांस्कृतिक स्तर व जीवन-स्तर इस आर्थिक प्रतियोगिता के मुख्य संदर्भक हैं।

इस आर्थिक प्रतियोगिता की शुरुआत में समाजवादी भारी अमुविषा की स्थिति में था। पहली समाजवादी क्रांति अपेक्षाकृत पिछड़े देश में विजयी हुई थी। क्रांतिपूर्ण रूस में विश्व के औद्योगिक उत्पादन के तीन प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक भाग उत्पादित होता था, उसका कुल औद्योगिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्पादन का आठवाँ हिस्सा था। विदेशी हस्तक्षेप व गृहयुद्ध के कारण यह अंतर और अधिक बढ गया जिससे देश में भूख और आर्थिक-अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी। 1920 में सोवियत रूस के भारी उद्योग 1913 की तुलना में सातवें भाग का उत्पादन कर रहे थे। इस्पात का उत्पादन 22 गुना कम हो गया था, विद्युत-ऊर्जा के उत्पादन में रूस विश्व में आठवें से अठारहवें स्थान पर उतर गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सौवें भाग से भी कम उत्पादन कर रहा था। लेकिन बाद में सोवियत संघ ने थोड़े समय में ही, समाजवादी औद्योगीकरण और कृषि के सामूहिकीकरण सहित आश्चर्यजनक आर्थिक सुधार किये। समाजवादी उत्पादन संबंधों की स्थापना ने उत्पादक-शक्तियों के विकास के लिए अब तक अज्ञात अवसर देश को प्रदान किये।

समाजवादी अर्थव्यवस्था के लाभ का प्रमुख लक्षण पूँजीवादी विश्व की तुलना में सोवियत संघ की तीव्र आर्थिक विकास-दरों में प्रकट होता है। 1913 व 1940 के बीच सोवियत संघ में औद्योगिक उत्पादन 670 प्रतिशत बढ़ा जबकि अमेरिका के लिए यह संख्या 110 प्रतिशत थी और अन्य पूँजीवादी देशों में इससे भी काफी कम थी। 1913 की तुलना में सोवियत संघ ने 1940 में 24 गुना अधिक ऊर्जा उत्पादन की जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी अवधि में 6.6 गुना बढ़ि हुई। इसी अवधि के लिए अन्य क्षेत्रों में तुलनात्मक उत्पादन-बृद्धि भी इस प्रकार थी—दमक 250 प्रतिशत व 35 प्रतिशत, इस्पात 330 प्रति-
83 प्रतिशत और सीमेंट 220 प्रतिशत व 42 प्रतिशत। 1940 में कुल

औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से मोवियत सघ विश्व में पाँचवें स्थान से दूसरे स्थान और यूरोप में चौथे स्थान से पहले स्थान पर आ गया था। विश्व के औद्योगिक उत्पादन में इसका भाग बढ़कर दस प्रतिशत हो गया था।

यह सब पूँजीवादी विश्व से आर्थिक प्रतियोगिता के आरम्भिक दो दशकों में (जब तक कि हिटलर की जर्मनी के विश्वासघातपूर्ण आक्रमण ने मोवियत सघ को पुनः देश की रक्षा व शत्रु के विनाश के लिए अपनी आर्थिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश नहीं कर दिया) समाजवाद की भारी विजय का सदर्शक है।

2. दो विरोधी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष और पूँजीवाद के आम-संकट का गहरा होना

दूसरा महायुद्ध इस युद्ध में भागीदार देशों के लिए भिन्न-भिन्न रूप में समाप्त हुआ। कुछ देश विजयियों में थे, कुछ अन्य पराजितों में। कुछ देश युद्ध में मजबूत होकर निकले, कुछ कमजोर हो गए। समग्र रूप में साम्राज्यवादी व्यवस्था के लिए युद्ध भारी पराजय सिद्ध हुआ। युद्ध पूँजीवाद को आम-संकट से बाहर निकालने में ही असफल नहीं रहा बल्कि उल्टे उसका परिणाम इस संकट को और अधिक उग्र बनाना रहा।

मोवियत जनगण की विजय और नाजी जर्मनी, फ्रांसिस्ट इटली व सैन्यवादी जापान की शूर समस्त विश्व के लिए ऐतिहासिक महत्त्व की कहानी थी। यूरोप और एशिया के बहुत से देशों में समाजवादी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं। समाजवाद एक देश की सीमा से बाहर निकलकर विश्व-व्यवस्था बन गया। इस में अक्षुब्ध समाजवादी क्रांति के बाद यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी।

विश्व-समाजवादी व्यवस्था की स्थापना ने एक नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों—पूर्ण समानता, राष्ट्रीयता-स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, आतुल्यपूर्ण सहयोग और परस्पर सहायता पर आधारित संबंधों की स्थापना की। ये संबंध दोनों प्रकार के हितों—समग्र विश्व-समाजवादी व्यवस्था के हित और वैयक्तिक समाजवादी राज्यों के राष्ट्रीय हितों को स्वीकार करते थे। समाजवादी व्यवस्था के भीतर ये संबंध समाजवादी देशों के एक समान सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक आधारों से और उनके सामुदायिक धर्म-हित व उद्देश्यों से उत्पन्न होते हैं।

दूसरे महायुद्ध के बाद जिन देशों ने समाजवादी राह स्वीकार की, वे पहले साम्राज्यवादी शोषण के शिकार थे। युद्ध से पहले पोलैंड की औद्योगिक जमापूँजी के दो-तिहाई से अधिक भाग और बुल्गेरिया की आधी से अधिक व हंगरी की एक-तिहाई संयुक्त-स्टाक पूँजी पर विदेशियों का अधिकार था। विदेशी इजारेदार हस्तान्तरण की इस औद्योगिक पूँजी के लगभग 50 प्रतिशत भाग पर नियंत्रण

रखने थे। साम्राज्यवादी देशों के इजारेदार पूँजीपति इन देशों की राष्ट्रीय भाषा का एक बड़ा हिस्सा अपनी तिजोरियों में भरने के लिए बाहर ले जाते थे।

केन्द्रीय व दक्षिणी पूर्वी यूरोप के अनेक देशों को पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था में प्रस्थान, इन देशों में विदेशी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण और विदेशी-व्यापार पर राज्य के एकाधिकार की स्थापना ने इन देशों के जनगण को विदेशी-अधीनता से बचा लिया। जब एशिया के अनेक देशों ने भी समाजवादी विचार का रास्ता चुन लिया तो साम्राज्यवादी इजारेदारियों को गंभीर आर्थिक नुकसान हुआ। यूरोप में समाजवादी क्रांति की विजय साम्राज्यवाद को एक और नया आधार था। पूँजीवादी शोषण के क्षेत्र में और अधिक कमी से विरव-पूँजीवाद आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, पूँजीवादी व्यवस्था में अस्थिरता बढ़ी और साम्राज्यवादी देशों के बीच तथा उन देशों के भीतर भी अंतर्निहित (मौजूद) अंतर्विरोधों में वृद्धि हुई।

आर्थिक प्रतियोगिता के दौरान समाजवाद ने यह दिशा दिया है कि अहाँ तक बढ़ने-ने आर्थिक मंदियों का सवाल है, यह पूँजीवादी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ व्यवस्था है (देखें, सारणी-1)। समाजवादी उत्पादन की प्रगति के अनेक कारण हैं जिनमें वैज्ञानिक-तकनीकी प्रगति के फलों का प्रयोग भी शामिल है। उपचार विकास-दर अंतिम रूप में आर्थिक प्रतियोगिता के परिणामों को निर्धारित करती है। वे यह बताती हैं कि कौन-सी व्यवस्था जनगणना की रचनात्मक ऊर्जा व जनपन द्वारा निर्मित उत्पादन साधनों का आर्थिक तर्कमूल रूप में उपयोग कर सकती है और अल्प प्रभावों नतीके से सामाजिक उत्पादन का संगठन कर सकती है।

सारणी-1 के अंकड़े यह बताने हैं कि समाजवादी देशों की औसत वार्षिक विकास-दर पूँजीवादी देशों की तुलना में लगभग दुगनी रही है। 1950 के अंकड़ों की तुलना में 1979 में समाजवादी देशों में औद्योगिक उत्पादन 14 गुना वार्षिक वा वार्षिक विकास पूँजीवादी देशों में चार गुना था। 1979 में समाजवादी देशों में 1937 के अंकड़ों की तुलना में औद्योगिक उत्पादन 24 गुना वार्षिक वा वार्षिक इनके अर्थ में पूँजीवादी देशों में औद्योगिक उत्पादन 6.25 गुना ही था। दूसरी ओर यदि हम समूह समाजवादी विकास के उत्पादन की तुलना 1937 में समाजवादी देशों (अर्थात् सोवियत संघ और मंगोलिया) के उत्पादन से करें तो यह वृद्धि 46 गुना होगी जबकि पूँजीवादी देशों में वृद्धि 5.6 गुना रही। इस कारण 1950 और 1969 के बीच विश्व के औद्योगिक उत्पादन में समाजवादी देशों का हिस्सा दुगुना हो गया। 1950 में यह लगभग 20 प्रतिशत था और 1973 में 47 प्रतिशत में वृद्धि। इसके साथ समाजवादी देशों का औद्योगिक उत्पादन विश्व पूँजीवादी देशों के औद्योगिक उत्पादन के 75 प्रतिशत में वृद्धि है।

सारणी-1
समाजवादी और अन्य देशों में औद्योगिक प्रगति
(1950 के प्रतिशत-अनुसार)

वर्ष	समस्त विश्व	समाजवादी देश	दोनों शामिल करते हुए		
			अन्य देश	औद्योगिक पूंजीवादी देश	विकासशील देश
1950	100	100	100	100	100
1955	147	191	135	132	156
1956	156	211	141	138	169
1957	164	234	145	142	183
1958	171	274	143	138	192
1959	192	327	159	155	208
1960	206	354	167	160	233
1965	285	501	227	218	329
1970	388	723	298	284	459
1979	623	14 गुना	421	391	747
औसत					
वार्षिक वृद्धि					
1951-79					
प्रतिशत में					
	6.5	9.5	5.1	4.8	7.2

9312

सोवियत संघ और अमरीका के बीच वार्षिक प्रतियोगिता का, दो विश्व-व्यवस्थाओं के बीच वार्षिक प्रतियोगिता में विशेष महत्व है। दोनों देशों के पास आश्चर्यजनक धार्मिक व तकनीकी साधन हैं। सोवियत संघ विश्व-समाजवादी व्यवस्था द्वारा उत्पादित भौतिक वस्तुओं के अत्यधिक मात्रा का उत्पादन करता है जबकि अमरीका विश्व के पूंजीवादी उत्पादन के लगभग 40 प्रतिशत का उत्पादन करता है।

महायुद्ध के बाद की लगभग सारी अवधि के दौरान यह बनाने के लिए जहाँ तक प्रमुख वार्षिक-अवधि के बीच औद्योगिक वृद्धि दरों का महत्व है, सोवियत संघ अमरीका में काफी आगे है (देखिए सारणी-2)।

सारणी-2

मद	सोवियत संघ	अमेरिका
राष्ट्रीय आय	7.6	3.5
औद्योगिक उत्पादन	8.9	4.3
कृषि	3.2	1.9
कुल माल-दुसर्दी	7.6	2.4
पूंजी-निवेश	8.4	3.1
औद्योगिक श्रम उत्पादकता	5.8	3.2

आज सोवियत संघ में केवल विकास-दर ही नहीं, बनेक क्षेत्रों में कुल उत्पादन भी अमेरिका की तुलना में अधिक है। उदाहरण के लिए 1979 में सोवियत संघ में कुछ प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन प्रतिशत अमेरिका की तुलना में इस प्रकार था—तेल (संचयित गैस सहित)—139; इस्पात—117; धरित्र-घाट—111, रेल के डीजल व बिजली के इंजन—175; सीमेन्ट—158; सूती वस्त्र—179, और ऊनी वस्त्र—456। सोवियत संघ अब तेल, इस्पात, धरित्र-घाट, सीमेन्ट, ऊनी वस्त्र और अन्य वस्तुओं के उत्पादन में विश्व का नेतृत्व करता है। इसने सोवियत संघ को प्रति व्यक्ति उत्पादन की दृष्टि से अमेरिका की तुलना में आने तक आर्थिक विछोड़ पर विजय पाने के लिए ठोस आधार भूमि प्राप्त होनी है।

सोवियत आर्थिक विकास अप्रत्याशी-दर विश्व-उत्पादन में उसके बड़े हुए भाग को सिद्ध करती है। 1979 में सोवियत संघ विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन का 20 प्रतिशत भाग उत्पादन करता था। चापीय वर्षों में विश्व के ऊर्जा, तेल, रैत, इस्पात और अग्रणी सेवाओं के कुल उत्पादन में सोवियत संघ का हिस्सा लगातार बढ़ता हो गया है।

विश्व-अर्थव्यवस्था में सोवियत संघ की स्थिति मजबूत होने के साथ सोवियत संघ की औद्योगिक उत्पादन के अनुपात में भी अग्रता है। अमेरिका की तुलना में सोवियत संघ का औद्योगिक उत्पादन 1913 में 12.5 प्रतिशत, 1950 में 39 प्रतिशत और 1977 में 80 प्रतिशत में अधिक था। 1909 और 1956 के बीच सोवियत संघ का कृषि उत्पादन औसत रूप से अमेरिका के उत्पादन के 45 प्रतिशत का 1971-79 में यह बढ़कर लगभग 85 प्रतिशत हो गया। 1979 में सोवियत संघ का औद्योगिक उत्पादन अमेरिका की तुलना में 67 प्रतिशत की दर से 1953 में 31 प्रतिशत की।

पिछले दशक में सोवियत संघ ने अपने औद्योगिक उत्पादन के परिमाण को दुगना कर लिया है। ऐसा करने के लिए ब्रिटेन को 25 वर्ष, पश्चिमी जर्मनी को 18 वर्ष, फ्रांस को 27 वर्ष और अमरीका को 16 वर्ष की जरूरत होती है।

पूंजीवाद के साथ आर्थिक प्रतियोगिता में समाजवाद की विजय की एक मुख्य शर्त उच्चतर श्रम उत्पादकता प्राप्त करना है। इस संवद में लेनिन ने लिखा है—
“पूंजीवाद पूरी तरह परास्त किया जा सकता है और एक नयी व काफी उच्चतर श्रम-उत्पादकता को प्राप्त करते हुए समाजवाद द्वारा पूरी तरह परास्त किया भी जाएगा।”

विश्व-समाजवादी व्यवस्था के देशों में श्रम-उत्पादकता की दरें विकसित पूंजीवादी देशों की तुलना में तेज गति से बढ़ रही हैं और दोनों के बीच का अंतर कम होता जा रहा है। 1951-79 के बीच सोवियत संघ में औद्योगिक श्रम-उत्पादकता की वार्षिक औसत वृद्धि 5.8 प्रतिशत थी जबकि अमरीका की वृद्धि-दर 4.2 प्रतिशत थी। (देखिए सारणी-2)

उत्पादन के कुल क्षेत्रों के महत्व के बावजूद आर्थिक विकास के स्तर का मुख्य संदर्शक भौतिक संपदा का प्रतिव्यक्ति उत्पादन है। यद्यपि समाजवादी देश अभी अधिकांश विकसित पूंजीवादी देशों के आर्थिक-विकास के स्तर तक नहीं पहुँच पाये हैं, लेकिन जीवन-स्तरों के अनेक संदर्शकों में वे विकसित पूंजीवादी देशों से अभी भी श्रेष्ठतर हैं। समाजवादी समुदाय के देशों में, जहाँ परजीवी उपभोग करनेवाला कोई शोषक-वर्ग नहीं है, राष्ट्रीय आय का उपयोग जनगण के कल्याण-कार्यों में सुधार व समाजवादी-उत्पादन के विस्तार के लिए किया जाता है। समाजवादी समुदाय के देशों में बेरोजगारी नहीं है और वहाँ लिंग, जाति अथवा राष्ट्रीयता के भेदभाव के बिना समान कार्य के लिए सबको समान वेतन मिलता है। समाज के सभी सदस्यों लिए निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा-सेवाओं की गारंटी है। सोवियत संघ ने संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, शोक-कल्याण आदि के अनेक क्षेत्रों में अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। उत्पादन-क्षमता के विस्तार ने समाजवादी देशों को जीवन-स्तरों के कुछ खास संदर्शकों में—जैसे प्रतिव्यक्ति वास्तविक आय, मूलभूत खाद्य-पदार्थों व औद्योगिक उत्पादों का प्रतिव्यक्ति औसत उपभोग—अधिकांश विकसित पूंजीवादी देशों से आगे निकल जाने में समर्थ बना दिया है। इसका कारण आर्थिक विकास की उच्च दरें और वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं का उपयोग है।

समाजवादी व पूंजीवादी व्यवस्थाएँ वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति के सुफलों के

1. बी० आई० लेनिन, 'एक महत्वपूर्ण भ्रमबाज, मोर्चा के पिछने का व कम्युनिस्ट युवाओं की व बहुरों की बोरता', संकलित रचनाएँ, भाग 29, पृ० 427 (अधेशों में)।

उपयोग की मूलतः भिन्न संभावनाओं को जन्म देती हैं। पूँजीपति वर्ग बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने व अधिकतम लाभ पाने के लिए इन उपलब्धियों का प्रयोग करने की कोशिश करता है। प्रमुख पूँजीवादी देशों में सैन्य-औद्योगिक-समूह सैनिक उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति की उपलब्धियों का अधिक-से-अधिक प्रयोग कर रहा है। इससे भीतिक-सामग्री, धम व वित्तीय संसाधनों का भारी अपव्यय हुआ है और अर्थव्यवस्था में बैधम्य की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इसके अलावा यह स्थिति मुद्रा-स्फीति को जन्म देती है व इन क्रांतिकारी उपलब्धियों के प्रसार को रोकती है।

पूँजीवादी विश्व में वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति वर्तमान सामाजिक-विरोधों के क्षेत्र को बढ़ाती है और नए विरोध उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, औद्योगिक-चक्र की चाहे कोई भी विगिष्ट अवस्था हो, स्वधासन बड़ी मात्रा में कार्बन-अवशोषण को अनावश्यक बनाकर कम कर रहा है और इस प्रकार बेरोजगारी में वृद्धि कर रहा है। वृष्टि का औद्योगीकरण व धम-उत्पादकता में तीव्र-वृद्धि स्थापित करने पर विगानों की बरबादी तथा कष्टदायक व विध्वंसक सामाजिक-भूरीकरण में बुरी हुई है।

विज्ञान और तकनीक के अनेक क्षेत्रों में समाजवादी देश विश्व का नेतृत्व करने हैं। उदाहरण के लिए, इसे अनगिना अनुसंधान में सोवियत उपलब्धियों, परमाणु-शक्ति के क्रांतिकारी उपयोग, जमीन-ऊर्जा केंद्र निर्माण में प्रवीणता, सभी दूरियों पर जलिन उपग्रह कोन्टेनर, ऊर्जा का सम्प्रेषण आदि में देखा जा सकता है। सोवियत संघ अंतरिक्ष उड़ान उमान हवाई की तकनीक में विश्व में पहले स्थान पर है और अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में औद्योगिक-उत्पत्तियों के समालन में इसके तकनीकी व आर्थिक परिणाम बरबरीदा की तुलना में उच्चतर हैं। समाजवादी देशों ने अपनी अर्थ-व्यवस्था में काम करने वाले कुशल कर्मियों की एक विज्ञान सेना तैयार करके वैज्ञानिक-तकनीकी क्रांति को और आगे विस्तार करने के लिए ठोस आघातिका की स्थिति कर ली है।

उत्पन्न क्रांति-कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे के प्रतिष्ठत का महत्त्व है। सोवियत संघ ने बरबरीदा की बरबरीदा कर ली है और उसने पश्चिमी यूरोप के विस्तारित देशों का 100 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र दिया है। पारम्परिक आर्थिक उत्पादन क्षमता के अन्तर्गत समाजवादी संरचना में क्षेत्र व विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे का क्षेत्र 100-200 प्रतिशत बढ़ गया है। समाजवादी देशों की उत्पादन क्षमता के वैज्ञानिक पूर्ण-अनुमानों के समानुपात क्षेत्र व विकास के क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है। इसमें समाजवादी देश अर्थव्यवस्था में अत्यधिक क्षेत्र व विज्ञान-उत्पत्ता के महत्त्व में समर्थ हो जाने हैं और उच्च-विकास के क्षेत्रों में समाजवादी संरचना में सुव्यवस्था का सर्वे।

परस्परिक आर्थिक सहायता परिपद् के सदस्य देशों के बीच आर्थिक वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने में 1971 का समाजवादी आर्थिक एकीकरण का व्यापक कार्यक्रम प्रमुख भूमिका अदा करेगा ।

वर्तमान समाजवाद की आर्थिक शक्ति में सुस्थिर वृद्धि, विश्व क्रांतिकारी प्रक्रिया को तीव्र करने व पूंजीवाद के आम-सकट को गहरा बनाने का एक प्रमुख कारक है । समाजवादी देशों में जीवन-स्तरो में सुस्थिर वृद्धि, दो सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच ऐतिहासिक विवाद में एक कायल करने वाला तर्क है ।

लेनिन ने अपने समय में ही बताया था कि विजयी समाजवाद आर्थिक-विकास में अपनी उपलब्धियों के द्वारा ही विश्व-क्राति के विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करेगा ।

साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था का संकट और पतन

साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था का संकट व पतन पूंजीवाद के आम-संकट का अनिवार्य भाग एवं एक प्रमुख लक्षण है। नए देश, जो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक समय के विशाल उपनिवेशी साम्राज्यों के खंडहरों के ऊपर प्रकट हुए हैं। विकासशील देशों में से कुछ ने विकास का गैर-पूंजीवादी रास्ता चुना है। इस प्रकार लेनिन का यह पूर्व अनुमान सच हो रहा है कि उपनिवेशी और पराधीन देशों के जनता-राष्ट्रीय मुक्ति के लिए संघर्ष आरंभ करने के बाद शोषक व्यवस्था की आधार-शिलाओं के विरुद्ध संघर्ष करने की ओर बढ़ेंगे। उपनिवेशी व्यवस्था का पतन साम्राज्यवाद के लिए एक नया शक्तिशाली आघात था और इसने उसकी राज-नीतिक, आर्थिक स्थितियों को भरपूर मात्रा में निर्वल किया। उपनिवेशी-व्यवस्था का संकट और पतन, विश्व के दो विरोधी सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं के विभाजन के बाद शुरू होने वाले पूंजीवाद के आम-संकट की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

1. उपनिवेशी व्यवस्था का पतन : पूंजीवाद के आम-संकट की एक अभिव्यक्ति

उपनिवेशी व्यवस्था का संकट उपनिवेशी विश्व में उस संघर्ष के तीव्र हो जाने को सूचित करता है जो उपनिवेशी व पराधीन साम्राज्यवाद के प्रभुत्व को पहले निर्वल बनाता है और फिर उपनिवेशी व्यवस्था के संकट के कारणों की जड़ इससे गहरे आंतरिक बन-

विरोधों में है, मुख्य रूप से साम्राज्यी देश के साम्राज्यवादी पूँजीपति वर्ग तथा पराधीन देशों के जनगण के बीच अतिविरोधों में तीव्र वृद्धि और साम्राज्यवाद के उपनिवेशी जुए की व्यवस्था तथा उपनिवेशों में उत्पादक-शक्तियों के बीच द्वंद्व की स्थिति में है। साम्राज्यवादी राज्यों द्वारा उपनिवेशी देशों का शोषण और जिन आर्थिक संबंधों को वे स्थापित करते हैं, वे सब उपनिवेशी विश्व में उत्पादक-शक्तियों के विकास को रोकते हैं। जिन जनगणों ने प्राचीनकाल से विश्व-सभ्यता में मूल्यवान भौतिक व आध्यात्मिक योगदान दिया है, साम्राज्यवाद के कारण अब वे स्वयं को सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन के चंगुल में फँसा पाते हैं और उनके प्रचुर रूप से समृद्ध प्राकृतिक ससाधन हिंसात्मक तरीकों से लूटे जाते हैं।

पराधीन देशों में उपनिवेशी संबंधों की व्यवस्था के विनाश और राष्ट्रीय मुक्ति क्रांतियों की सफलता के लिए वस्तुनिष्ठ ही नहीं, आत्मनिष्ठ स्थितियाँ भी परिपक्व हुईं। पूँजीवाद के विकास के साथ, राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग, राष्ट्रीय बुद्धिजीवी और मजदूर वर्ग का भी निर्माण हुआ। ये वे राजनैतिक शक्तियाँ थीं जो उपनिवेशी शासनों के विरुद्ध कार्य करने के लिए जनगणों को आंदोलित कर सकती थीं।

विदेशी इजारेदारों के कारखानों व बागानों के मजदूर भूखी मरने लायक ही मजदूरी पाते थे और उन्हें साम्राज्यी देश के मजदूर वर्ग को प्राप्त आर्थिक-राज-नैतिक अधिकारों में कुछ छोटे अधिकार ही दिये गये थे। स्थानीय राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के कारखानों को विदेशी उत्पादनों से प्रतियोगी सघर्ष में अत्यंत कठिन समय का सामना करना होता था। हमसे राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग में असन्तोष उत्पन्न हुआ। इसका अर्थवाद स्थानीय पूँजीपति वर्ग का वह हिस्सा था जो मेहनतकों के शोषण में विदेशी पूँजी की मदद करता था। इस समूह—तथाकथित दलाल पूँजीपति वर्ग—ने उपनिवेशी शासन का समर्थन किया।

उपनिवेशी व्यवस्था स्थानीय किसानों की शत्रु थी, जो उपनिवेशवादी और 'अग्ने' क्रांतियों से ही शोषित होते थे। इसी कारण किसान वर्ग ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघर्ष में सक्रिय भाग लिया। हमने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की व्यापक स्वरूप दिया क्योंकि पराधीन देशों की जनसंख्या में किसान ही सबसे बड़ा भाग है।

कुछ विकासशील देशों में सामुदायिक व्यवस्था के अस्तित्व अभी भी मजबूत है, उदाहरण के लिए अनेक अफ्रीकी देशों में किसानों द्वारा कृषि-कार्य का आधार सामुदायिक सम्पत्ति है। इस कारण वहाँ राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का नेतृत्व अग्रिक प्रजासत्ताक दलतों व सामाजिक समूहों—जैसे राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग, बुद्धिजीवी, छोटी पूँजी वाले शोष तथा सेना के प्रतिनिधियों—द्वारा किया जाता है और सभी साम्य-विरोधी व साम्राज्यवाद-विरोधी शक्तिवाला उनके चारों तरफ एक हो जाती है।

रूस में समाजवादी क्रांति की विजय उपनिवेशी जनगणों के सामने राष्ट्रीय व सामाजिक मुक्ति के लिए संघर्ष करने की एक अपील और उदाहरण थी। इस तथ्य ने कि सोवियत संघ में जातीय प्रश्न का समाधान कर लिया गया है, उपनिवेशी जनगणों को आत्ममुक्ति और उपनिवेशी शोषण के परिणामों पर विजय पाने का रास्ता दिखाया।

उपनिवेशी व पराधीन देशों में, विशेष रूप से पहले महायुद्ध के बाद, नवजात पूँजीवाद का उदय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को सक्रिय बनाने में सहायक हुआ। युद्ध के दिनों में साम्राज्यीय देश व उपनिवेशों के बीच आर्थिक संबंध या तो विच्छिन्न हो गये या कम हो गये। और औद्योगिक उत्पादों का निर्यात तेजी से गिरा। इसने उपनिवेशों में उद्योग के विकास तथा स्थानीय राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग व सर्वहारा वर्ग के विकास को प्रोत्साहित किया। जैसे ही इसने साम्राज्यवाद को समग्र रूप में कमजोर किया, युद्ध ने उसे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के प्रहारों के सामने अधिक नाबूत बना दिया।

रूस की समाजवादी अक्तूबर क्रांति से प्रभावित होकर चीन, भारत और हिन्देशिया में राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों की एक लहर आयी। तुर्की में राष्ट्रीय क्रांति हुई, मोरक्को व अफ़ग़ानिस्तान में मुक्ति युद्ध हुए और हिन्द चीन, त्रिनिदीन व कोरिया में जन-विद्रोह हुए। 1921 में मंगोलिया में लोक-क्रांति हुई जिसने सोवियत संघ की प्रत्यक्ष सहायता से समाजवादी समाज का निर्माण आरंभ किया। 1922 में तुर्की में गणतंत्र की घोषणा हुई। मिस्र के जनगण ने भी अपनी स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता के लिए बहादुरी से संघर्ष किया और 1922 में ब्रिटेन मिस्र को आंशिक स्वतंत्रता देने के लिए विवश हुआ। इसी समय ईरान ने भी क्रांति स्वतंत्रता प्राप्त की। उपनिवेशी जुए के विरुद्ध संघर्ष में पराधीन राष्ट्र विरुद्ध पहले समाजवादी राज्य के अनुभव व समर्थन पर भरोसा करने में समर्थ थे।

लेकिन पूँजीवाद के आम-संकट के आरंभिक युग में उपनिवेशी व पराधीन देशों में क्रांतिकारी कार्य सदैव वास्तविक स्वतंत्रता की ओर नहीं बढ़े। पर साम्राज्यवादी शक्तियों ने कुछ देशों, जैसे ईरान, सीबिया एवं अन्य, को आंशिक स्वतंत्रता दी, फिर भी वे उन्हें साम्राज्यवाद पर निर्भर बनाये रखने में सफल रहे। 1920 व 1930 के दशक में भी साम्राज्यवादी शक्तियाँ अधिकांश उपनिवेशी पराधीन देशों में राजनैतिक प्रभुत्व बनाये रखने में सफल रहीं। मजदूर वर्ग को मापेस निबंधनता, किसानों की कारंवाइयों की असंगठित प्रवृत्ति और संयुक्त राष्ट्रीय साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा, जो देश-विशेष की सारी राजनैतिक शक्तियों को सभटिन कर सकता था, के अभाव के कारण ही वे ऐसा करने में समर्थ नहीं हुए।

मेकिन, ऐसा होने पर भी, इस अवधि के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का महत्व अत्यंत अधिक है। जो उपनिवेशी व पराधीन देश पहले साम्राज्यवाद की शरणा

आरक्षित शक्ति थे, वे अब तनावपूर्ण राजनैतिक सघर्षों के क्षेत्र बन गये। इन उपनिवेशी देशों में राष्ट्रीय मुक्ति-सघर्ष के विकास ने यह दिखाया कि इन देशों के छूले शोषण का युग अब अटल रूप में भूतकाल की चीड़ हो गया है और मुक्ति-क्रांतियों का युग—कभी उत्पीड़ित रहे जनगणों के जागरण व विश्व-क्रांतिकारी आंदोलन में उनके शामिल होने का युग—शुरू हो गया है।

दूसरे महायुद्ध के दौरान और युद्ध बाद के आरम्भिक दशकों में अर्थात् पूँजीवाद के आम-संकट की दूसरी अवस्था में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन गुणात्मक रूप से एक नये स्तर तक विकसित हुए। इसमें साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था की इमारत भरभराकर गिर पड़ी। साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था के संकट के बाद उसके पतन आया जो सार रूप में ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा उपनिवेशी व पराधीन देशों के उत्पीड़न पर आधारित आर्थिक-राजनैतिक संबंधों का अंत हुआ और भूतपूर्व उपनिवेशों में नये स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई।

दूसरे महायुद्ध के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों को आगे बढ़ाने वाली धरलू व अंतर्राष्ट्रीय, दोनों ही परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन हुए। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के निरन्तर विकास के लिए यूरोप में फासीवाद पर विजय और एशिया में सैन्यवादी जापान की हार बहुत महत्वपूर्ण थी। सोवियत संघ की विजय में यह दिखता दिया कि समाजवाद की भूमि अजेय है और वह साम्राज्यवाद-विरोधी विश्व-संघर्ष का केन्द्रीय स्तंभ है। इसके साथ हिटलरी जर्मनी व सैन्यवादी जापान—अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद की सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ—जो सबसे अधिक शर्मनाक विस्म के जातिवाद तथा राष्ट्रीय उत्पीड़न का समर्थन करती थी—की हार समकालीन साम्राज्यवाद की संपूर्ण विचारधारा की गंभीर पराजय व मुक्ति के विचारों की विजय को प्रकट करती थी। यूरोप व एशिया के अनेक देशों में समाजवादी क्रांति की विजय तथा उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न विश्व-समाजवादी व्यवस्था राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के और आगे विकास के लिए निर्णायक महत्व की थी।

पूँजीवाद के आम-संकट की पहली अवस्था में सोवियत संघ उपनिवेशी जनगण को मुख्य रूप से नैतिक व राजनैतिक समर्थन ही दे सका था। नयी स्थिति में, केवल सोवियत संघ ही नहीं, संपूर्ण विश्व-समाजवादी व्यवस्था साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में उपनिवेशी विश्व को सहायता दे रही है। यह सहायता नैतिक-व राजनैतिक समर्थन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक व सैनिक सहायता भी शामिल है।

दूसरे महायुद्ध के तुरंत बाद एशिया उपनिवेशी शासनों के विरुद्ध संघर्ष का मुख्य क्षेत्र बन गया। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के क्षेत्रों के आरम्भिक विकास में

वाद भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता देने के लिए याध्य हुआ। हिन्देशिया बर्मा, श्रीलंका का गणराज्य और अन्य एशियाई देशों ने भी उपनिवेशी शासनों को उखाड़ दिया। 1944 व 1954 के बीच 15 एशियाई देशों ने, जो सभी साम्राज्यवादी शक्तियों के भूतपूर्व उपनिवेश थे, स्वतंत्रता प्राप्त की। अफ्रीका में भी उपनिवेशी व्यवस्था का पतन निकट दिखाई दे रहा था। अनेक देशों ने जैसे मिस्र, सूडान, ट्यूनेशिया और मोरक्को ने स्वतंत्रता प्राप्त की। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा उपनिवेशी विश्व में राष्ट्रीय पुनर्जागरण की प्रक्रिया को बलपूर्वक रोकने के भूतपूर्व उपनिवेशी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के प्रयत्न असफल रहे।

पूँजीवाद के आम-संकट की आरंभिक तीसरी अवस्था, जो 1950 के दशक उत्तरार्ध में आरम्भ हुई, का मुख्य लक्षण साम्राज्यवाद का और अधिक निर्बल होना था। इसे उपनिवेशी व्यवस्था के निर्णायक पतन उपनिवेशों को पूर्ण राजनैतिक मुक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए विकासशील देशों के तीव्र संघर्षों ने देखा जा सकता है। एशिया में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चलता रहा—उस समय मध्य-पूर्व (पश्चिमी एशिया) उपनिवेश-विरोधी संघर्ष का मुख्य केंद्र हो गया था। अरब देशों के संघर्ष ने मध्य-पूर्व व अफ्रीका में साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरुद्ध समग्र संघर्ष पर सकारात्मक प्रभाव डाला। साम्राज्यवाद व इजरायल आक्रमण के विरुद्ध यह संघर्ष, स्वतंत्रता और समाजवाद की विश्वव्यापी शक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़ा करने वाले आम-संघर्ष का आनिष्ठ भाग था।

अफ्रीका में भी भारी परिवर्तन हुए। अकेले 1960 में 17 अफ्रीकी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और 1980 के दशक के आरम्भ में अफ्रीका में 50 से अधिक सार्वभौम देश हो गये थे। गिनी-बिसाऊ, मोजाम्बिक और अंगोला के जनगणतन्त्र संघटनों के बाद अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। देशभक्त क्रांतिकारी जनगणतन्त्र संघटनों—मोजाम्बिक की मुक्ति के लिए मोर्चा (फ्रीलिमो), केपवर्दे द्वीप व सिनेराले बिसाऊ के क्रांतिकारी दल और अंगोला की मुक्ति का लोकप्रिय आंदोलन (एम्पी० एल० ए०), जो उपनिवेशी जनगणों के मुक्ति-संघर्ष के हरावस दस्तक दे रहे हैं—के नेतृत्व में इन देशों के जनगणों ने पुर्तगाली साम्राज्यवाद पर भारी प्रहार किया। आतंक और हिंसा से अफ्रीकी देशभक्तों को कुचलने की पुर्तगाल की सलाहकार व केटानो की फ्रांसिस्ट सरकारों के प्रयत्न पूरी तरह असफल हुए। गिनी-बिसाऊ, मोजाम्बिक और अंगोला के जनगणों के सशस्त्र संघर्ष ने उपनिवेशवादियों को संन्य-क्षेत्र में ही पराजित नहीं किया, स्वयं पुर्तगाल में भी जनवादी आंदोलन को मजबूत करने में बहुत प्रोत्साहन व सहायता पहुँचायी। और अप्रैल 1974 के फ्रांसिस्ट तानाशाही के उच्छेदन को प्रोत्साहित किया। गिनी बिसाऊ, मोजाम्बिक और अंगोला के जनगणों के लम्बे सशस्त्र संघर्ष में सोवियत संघ ने उन्हें बड़ी सहायता

में नैतिक व भौतिक सहायता दी।

अफ्रीका में राष्ट्रीय मुक्ति की शक्तियों और उपनिवेशवाद के बीच ऐतिहासिक युद्ध ने महाद्वीप की सीमाओं का दूर तक अतिक्रमण किया। अफ्रीका में उपनिवेशी शासनों को समाप्त करने का संघर्ष, समस्त विश्व की प्रगतिशील व शांतिवादी शक्तियों के साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष का आगिक भाग हो गया है।

आगे प्रस्तुत आँकड़े, पूँजीवाद के आम-सकट की तीसरी अवस्था में साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था के बढ़ते पतन के सूचक हैं। युद्ध बाद के आरम्भिक दशक में एशिया व अफ्रीका के 14 देशों ने स्वयं को उपनिवेशी जुए से मुक्त किया, परवर्ती दशक में अफ्रीका व एशिया के 50 से अधिक देशों ने उनका अनुसरण किया।

साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष की लपटें पश्चिमी गोलार्ध में भी फैल गई हैं। वहाँ राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। अधिकांश सातवीं अमरीकी देशों ने 19वीं शताब्दी के आरंभ में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, किंतु वे साम्राज्यवादी शक्तियों पर आर्थिक निर्भरता की स्थिति में फँस गये। अब उनके जनगण अमरीकी तथा अन्य साम्राज्यवादी हज़ारेदारियों के विरुद्ध और असली राष्ट्रीय प्रभुसत्ता व आर्थिक आजादी प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। क्यूबा के बहादुर जनगण पश्चिमी गोलार्ध में समाजवादी क्रांति करने वाले पहले जनगण थे और क्यूबा की क्रांति असली राष्ट्रीय स्वतंत्रता व सामाजिक प्रगति के लिए संघर्ष में सारे सातवीं अमरीकी जनगण के लिए एक उदाहरण बन गयी। सत्तर के दशक की विशेषता थी—सातवीं अमरीकी जनगण द्वारा अपनी स्वतंत्रता, जनतंत्र व सामाजिक प्रगति को दृढ़ करने के लिए बढ़ी हुई भाषा में सशिव संघर्ष। उरण्वे की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के प्रथम सचिव रोडने एरिसमैडी ने बताया है—“क्यूबा की क्रांति द्वारा शुरू किये गये दशक के परिणाम दिखाने हैं कि अमरीका मुक्ति संघर्षों को सशिव गति में सदातार ऊपर खड़े मार्ग पर विवास करने में रोकने में असफल रहा है।”

बिसी में 1970 के राष्ट्रपति-चुनाव में अनेक प्रगतिशील दलों के गठबन्धन के उम्मीदवार सल्वेदोर एम्बेडी की विजय की लानीनी अमरीका में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। बिसी की लोकप्रिय एका की सरकार ने अपने तीन वर्ष के शासनकाल में अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया और विदेशी हज़ारेदारियों, विशेष रूप से अमरीकन हज़ारेदारियों की शक्तिशालियों पर रोक लगायी। विदेशी हज़ारेदारियों की खानें, बैंक व कारखाने सरकार द्वारा अधिकार में ले

राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन समकालीन विप्लव-क्रान्तिकारी प्रक्रिया का भागिक भाग बन गया है। नये मार्क्सवादी राज्यों के—जो उपनिवेशी साम्राज्यों के खड्डरों में उत्पन्न हुए हैं, जनगण साम्राज्यवाद की राजनैतिक, आर्थिक व मैनिफेस्ट-सामरिक स्थितियों पर शक्तिशाली प्रहार कर रहे हैं। उपनिवेशी व्यवस्था का पतन और-आर्थिक शोषण, श्रुते बम प्रयोग और सूटमार (जो उपनिवेशी युग की विशेषताएँ थी) के अंत को सूचित करता है। अंतर्राष्ट्रीय इजारेदार पूँजी अब और अधिक अपने मूलपूर्व उपनिवेशों की धर्मशक्ति व भौतिक साधनों का इच्छानुसार प्रयोग नहीं कर सकती है। उपनिवेशी दामता की व्यवस्था के पतन का परिणाम भूमंडलीय शक्तियों के सहसंबंध में भारी परिवर्तन हुआ है। वस्तुनिष्ठ रूप में, राजनैतिक रूप से स्वाधीन राज्य साम्राज्यवाद-विरोधी व क्रान्तिकारी शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं। नये मार्क्सवादी राज्यों का भारी बहुमत साम्राज्यवादी शक्ति-शुले में शामिल नहीं है। वे सटस्थता की नीति का पालन करते हैं और एक नये विश्व-युद्ध को रोकने के समर्थक हैं। राजनैतिक स्वतंत्रता मूलपूर्व उपनिवेशों के अंतर्गत के लिए आर्थिक आराम-निर्भरता, उच्चतर जीवन-स्तर और अपनी भावुकियों के पुनरुत्थान व विकास के लिए राह खोलती है।

2. नव-उपनिवेशवाद

जब उपनिवेशों में स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तो साम्राज्यवादी शक्तियों ने उन्हें आर्थिक व राजनैतिक बंधन में बनाये रखने के लिए नये तरीकों व रूपों का प्रयोग शुरू कर दिया। आधुनिक उपनिवेशवाद अर्थात् नव-उपनिवेशवाद विकासशील देशों में साम्राज्यवाद की स्थिति को बनाये रखने व मजबूत करने के लिए आर्थिक, राजनैतिक, विचारधारात्मक व अन्य उपायों की समग्र श्रृंखला है। उपनिवेशवाद मूलतः तीव्र आर्थिक दमन और सूटमार के तरीकों का प्रयोग करता था, नव-उपनिवेशवाद नयी ऐतिहासिक स्थितियों के अनुकूल अधिक सूक्ष्म तरीकों से अपने उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। किन्तु इसका अर्थ अपने दुहरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष दबाव (जिसमें विकासशील देशों के मामलों में शकस्य हस्तक्षेप भी शामिल है) का त्याग नहीं है। नव-उपनिवेशवाद के ये दोहरे उद्देश्य हैं—एक, विकासशील देशों में अपनी स्थिति को सुरक्षित रखना व उसका विस्तार करना और इजारेदारी शोषण को तीव्र करना; दो, जिन देशों ने स्वयं की उपनिवेशी व्यवस्था से मुक्त कर लिया है, उन्हें विकास के और-पूँजीवादी रास्ते को रोकना और उन्हें विश्व-पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के भीतर बनाये

... देशवाद का एक महत्वपूर्ण रूप है—विकासशील देशों की पूँजी (सहस्रता के बेस में) का निर्माण। इस 'सहायता' का अधिकतम भाग

साम्राज्यवाद की आक्रामक योजनाओं, सामरिक ज़रूरतों और विश्व-समाजवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में विकासशील देशों को अप्रमोर्चा के रूप में बदलने की कोशिशों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साम्राज्यवादी, राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था में अपनी प्रभावशाली स्थिति बनाये रखने और इजारेदार के पक्ष में उनका उपयोग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उपनिवेशी-व्यवस्था के पतन से पहले उपनिवेशों में पूँजी का निर्यात मुख्य रूप से निजी निवेशों के द्वारा किया जाता था, अब पूँजीवाद के आम-सबूट की दूसरी और विशेष रूप से तीसरी अवस्था में राज्य द्वारा नियंत्रित पूँजीवाद का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए, विदेशों में अमरीका के राजकीय निवेश 1950 में 11.09 अरब डॉलर से बढ़कर 1978 में 54.2 अरब डॉलर अर्थात् पाँच गुना से अधिक हो गये हैं। राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद बहुत से विकासशील देशों ने विदेशी निवेशों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके परिणामस्वरूप दूसरे महायुद्ध के बाद आरंभिक दशकों में निजी इजारेदार पूँजी का प्रवाह सापेक्ष रूप से कम हो गया। मूलतः उपनिवेशों की शोषण का क्षेत्र बनाये रखने के लिए पूँजीवादी राज्य इजारेदारों की सहायता के लिए आगे आ गया है।

राजकीय पूँजी के निर्यात के साथ विकासशील देशों को निजी इजारेदार पूँजी का निर्यात अब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विकासशील देशों को पूँजी का राजकीय निर्यात निजी निवेश के लिए रास्ता साफ करता है। साम्राज्यवादी देश नये राष्ट्रों को ऋण व अनुदान देते हैं और इसके बदले में विदेशी निजी निवेश के लिए 'अनुकूल वातावरण' बनाये रखने तथा अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण की स्थिति में उनके हितों के लिए गारंटी आदि की माँग करते हैं। विकसित देशों की निजी पूँजी ने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में मजदूर श्रम या लिया है। 1960-67 में अर्थव्यवस्थाओं में स्पष्ट रूप से राजकीय पूँजी का प्रभुत्व था लेकिन तब के बाद स्थिति बदल गयी है। 1970 के दशक के अंत में विकासशील देशों में अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, जापान और फ्रांस का निजी निवेश एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका में उनके कुल निवेश का 84.2 प्रतिशत था।¹

पूँजीवादी अर्थशास्त्री यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पूँजी का निर्यात विकासशील देशों में आर्थिक व सांस्कृतिक प्रगति के लिए सहायक है। लेकिन वे इस तथ्य को छुपाने हैं कि विकासशील देशों में निवेश से साम्राज्यवादी राज्यों का इजारेदार पूँजीनिर्भर बर्तन जो मुनाफा प्राप्ति करता है वह उनके नये निवेश में बाध

1 'विकासशील देशों में प्रमुख निजी विदेशी निवेश', कॉन्ट्रिब्यूटन, नवंबर 1979, पृ. 73-78 (अमेरीकी के)।

रपादा है। अमरीका के अधिष्ठान और देशों के अनुसार विकासशील देशों में अमरीका के प्रत्यक्ष निजी निवेश की कुल राशि 1970-78 में 19.2 अरब डॉलर से बढ़कर 40.5 अरब डॉलर अर्थात् 2.7 गुना अधिक हो गयी जबकि इसी अवधि में अमरीका को वार्षिक रूप में भेजा गया अनुरूपी शुद्ध मुनाफा 2.9 अरब डॉलर से छत्रांग लगाकर 8.9 अरब डॉलर अर्थात् 3.1 गुना अधिक हो गया। 1970-78 के बीच विकासशील देशों से अमरीका को शुद्ध मुनाफे के रूप में लगभग 45 अरब डॉलर की राशि भेजी गयी। यह तथ्य कि साम्राज्यवादी इजारेदारियाँ विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा बाहर ले जाती हैं, विकासशील देशों के उत्पादन-शक्तियों के विकास में बाधा डालना है और घरेलू पूँजी के संघर्ष को बढ़ाकर करता है। निवेश द्वारा होने वाली आय का भुगतान, विकासशील देशों के भुगतान समुलन में घाटा रहने का मुख्य कारण है। विदेशी इजारेदार पूँजी, खासतौर से जब वह विकासशील देशों में प्रत्यक्ष-निवेश के रूप में प्रवेश करती है, उनकी अर्थव्यवस्था के उपनिवेशी ढाँचे को मजबूत करती है और सार्वजनिक-क्षेत्र की वृद्धि को रोकने के साथ-साथ उद्योगों के विषम विकास को बढ़ाती है। देशों निजी अथवा सार्वजनिक पूँजी के नियोजन के साथ मिश्रित कंपनियाँ बनाते समय विदेशी व स्यानीय निवेश के बीच अनुपात के सवाल का फैसला विशिष्ट विकासशील देश की सामाजिक नीति की लक्ष्य-दिशा के मानदंड और उसकी अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुसार होता है। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा किसी विशेष विकासशील देश को दी गयी 'सहायता' विशिष्ट दशाओं के अनुसार विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यह आर्थिक गुलामी का साधन बन सकती है और इजारेदार पूँजी के निवेश क्षेत्र व बाजारों के विस्तार का मार्ग भी बन सकती है। कुछ अन्य मामलों में 'सहायता' उपयोग नये क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाता है ताकि बाद में उन्हें विश्व पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में शामिल किया जा सके। अनेक उदाहरणों में जन-विरोधी प्रतिक्रियावादी शक्तियों को सहायता देने या राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलनों के विरुद्ध लड़ने के लिए साम्राज्यवादी देशों से राजकीय ऋण और अनुदान सहायता दी जाती है। कुछ खास देशों में, जिन्हें 'सहायता' दी गई है, अमरीका ने सैनिक बल स्थापित कर लिये हैं और सेना तैनात कर दी है। अतः पूँजी का निर्यात चाहे किसी भी रूप में किया जाये, अभी भी सबाई यह है कि यह उपनिवेशी-शोषण का एक प्रमुख तरीका और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को दबाने का साधन है।

इन दिनों, अर्थ के पूँजीवादी-विभाजन की व्यवस्था में शामिल होने के लिए विकासशील देशों को प्रोत्साहित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियाँ नव-उपनिवेश-व्यवस्था में प्रमुख भूमिका अदा कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूँजी के बीच अंतर्जातीय-विकास को नियंत्रित तथा उसका प्रयोग करने दिना-चाहती है। इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएँ अधिकाधिक मात्रा

में साम्राज्यवाद पर निर्भर हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियाँ विकासशील देशों में नव-निर्मित औद्योगिक-उद्यमों को, एक औद्योगिक-समूह भौगोलिक दृष्टि से अलग-अलग फैली संयोजन इकाई और अन्यत्र निमित्त होने वाले उत्पादों के अलग-अलग हिस्सों की आपूर्ति करने वाला समझती हैं। अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियाँ (अथवा बहुराष्ट्रीय निगम) विकासशील देशों की स्थितियों के अनुरूप बन जाती हैं। यदि उन्होंने खनिज-बोहन (मुख्य रूप से पेट्रोल-तेल) पर से प्रत्यक्ष-नियंत्रण खो दिया है तो उन्होंने निर्माण-उद्योग में घुसपैठ कर ली है। विकासशील देशों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन देने के मुद्दों के पीछे वे वास्तव में औद्योगिक नव-उपनिवेशवाद का क्रियान्वयन ही कर रहे हैं।

विकासशील देशों व साम्राज्यवाद के बीच व्यापार पर भी नव-उपनिवेशवाद के दाग की छाप है। उनके बीच विनिमय का असंतुलन न केवल कम ही नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ गया है। विकासशील देशों द्वारा नियंत्रित किये जाने वाले औद्योगिक व कृषिजन्य कच्चे माल की ऊँची कीमतें, पूँजीवादी देशों द्वारा भेजे जाने वाले औद्योगिक सामान की ऊँची कीमतों से पीछे रही हैं। समुक्त राष्ट्र संघ के आँकड़ों के अनुसार कीमतों के स्तरों में इस बढ़ते अंतर के कारण 1960-70 के दशकों के बीच विकासशील देशों को लगभग तीन अरब डॉलर की हानि हुई। यह हानि अब औद्योगिक रूप से विकसित पूँजीवादी देशों द्वारा उन्हें दी जाने वाली मुफ्त सहायता की राशि से अधिक हो गयी है।

कोई भी यह देख सकता है कि विकासशील देशों को सार्वजनिक व निजी पूँजी के बढ़ते निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय इजारेदारियों के बढ़ते क्रियाकलाप और विकासशील देशों के विदेश व्यापार में बढ़ते असंतुलन के साथ इन देशों से धन बाहर जा रहा है। यह धन मुताफ़ी व लाभार्थों के हस्तान्तरण, ऋण व उधार के पुनर्भूगतान, इजारेदारी मूल्यों के प्रयोग के द्वारा औद्योगिक उत्पादों के कुछ भाग के पुनर्वितरण के रूप में बाहर जा रहा है। युद्ध के बाद धन का यह बहिर्गमन विकासशील देशों में वित्तीय ससाधनों के आगमन से अधिक हो गया है। औद्योगिक-रूप से विकसित देशों के नाम उनके कर्ज में तीव्र वृद्धि इसका अप्रत्यक्ष सूचक है। व्यापार और विकास के लिए समुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन (अंकटाड-UNCTAD) के अनुसार 1979 के शुरु में यह कर्ज 285 अरब डॉलर था।¹

वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति के प्रभाव से, उपनिवेशी पराधीनता से स्वयं को मुक्त करने वाले देशों को उच्च-स्तरीय योग्यता-संपन्न व्यक्तियों की अत्यावश्यक जरूरत होती है। लेकिन साम्राज्यवादी देश विकासशील देशों से उच्च-स्तरीय विनोद्योगों को बाहर निकालने के लिए अनेक तरह के तरीकों का प्रयोग कर रहे

है। ऐसा होने पर विकासशील देशों को दुहरा नुकसान—विशेषज्ञों का और उनके प्रशिक्षण पर खर्च किये गये धन का, होता है। यूनेस्को (शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन) के अनुसार 1970 में विकासशील देशों में आने कर्मियों की शिक्षा व प्रशिक्षण पर लगभग 12 अरब डॉलर खर्च किये। इन कार्य के लिए अन्य देशों में उन्हें लगभग डेढ़ अरब डॉलर की सहायता मिली जबकि नुकसान कर्मियों के बाहर धने जाने से उन्हें लगभग 8-10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।

युद्धोत्तर काल की एक विशेषता तथाकथित सामूहिक नव-उपनिवेशवाद (विकासशील देशों को गुलाम बनाये रखने के उद्देश्य में साम्राज्यवादी शक्तियों के संयुक्त-प्रयत्न की व्यवस्था) का प्रकट होना व उसका विकास है। सामूहिक उपनिवेशवाद का एक रूप विकासशील देशों को एकांतिक आर्थिक गुटों, (जैसे यूरोपीय आर्थिक समुदाय, त्रिसमे फाम व डेन्ड्रियम के भूतपूर्व उपनिवेश सहायक सदस्य के रूप में शामिल हैं) में शामिल करना है। इन संगठनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नियम बनानी पुरानी उपनिवेशी सुविधाओं को बनाये रखने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं बल्कि नयी विशेष सुविधाएँ पाने की कोशिश भी करते हैं। ताकि वे अफ्रीका के भूतपूर्व उपनिवेश व अर्ध-उपनिवेशी देशों के संसाधनों के संयुक्त शोषण का प्रबंध कर सकें। अफ्रीकी बाजारों में पश्चिमी यूरोप की इजारेदारियों द्वारा निमित्त वस्तुओं का व्यापक प्रवेश देशीय उद्योग को नकारात्मक रूप में प्रभावित करता है। अल्प-उत्पन्न से लैस छोटे उद्यमों द्वारा निमित्त स्थानीय उत्पाद न तो कीमत में और न गुणवत्ता में ही बड़ी यूरोपीय कंपनियों के उत्पादों से होड़ कर पाते हैं। इसके साथ अफ्रीका के विकासशील देशों की एक विशेषता, मूल्यवान औद्योगिक या कृषियन्त्र कच्चा माल उत्पादन करनेवाले उन एक या दो क्षेत्रों का तीव्र विकास है, जिनके विकास में आर्थिक-रूप से विकसित पश्चिमी देशों के उद्योगों की सक्रिय दिलचस्पी है। इसके परिणामस्वरूप अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्थाएँ एक ओर अभी तक अपनी अनिवार्य 'एक फ्रन्ली' विशेषता को बचाये हुए हैं, दूसरी ओर वे औद्योगिकीकरण में मंद गति का सामना करती हैं क्योंकि शिशु देशी उद्योग पश्चिमी यूरोप की इजारेदारियों के विरुद्ध प्रतिযোগिता नहीं कर पाते हैं। अफ्रीकी देश यूरोपीय आर्थिक समुदाय से मिलने वाले ऋण का निवेश मुख्य रूप से आधार-भूत ढाँचे के विकास और परंपरागत सामान के निर्यात की वृद्धि में करते हैं, बहु-क्षेत्रीय स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का निर्माण करने वाली परियोजनाओं में नहीं करते।

ऋण देने और वित्तीय निवेश करने वाले संगठन जैसे—युननिर्माण व विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आई० बी० आर० डी०), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई० एम० एफ) तथा अन्य संगठन, सामूहिक उपनिवेशवाद के महत्वपूर्ण अभिकरण हैं। वे मुख्य रूप से निजी इजारेदारियों द्वारा विकासशील देशों को निर्यात की

नयी पूँजी की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सगठन प्रायः उन देशों को ऋण देने हैं जो साम्राज्यवाद को आर्थिक-राजनैतिक छूट देते हैं और जो साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरोधी हैं उन्हें ऋण देना वे नापसंद करते हैं।

राष्ट्रीय उद्योग के निर्माण के लिए विशाल संसाधनों की जरूरत होती है। विकासशील देशों में नयी परियोजनाओं के लिए वित्त-प्रवर्ध मुख्य रूप से राज्य करता है और इससे बजट संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। जब विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (इजारेदार पूँजी के हितों की रक्षा करने वाला सगठन) से सहायता माँगते हैं तो कोष सदैव जल्दी से सहमत नहीं होता। विकासशील देशों में मुद्रा-प्रसार को 'सामान्य' करने के लिए कोष अक्सर आर्थिक-विकास की दरों व सार्वजनिक खर्च को कम करने की माँग करता है। कोष का नेतृत्व अपने सदस्य देशों में औद्योगिकीकरण को हानि पहुँचाने हुए भी विरोधी स्थिरता को प्राथमिकता देने की माँग करता है यद्यपि आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए औद्योगिकीकरण को सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। आई० डी० आर० डी० भी इन्हीं नीतियों के अनुसार काम करता है।

सैनिक तानाशाही और कठपुतली शासनो की स्थापना एक ऐसा तरीका है, विकासशील देशों में अपनी सर्वोच्चता बनाये रखने के लिए साम्राज्यवादी देश जिसका व्यापक प्रयोग करते हैं। जब जन-समूह ध्रुव शासकों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं तो साम्राज्यवादी 'स्वतंत्रता व प्रजातंत्र' के बहाने से मुक्ति-आंदोलनों को बल-प्रयोग से दबाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। अफ्रीका और सातीनी अमरीका के राज्य इस तरह के हस्तक्षेप के हमेशा शिकार रहे हैं। तथ्यों से पूरी तरह प्रकट है कि साम्राज्यवाद ने अपने सुटेरेपन के सारतत्त्व को अभी नहीं छोड़ा है। विकासशील देशों के विरुद्ध प्रत्यक्ष राजनैतिक-आर्थिक व सैनिक दबाव के प्रयोग को छोड़े बिना आधुनिक उपनिवेशवादी विचारधारात्मक भीतरघात के तरीकों का भी प्रयोग करते हैं। इन विशेष विचारधारात्मक धारणाओं में से एक 'वर्ग-शांति' और 'भागीदारी' की धारणा प्रमुख है। आधुनिक पूँजीवादी अर्थशास्त्री यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वर्ग-सहयोग विकासशील देशों में आर्थिक-विकास को तीव्र करेगा। उदाहरण के लिए, अमेरिकन प्रो० जान पी० पावेलसन के अनुसार विकासशील देशों के अभी तक पिछड़े बने रहने का मुख्य कारण उत्पादन में शामिल लोगों के बीच परस्पर विश्वास की कमी है। पावेलसन बल देकर कहते हैं—“अल्प विकसित देशों का ऐसे स्पष्ट रूप से परिभाषित समूहों में विभाजन, (जैसे, सेना राजनीतिक, जमींदार, व्यापारी, मजदूर, किसान, जनजाति, छात्र आदि) जो न केवल एक-दूसरे से संपर्क ही नहीं रखते हैं बल्कि सक्रिय रूप से एक-दूसरे के प्रति नापसंदगी व अविश्वास के भाव रखते हैं तथा मुकसान पहुँचाने की

हैं। ऐसा होने पर विकासशील उनके प्रशिक्षण पर खर्च किये गये स स्कुति के लिए संयुक्त राष्ट्र देशों ने अपने कर्मियों की शा किये। इस कार्य के लिए अन् मिली जबकि कुशल कर्मियों के का नुकसान हुआ।

युद्धोत्तर काल की ए (विकासशील देशों को गुला समुक्त-प्रयत्न की व्यवस्था' निवेशवाद का एक रूप वि आर्थिक समुदाय, जिसमें रूप में शामिल हैं) में शा' अरबी पुरानी उपनिवेश' बन्कि नरी विशेष सु' भूतपूर्व उपनिवेश व र कर सके। अकीरी वस्तुओं का व्यापक है। अन्त-उत्तरणों में और न गुणवत्ता इसके साथ अर्थात् या वृषिजन्य व है, तिनके विहा दिमचगरी है।। तद अपनी र औद्योगिकीय परिषदी यूरो' देश यूरोपीय रूप इ'व के' क्षेत्रीय रूप

Handwritten notes in Hindi, partially legible, appearing as bleed-through or marginalia on the right side of the page.

Extensive handwritten notes in Hindi, continuing the discussion or providing additional context, located on the right side of the page.

Handwritten notes at the bottom of the page, possibly a signature or date.

यसो पूँजी की सुरक्षा की गारंटी देने हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रायः उन देशों को ऋण देने हैं जो साम्राज्यवाद को आधिक-राजनैतिक छूट देने हैं और जो साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरोधी हैं उन्हें ऋण देना वे नापसंद करते हैं।

राष्ट्रीय उद्योग के निर्माण के लिए विशाल समाघनों की जरूरत होती है। विकासशील देशों में नयी परियोजनाओं के लिए वित्त-प्रबंध मुख्य रूप से राज्य करता है और इससे बचट सबधी षडिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। जब विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (इजारेदार पूँजी के हितों की रक्षा करने वाला संगठन) से सहायता माँगते हैं तो कोष सदैव जल्दी से सहमत नहीं होता। विकासशील देशों में मुद्रा-प्रसार को 'सामान्य' करने के लिए कोष अक्सर आधिक-विकास की दरों व सार्वजनिक खर्च को कम करने की माँग करता है। कोष का नेतृत्व अपने सदस्य देशों से औद्योगिकीकरण को हानि पहुँचाते हुए भी वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देने की माँग करता है यद्यपि आधिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए औद्योगिकीकरण को सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। आई० बी० आर० डी० भी इन्ही नीतियों के अनुसार काम करता है।

सैनिक वानाशाही और बटुलसी शासनों की स्थापना एक ऐसा तरीका है, विकासशील देशों में अपनी सर्वोच्चता बनाये रखने के लिए साम्राज्यवादी देश जिसका व्यापक प्रयोग करते हैं। जब जन-समूह घृष्ट शासकों के विरुद्ध विद्रोह करते हैं तो साम्राज्यवादी 'स्वतंत्रता व प्रजातंत्र' के बहाने से मुक्ति-आंदोलनों को बल-प्रयोग से दबाने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। अफ्रीका और लातीनी अमरीका के राज्य इस तरह के हस्तक्षेप के हमेशा शिकार रहे हैं। तथ्यों से पूरी तरह प्रकट है कि साम्राज्यवाद ने अपने लुटेरेपन के सारतत्त्व को अभी नहीं छोड़ा है। विकासशील देशों के विरुद्ध प्रत्यक्ष राजनैतिक-आधिक व सैनिक दबाव के प्रयोग को छोड़ें बिना आधुनिक उपनिवेशवादी विचारधारात्मक भीतरघात के तरीकों का भी प्रयोग करते हैं। इन विशेष विचारधारात्मक धारणाओं में से एक 'वर्ग-जाति' और 'भाषीदारी' की धारणा प्रमुख है। आधुनिक पूँजीवादी अर्थशास्त्री यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वर्ग-सहयोग विकासशील देशों में आधिक-विकास को तीव्र करेगा। उदाहरण के लिए, अमेरिकन प्रो० जान पी० पावेलसन के अनुसार विकासशील देशों के अभी तक पिछड़े बने रहने का मुख्य कारण उत्पादन में शामिल लोगों के बीच परस्पर विषवास की कमी है। पावेलसन बल देकर कहते हैं—“अल्प विकसित देशों का ऐसे स्पष्ट रूप से परिभाषित समूहों में विभाजन, (जैसे, सेना राजनीतिज्ञ, जमींदार, व्यापारी, मजदूर, किसान, जनजाति, छात्र आदि) जो न केवल एक-दूसरे से संपर्क ही नहीं रखते हैं बल्कि सक्रिय रूप से एक-दूसरे के प्रति नापसंदगी व अविश्वास के भाव रखते हैं”

कोशिश करते हैं, उत्पादन के उपकरणों के तकमंगन विभाजन को रोकना है।¹

विकासशील देशों की सामाजिक-संरचना के पावेस्मान के विभाजन को हमें उसकी बुद्धि के लिए छोड़ देना चाहिए। अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वह वर्ग-विरोधों के स्रोतों का उत्पादन नहीं करता है बल्कि विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति की अनिवायं शर्त के रूप में वर्ग-सहयोग की अपील करता है। राष्ट्रीय एकता और राजनैतिक स्थिरता निश्चय ही सामाजिक-आर्थिक विकास की सफलता के लिए सब वही महत्त्वपूर्ण शर्तें हैं लेकिन नव-उपनिवेशवाद के समर्थक विकासशील व साम्राज्यवादी देशों के बीच मौजूद अंतर्विरोधों को छुपाने की कोशिश करते हैं जबकि साम्राज्यवाद विकासशील देशों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने और उन्हें विकास का गैर-पूँजीवादी रास्ता ग्रहण करने से रोकने में लगा हुआ है।

पूँजीवादी अर्थशास्त्री भागीदारी के सिद्धान्त पर भी बहुत बल देते हैं यद्यपि इसके सारतत्त्व और, ज्यादा महत्त्वपूर्ण यह है कि, इसके तरीकों में हाल में महत्त्वपूर्ण बदलाव आये हैं। उपनिवेशी व्यवस्था के पतन के बाद के आरंभिक वर्षों में पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों ने यह दावा किया कि विकासशील देश अपने पूर्ववर्ती स्वामी राज्यों के साथ भागीदार बन गये हैं क्योंकि उन्होंने उनके (साम्राज्यवादी देशों के) साथ अपने परंपरागत संबंधों को बनाये रखा है। ब्रिटिश राष्ट्र-कुल संघ, फ्रांसीसी-अफ्रीकन समुदाय तथा अन्य राजनैतिक संगठन, जिनमें सदस्यों की स्थिति असमान स्तर की है, विधिवत बनाये गये और उनका विस्तार किया गया। अमरीका ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि अपनी ऐतिहासिक नियति के कारण वह विकासशील देशों का भागीदार है क्योंकि वह भी पहले यूरोपीय उपनिवेश था। चूंकि यह भागीदारी व्यवहार में साम्राज्यवादी शक्तियों पर विकासशील देशों की निर्भरता को बनाये रखने में ही सहायक थी, अतः इसका आकर्षण तेजी से कम हो गया। इसी कारण नव-उपनिवेशवाद के समर्थकों को भागीदारी के सिद्धान्त का आधुनिकीकरण और इसके तरीकों का नवीकरण करना पड़ा।

औद्योगिकीकरण, कृषि-मुधार, सार्वजनिक-क्षेत्र का निर्माण, आर्थिक नियोजन और श्रम के पुराने अंतर्राष्ट्रीय विभाजन का विनाश—जो सब विकासशील देशों में विश्व-समाजवादी व्यवस्था के अनुभवों से जुड़े हुए हैं, साम्राज्यवादी शक्तियों उनके झूले विरोध का खतरा उठाना प्रायः नापसंद करती हैं। विकासशील देशों में आर्थिक कार्यों के लिए तत्काल सहायता देने के शब्दों को पहचानते हुए साम्राज्यवादी शक्तियाँ उन्हें पूँजीवादी विकास के उरा रास्ते पर धकेल रही हैं जिसमें उनकी अर्थ-

1. जार्ल पी. पावेस्मान, 'आर्थिक विकास की संस्थाएँ : विकासशील देशों में वर्गों प्रवर्धन-व्यवस्था का सिद्धान्त', प्रिन्टन, एन. जे., 1972, पृ. 33 (नवमी में)।

व्यवस्थाएँ विचर पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से एकीकृत हो जाएँगी। इससे विकासशील देश साम्राज्यवादी देशों पर आर्थिक दृष्टि से और अधिक निर्भर हो जायेंगे।

3. विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के विशिष्ट लक्षण

यह तथ्य, कि एशिया, अफ्रीका व लातीनी अमरीका के बहुसंख्यक देशों ने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, अभी इसका सूचक नहीं है कि विकसित साम्राज्यवादी देशों पर उनकी आर्थिक निर्भरता के संकेतों का अंत हो गया है। उपनिवेशवाद की राजनैतिक प्रभुता के विपटन ने भूतपूर्व उपनिवेशों व अर्ध-उपनिवेशों देशों में सिर्फ शोषण के रीर-आर्थिक रूपों को नष्ट करने में सहायता दी। राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद यदि आर्थिक मुक्ति नहीं आती है या उपनिवेशों आर्थिक ढाँचा मुरझित छोड़ दिया जाता है तो राजनैतिक स्वतंत्रता अधूरी होती है और काल्पनिक हो जाने की हद तक अपना अर्थ खो देती है।

राजनैतिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है हालाँकि यह साम्राज्यवाद की बेड़ियों से भूतपूर्व उपनिवेशों व अर्ध-उपनिवेशों देशों की मुक्ति की ओर पहला कदम ही है। इसका महत्व यह है कि वे विदेशी आधिपत्य से पूर्ण मुक्ति के लिए संघर्ष कर सकते हैं। वर्तमान में उनके राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों के मुख्य मुद्दे आर्थिक स्वतंत्रता, विदेशी पूँजी के आधिपत्य व साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा उन पर लादे गये सूट-मारपूर्ण संबंधों की व्यवस्था की समाप्ति और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाओं की स्थापना है।

विकासशील देशों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ क्या हैं? उनके उत्पादन-संबंध नानारूपी, अटिल और अंतर्विरोधी हैं। वास्तव में उनमें आर्थिक संबंधों की पूरी शृंखला—आदिम जातीय से लेकर आधुनिक पूँजीवादी तक—शामिल है। उनमें बहुत भिन्न प्रकार की आर्थिक संरचनाएँ एक-दूसरे से भुँधी हुई हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता पाने के बाद पहले वर्षों में कुछ विकासशील देशों ने विशेष रूप से अफ्रीका के देशों ने, अपने मजबूत जनजातीय व सामुदायिक संबंधों को बनाये रखा। इनमें से कुछ देशों में सामुदायिक स्वामित्व व प्राकृतिक अर्थ-व्यवस्था पर आधारित यह व्यवस्था धीरे-धीरे छोटे स्तर के वस्तु-उत्पादन में विकसित हुई जबकि कुछ अन्य देशों में सामंती अथवा अर्ध-सामंती व्यवस्था में विकसित हुई। इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन पर विदेशी व स्थानीय पूँजी का बड़ा भारी प्रभाव था। इन संरचनाओं के अलावा अधिकांश विकासशील देशों में शार्व-जनिक क्षेत्र का भी विशेष स्थान है। विभिन्न अर्थ-संरचनाओं के बीच संबंध, प्रत्येक देश-विशेष में ऐतिहासिक रूप से निश्चित परिस्थितियों, उत्पादन-शक्तियों के विकास, सामंती संबंधों के अवशेष, विदेशी पूँजी के आधिपत्य की सीमा आदि पर निर्भर है।

विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था की विशेषता एक-कमली विकास है। इसमें संपूर्णराष्ट्रीय-उत्पाद और निर्यात में एक या दो उत्पादन-सामग्री की पूरी प्रधानता होती है। उनकी उद्योग-व्यवस्था अल्पविकसित है। 1980 के आरंभ में उनकी आबादी पूंजीवादी विश्व की आबादी के आधे भाग से ज्यादा थी लेकिन उनका औद्योगिक उत्पादन संपूर्ण पूंजीवादी उत्पादन के दसवें भाग से भी कम था। विकासशील देशों में भारी उद्योगों में प्रतिव्यक्ति उत्पादन विकसित पूंजीवादी देशों के उत्पादन का तीसरा भाग है। विकासशील देशों की एक विशेषता मूलतः पिछड़ी कृषि-व्यवस्था है जिसमें आदिम औजारों का प्रयोग होता है। इन देशों में लाभ-प्रद रूप से काम करने वालों का 50 से 90 प्रतिशत भाग कृषि के नाम में लगा हुआ है।

आर्थिक-विकास का निम्न स्तर और बहुसंरचनात्मक अर्थव्यवस्था जटिल सामाजिक बनावटों को निश्चित करती है। इन देशों में ऐसे वर्ग और सामाजिक-संस्तर अब भी बचे हैं जो विकसित पूंजीवादी देशों में काफ़ी पहले समाप्त हो गये थे। इन देशों के पूंजीपति व सर्वहारा पश्चिमी यूरोप एवं अमरीका के पूंजीपति व सर्वहारा से कुछ भिन्न हैं।

एक-कमली अर्थव्यवस्था, अल्प आर्थिक-विकास, आदिम कृषि, अत्यंत कम धम-उत्पादकता और स्थानीय सुयोग्य कर्मियों की कमी का परिणाम प्रति-व्यक्ति अल्प-आय हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सच के आँकड़ों के अनुसार 1980 के दशक के आरंभ में विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति आय औद्योगिक रूप से विकसित पूंजीवादी राज्यों से 14 गुना कम थी, जबकि विकसित देशों में यह संख्या 6000-7000 डॉलर है, पेट्रोलियम निर्यात नहीं करने वाले विकासशील देशों में यह 350-450 डॉलर है और 29 सबसे कम विकसित देशों में सिर्फ 150 डॉलर है।¹ परिणामस्वरूप विकासशील देशों में जीवन-स्तर अत्यंत नीचे है। जनसंख्या पोषाहार की व्यवस्थित कमी से पीड़ित है। इन देशों में बहुत कम स्कूल व अस्पताल हैं और डॉक्टर व शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। निरक्षरता की दर भी इन देशों में बहुत ऊँची है।

परम्परागत आर्थिक पिछड़ेपन तथा मेहनतकशों की गरीबी व भूख को समाप्त करने के लिए विकासशील देशों को बहुत व्यापक सामाजिक-आर्थिक सुधार करने होंगे। और ऐसा करने के लिए उन्हें विदेशी पूंजी की सर्वोच्चता की समाप्ति, अपने देशों का औद्योगिकीकरण, मूलभूत भूमि-सुधारों पर अमल, अर्थव्यवस्था के सरकारी क्षेत्र को मजबूत करना तथा समाजवादी देशों से परस्पर-सामंजसक

1. 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास के आँकड़ों की पुस्तिका', परिशिष्ट 1919, पृ० 211
कमली में।

मंघो का विस्तार करना होगा। इन प्रमुख ऋदमों को उठाना इस पर निर्भर है कि विकासशील देश कौन-सा रास्ता ग्रहण करते हैं।

नव-स्वतंत्र देशों के लिए विकास के दो रास्ते—राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की वर्तमान अवस्था में विकासशील देश विकास के दो रास्तों—पूँजीवादी और गैर-पूँजीवादी—में से कोई एक चुन सकते हैं। कुछ विकासशील देशों में वर्ग-शक्तियों के सह-संबंध और स्थापित आर्थिक-सामाजिक संरचना के कारण पूँजीवादी विकल्प निश्चित हो गया है। वहाँ राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष को अवरुद्ध करने और पूँजीवादी विकास के माध्यम से आर्थिक प्रगति को पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका अनिवार्य परिणाम पूँजीवाद में अतर्निहित सामाजिक अंतर्विरोधों में वृद्धि, जैसे अव्यवस्थित आर्थिक विकास, राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के हार्थों में संपदा का अधिक-से-अधिक केंद्रीकरण और शोषक-वर्ग में मेहनतकारों के जीवन-स्तरों के बीच बढ़ता हुआ होता है।

इतिहास बताता है कि जिन देशों ने पूँजीवादी रास्ता पसंद किया, वे अपने सामने प्रस्तुत एक समस्या का समाधान करने में भी असफल रहे। वे धर्म के अंतर्राष्ट्रीय पूँजीवादी विभाजन के अंतर्गत साम्राज्यवादी देशों को कच्चा-माल व कृषि-जन्य पदार्थों के असमान व अधीनस्थ आपूर्ति करने वाले बने रहते हैं। पूँजीवाद के अंतर्गत विकासशील देश शोषण की समाप्ति, आर्थिक-स्वतंत्रता की प्राप्ति व अन्य कार्य नहीं कर सकते।

राजनैतिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है किंतु राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति के विकास में सिर्फ आरंभिक ऋदम है। राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद अनेक अनिवार्य जनवादी मुद्दों का अवश्यक है, जैसे—उपनिवेशी आर्थिक ढाँचे का विनाश; विदेशी हजारेदार पूँजी के आधिपत्य का अंत; साम्राज्यवादी राजनैतिक नियंत्रण के विविध छुपे रूपों की समाप्ति; स्थानीय शोषक वर्ग व सामाजिक सस्तरों, जो अब भी साम्राज्यवादी प्रभुत्व के लिए सामाजिक आधार-भूमि बनाते हैं (जैसे सामंती जमींदार, साम्राज्यवादपरस्त नौकरशाही नेतृत्व आदि), की आर्थिक स्थितियों का नाश; सामाजिक व राजनैतिक जीवन का जनवादीकरण और राज्य-शक्ति के विकास पर मेहनतकारों के नियंत्रण की स्थापना। इन कार्यों के आधार पर ही तीव्र आर्थिक विकास और प्रगतिशील आर्थिक उपार्यों (जिनका वर्णन मैं आगे करूँगा) की प्राप्ति संभव है।

सुसंयत रूप से विकसित होती राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति का परिणाम होता है—गैर-पूँजीवादी रास्ते पर प्रगति। यह प्रगति आवश्यक भौतिक व तकनीकी आधारों के निर्माण तथा समाज की वर्गीय व सामाजिक पुनर्संरचना के बाद समाजवाद की ओर परवर्ती-संक्रमण के लिए परिस्थितियों की रचना करती है।

जब साम्राज्यवाद का सारे विश्व पर पूरी तरह आधिपत्य था, तब एशिया,

अकीका व सातीनी अमरीका के उपनिवेशी एवं अर्ध-उपनिवेशी देशों में ग्रैर-पूँजीवादी-विकास असंभव था। रुम में महान् समाजवादी अक्यूबर-क्रान्ति की विजय, विश्व समाजवादी व्यवस्था के उदय और आधुनिक विश्व में उमकी बड़की भूमिका ने विकासशील देशों के लिए विकास के ग्रैर-पूँजीवादी रास्ते के द्वार पूरी तरह खोल दिये हैं।

वैज्ञानिक समाजवाद के सस्थापक मार्क्स और एंगेल्स ने यह मिद्ध किया था कि मानवता विकास की निश्चित अवस्थाओं से, जिनको उन्होंने सामाजिक-आर्थिक संरचना कहा, गुजरती है। मार्क्स और एंगेल्स ने जो कुछ प्रतिपादित किया, नयी ऐतिहासिक स्थितियों के अनुकूल उसका विकास करते हुए लेनिन ने साम्राज्यवाद के युग में समाजवादी प्रगति के सिद्धांत को, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े देशों में समाजवाद की विजय का व्यावहारिक कार्यक्रम भी शामिल है, प्रस्तुत किया। समाजवादी अक्यूबर-क्रान्ति तथा अपने उपनिवेश व साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों के प्रभाव से पूरब के जनगणों की चेतना में जो उभार आया उसने आर्थिक रूप से पिछड़े देशों, जिनमें पूँजीवाद का विकास नहीं हुआ था और परिपक्व सर्वहारा वर्ग का अभाव था, में सामाजिक मुक्ति के विशिष्ट रास्तों के निर्धारण की आवश्यकता उत्पन्न की। दूसरे शब्दों में यह सवाल उठा कि ये राष्ट्र पूँजीवाद को छोड़ते हुए समाजवाद की ओर बढ़ सकते हैं या नहीं।

लेनिन इस सवाल का जवाब देने वाले पहले मार्क्सवादी थे। उन्होंने कहा— “क्या हमें इस दावे को सही मानना चाहिए कि पिछड़े देशों (जो अब मुक्ति की राह पर हैं तथा जिनमें युद्ध के बाद प्रगति की ओर कुछ बढ़ाव दिखाई देता है) के लिए आर्थिक विकास की पूँजीवादी अवस्था को पाना अनिवार्य है? हमने इसका उत्तर ‘नहीं’ में दिया।

“...विकसित देशों के सर्वहारा की सहायता से पिछड़े देश पूँजीवादी अवस्था से गुजरे बिना ही सोवियत-व्यवस्था तक और विकास की कुछ विशेष अवस्थाओं को पार करके साम्यवाद तक पहुँच सकते हैं।”

लेनिन के इस प्रमाणीकरण ने कि विकास की ग्रैर-पूँजीवादी अवस्था संभव है, आर्थिक रूप से पिछड़े देशों के जनगणों के सामने, पूँजीवाद का अनुभव किये बिना ही एक नयी शोषण-मुक्ति समाजवादी व्यवस्था की ओर बढ़ने का परिप्रेक्ष्य खोल दिया। उन्होंने इन दावों की अमर्ति दिखाई कि जिन देशों ने पूँजीवाद द्वारा प्रदत्त पर्याप्त भौतिक-उत्पादन व समाजवाद के लिए आवश्यक अन्य स्थितियों को पाये बिना ही उपनिवेशवाद का जुआ दूर कर दिया है, उन्हें पूँजीवाद की अवस्था से

1. जी० आर० लेनिन 'अधुनिक इतरवैकल्प की दूसरी क्रांति', 19 नुम्बर् के 7 अगस्त, रवाएँ, भाग 31, पृ० 244।

निवार्य रूप से गुजरना पड़ेगा।

विकास के गैर-मूजीवादी रास्ते का लेनिन का सिद्धांत, रूस के भूतपूर्व पिछड़े नगणों के अनुभव पर आधारित था। बुखारा, अजरबैजान और आर्मेनिया के सोवियत गणराज्यों की स्थापना व दृढ़ीकरण की ओर सकेत करते हुए लेनिन ने बताया—“ये गणराज्य इस तथ्य को प्रमाणित व उसकी पुष्टि करते हैं कि सोवियत सरकार के विचार तथा सिद्धांत औद्योगिक रूप से विकसित देशों में ही नहीं, उन शो में ही नहीं जहाँ सर्वहारा-वर्ग जैसा सामाजिक आधार मौजूद है, बल्कि उन शो में भी समझे जाते हैं और तत्काल व्यवहार्य हैं जिनका आधार किसान वर्ग है।”¹ विभिन्न परिस्थितियों के होने पर एक समय पिछड़े जनगणों द्वारा गैर-मूजीवादी रास्ते पर विकास करने की संभावना मंगोलियाई लोक गणराज्य के अनुभव से भी प्रमाणित होती है, जिसने सोवियत-सघ की सहायता से पूंजीवाद को फोड़कर समाजवाद का सफलतापूर्वक निर्माण किया है।

पिछड़े देशों में विनास के गैर-मूजीवादी रास्ते के संबंध में लेनिन ने जो कुछ कहा था, जिन देशों में स्थानीय पूंजीवाद अभी महत्वपूर्ण शक्ति नहीं बना है, उन देशों के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की वर्तमान अवस्था में वह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन देशों में समाजवाद के निर्माण के लिए भौतिक, तकनीकी, सामाजिक साधनों का अभी भी अभाव है। इन देशों में प्रगतिशील शक्तियाँ राज्य-तंत्र पर विश्वास करते हुए तथा जनगणों के समर्थन से ऐसे मूलगामी मुद्धार कर रही हैं जो समाजवाद में संक्रमण के लिए परिस्थितियों का निर्माण करेंगे।

जिन देशों ने दूसरे महायुद्ध के बाद स्वयं को साम्राज्यवादी गुलामी से मुक्त किया, अनुकूल बाहरी व भीतरी कारकों का सम्मिलन उन देशों में विकास की गैर-मूजीवादी रास्ते की संभावनाओं को अधिक वास्तविक बनाता है। विष्व-समाजवादी व्यवस्था का निर्माण तथा इसकी शक्ति व प्रभाव में वृद्धि, साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था का पतन, समय रूप से साम्राज्यवाद का अधिक निर्बल हो जाना और भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले देशों के बीच सह-अस्तित्व की नीति की सफलता बाहरी कारकों में हैं। समाजवादी देशों से सब क्षेत्रों में सहायता विकासशील देशों को पूंजीवादी आर्थिक-व्यवस्था की पकड़ को तोड़ने या कम-से-कम उस पर निर्भरता को गंभीरता से कमजोर करने का अवसर देती है। विकासशील देशों को राष्ट्रीय-वर्गियों के प्रशिक्षण, शिक्षा को प्रोत्साहन और अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए समाजवादी देशों से जो सहायता मिलती है, वह साम्राज्यवादियों को इन देशों पर दबाव डालने के साधनों में बचिन करती

1. वी० स्टालीन, लेनिन, कोविचों को जादरी अक्षिण कनी बचिन, सितम्बर 22-29, 1920 ई०, संकलित रचनाएँ, भाग 31, पृ० 490 (अंश 30)।

है। राष्ट्रीय-जनवादी राज्य वह साधन है, जिसके माध्यम से मुक्त हुए देश पूँजीवादी रास्ते पर विकास करते हैं। जहाँ तक इसके वर्गीय सारतत्त्व का संबंध है, राष्ट्रीय जनवादी राज्य क्रांतिकारी, साम्राज्यवाद-विरोधी, सामंत-विरोधी और पूँजीवाद-विरोधी शक्तियों के सम्मिलन के हितों को अभिव्यक्त करता है। बहुमत की जनवादी तानाशाही या क्रांतिकारी जनगण की तानाशाही है। प्रकार की राजनैतिक-व्यवस्था वाले देशों ने पूँजीवाद को अस्वीकार कर दिया और ऐसा रास्ता स्वीकार किया है जिसका परिप्रेक्ष्य समाजवादी समाज है।

नये देशों के घैर-पूँजीवादी रास्ते पर विकास के लिए वस्तुनिष्ठ संभावना के मौजूद होने का अर्थ यह नहीं है कि ऐसा अपने आप हो जायेगा। चूंकि इन देशों में मजदूर-बर्ग अभी बहुत कमजोर है और काफ़ी प्रभावशाली नहीं है। आगामी विकास बहुत कुछ इस पर निर्भर है कि कौन-सी सामाजिक-शक्तियाँ-साम्राज्यवाद-समर्थक या क्रांतिकारी जनवादी, देश का नेतृत्व करती हैं तथा कि पर-साम्राज्यवादी शक्तियों पर या विश्व समाजवादी व्यवस्था पर, ये शक्तियाँ विजयवादी हैं। घैर-पूँजीवादी विकास के लिए आवश्यक जगत यह है कि सार्वजनिक प्रशासनिक शक्तियाँ संयुक्त हो जाएँ और जनगण आंतरिक प्रतिक्रिया। साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रशासनिक मोर्चा बनाएँ तथा उन्हें मजबूत करें। राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन की साम्राज्यवाद-विरोधी दिशा और व्यापक रूप से घैरे सामाजिक-आर्थिक विच्छेदन को समाप्त करने की इच्छा ही अनेक सामाजिक-शक्तियों के संयुक्त-राष्ट्रीय मोर्चा के निर्माण के लिए वस्तुनिष्ठ परिस्थितियों की रचना करती है।

हमें उन विकासशील देशों, जिन्होंने घैर-पूँजीवादी विकास का मार्ग चुन लिया है, से किये गये मुख्य आर्थिक-सुधारों की परीक्षा करनी चाहिए।

विदेशी इन्वारेस्टमेंटों के आधिपत्य को समाप्त—विदेशी इन्वारेस्टमेंटों के आधिपत्य को समाप्त करने वाले राजनैतिक-आर्थिक उपायों की एक व्यवस्था का चिन्तन तथा विचार घैर-पूँजीवादी विकास के लिए सबसे बड़ी एक प्रमुख आवश्यकता है। यह व्यवस्था सामाजिक-आर्थिक सुधारों की मुख्य दिशा है क्योंकि यह साम्राज्यवादी-शक्तियों में आर्थिक-जनकता वाले के सर्प, सामाजिक-राजनैतिक शक्तियों की हृदय और विदेशी-निधि के साथ बहुत निष्ठा के साथ जुड़ी है।

विकासशील देशों से सब-इन्वारेस्टमेंट के अधिपत्य अभी भी बचे हुए हैं इन्वारेस्टमेंट इन्वारेस्टमेंटों के आधिपत्य के अन्त की इच्छा होती है। विदेशी इन्वारेस्टमेंटों के विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ हैं और उनके राजनैतिक व धन-सम्पत्तियों का संरक्षण करने हुए भारी-भारों का सामना करती हैं। वे विकासशील देशों को उनके सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक

पूँजी से वंचित कर रही हैं क्योंकि वह आवश्यक पूँजी मुताफे के रूप में बाहर भेज दी जाती है। वास्तव में बहुराष्ट्रीय निगमों के क्रियाकलाप अपने प्राकृतिक व अन्य ससाधनों पर नये देशों की सर्वोच्चता को क्षति पहुँचाते हैं और उनके पिछड़ेपन को स्थायी बनाते हैं।

विकासशील देशों में विदेशी इजारेदारियों की सर्वोच्चता की समाप्ति का कार्य प्रायः इनके उद्यमों के राष्ट्रीयकरण से शुरू होता है। अल्जीरिया, सीरिया, गिनी, पेरू और अन्य देशों ने राष्ट्रीयकरण के अभियान शुरू किये हैं। उदाहरण के लिए अकेले सातीनी अमरीका में 1970-76 के बीच 163 उद्यमों का राष्ट्रीयकरण किया गया।¹ वेनेजुएला, पेरू, इक्वेडोर, गुयाना और जमैका ने मोटे तौर से अपने धनन व तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। बेनिन के लोकतन्त्रराज्य ने विदेशियों को मिली तेल-रियायती, कपास का उत्पादन व विक्रय, औषधि-उद्योग, विद्युत-ऊर्जा उत्पादन आदि का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। विदेशी इजारेदारियों की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण जल्दी और क्षतिपूर्ति के द्वारा किया गया है। अर्थव्यवस्था के कुछ विशेष क्षेत्रों में विदेशी पूँजी के निवेश पर रोक लगा कर और उन्हें पूरी तरह से राजकीय उद्यमों का क्षेत्र घोषित करके भी विदेशी इजारेदारियों की गतिविधियों को सीमित किया गया है।

कुछ विकासशील देश विदेशी पूँजी की गतिविधियों को सीमित व नियंत्रित करने के लिए संयुक्त-उद्यमों की स्थापना की नीति पर व्यापक रूप से अमल करते हैं। वे आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूँजी, तकनीकी-प्रवीणता और तकनीकी-कर्मियों का उपयोग करते हैं।

कुछ देशों ने, जिन्होंने गैर-मूँजीवादी विकास का मार्ग चुना है, विदेशी कंपनियों द्वारा भुनाफ़ा बाहर ले जाने पर रोक लगायी है और इसके साथ इन कंपनियों को उच्चतर कर भी देना पड़ता है।

जिन देशों ने आर्थिक-विकास के मूँजीवादी रास्ते को अस्वीकार कर दिया है, उनमें निजी उद्यमों का राष्ट्रीयकरण प्रायः काफ़ी व्यापक है। उदाहरण के लिए सीरिया ने अपने बड़े व मध्यम उद्यमों का बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीयकरण कर दिया है और कांगो के लोकतन्त्रराज्य ने बैंकिंग-व्यवस्था व बीमा-कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया है। लबानिया में राष्ट्रीयकरण समाजवादी दिशा की ओर संक्रमण को प्रोत्साहित करनेवाला मुख्य उपकरण है। यमन के लोकतन्त्रवादी गणराज्य, अंगोला, मोजम्बिक, अफ़ग़ानिस्तान, इथोपिया, मेडागास्कर (मलगासी) तथा अन्य देशों ने निजी उद्यमों का राष्ट्रीयकरण करके मूलगामी उद्यमों का क्रियान्वयन किया है। अपने पहले वाले रास्ते पर चलने हुए मई 1979 में

1. 'विकास-विकास में बहुराष्ट्रीय नियंत्रण', न्यूयॉर्क, 20 मार्च, 1978, पृ. 233।

अगोला की मन्त्रिपरिषद् ने सौ गं अधिक उन निजी उद्योगों व व्यापारिक उद्यमों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है जिनके स्वामी देश छोड़कर चले गये थे।

राष्ट्रीयकरण आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करने वाला कारक है। अल्जीरिया का सकल घरेलू उत्पादन 1973 के 3000 करोड़ दीनार से बढ़कर 1977 में 7000 करोड़ दीनार हो गया। 1978-79 के वित्तीय वर्ष के लिए इथोपिया का औद्योगिक उत्पादन 35.5 प्रतिशत बढ़ा। अदिम अबाया के धर्म-शोधन उद्योग में राष्ट्रीयकरण के बाद पाँच वर्षों में उत्पादन लगभग दुगना हो गया है।

सरकारी क्षेत्र की स्थापना और उसका स्वरित बृद्धिकरण—इजारेदारी आधिपत्य के विरुद्ध विकासशील देशों के संघर्ष और उनके स्वतंत्र आर्थिक-विकास के लिए सरकारी क्षेत्र अधिक-से-अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। इसका निर्माण विदेशी संपत्ति के राष्ट्रीयकरण व सरकारी उद्यमों की स्थापना, दोनों ही तरीकों से होता है। अल्जीरिया के 90 प्रतिशत औद्योगिक उत्पाद सरकारी-क्षेत्र में बनाये जाते हैं। उदाहरण के लिए, राज्य संपूर्ण खनन-उद्योग और ऊर्जा व काँच के सारे उत्पादन का नियंत्रण करता है। 1978 में 100 में अधिक संयंत्र व कारखाने सरकारी क्षेत्र में थे। सीरिया का लगभग 75 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन और कुल मिला कर इसकी राष्ट्रीय आय का 46 प्रतिशत राजकीय क्षेत्र से जुड़ा है। गिनी, संजानिया, यमन के लोकजनवादी गणराज्य और अन्य देशों में बहुत से विदेशी उद्यम, बैंक तथा व्यापारिक कंपनियाँ राजकीय संपत्ति बना दी गयी हैं।

सरकारी क्षेत्र के क्रियाकलाप आर्थिक-प्रक्रिया का नियंत्रण, सत्ताधर्मी का संकेंद्रीकरण, अति महत्वपूर्ण उद्योगों का निर्माण और राजकीय कोष में वृद्धि को सभव बनाते हैं। इस सबसे विदेशी पूँजी पर निर्भरता को कमजोर करने में सहायता मिलती है। उन सब देशों में, जिन्होंने विकास के गैर-पूँजीवादी रास्ते को चुना है, सरकारी क्षेत्र जनगण के हित में आर्थिक-विकास को प्रोत्साहित करता है। ये देश जैमे-जैमे इन दिशा में आगे बढ़ते हैं अर्थात् जब मजदूर वर्ग और अन्य मेहनतकश जनगण समाज को नेतृत्वकारी शक्ति बन जाते हैं तब सरकारी क्षेत्र समाजवादी स्वामित्व का आधार बन सकता है। इससे ज्ञात होता है कि साम्राज्यवादी विकासशील देश सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध क्यों हैं ?

आर्थिक समस्याओं का सामना करते हुए सरकारी क्षेत्र की प्रकृति व सामाजिक कार्य आवश्यक रूप से भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। जहाँ राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग मजबूत है, वहाँ राजकीय क्षेत्र अनिवार्यतः राजकीय पूँजीवाद होता है। लेकिन ऐसा होने पर भी, विकासशील देशों में भी राजकीय पूँजीवाद राज्य-इजारेदार पूँजीवाद विन्तुल नहीं है। विकासशील देशों में नये राज्यों की स्थापना में यह एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। इसका जग्य साम्राज्यवाद का विरोध करने का उन्ही उद्देश्य से होना है और आर्थिक-नवतन्त्रता के लिए

उनके सघर्ष में यह एक साधन है। सरकारी क्षेत्र के मजबूत होने से केवल उत्पादन सामर्थ्य ही नहीं बढ़ती है, बल्कि सारी सामाजिक-प्रक्रिया का क्रान्तिकरण होता है और यह श्रम-पूँजीवादी विकास के लिए आर्थिक आधार-शिला बनता है।

विकासशील देशों का औद्योगिकीकरण—औद्योगिकीकरण उपनिवेशी अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण, आर्थिक स्वतंत्रता की सुरक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन पर विजय पाने के लिए एक कारक है।

साम्राज्यवादी इजारेदारियों विकासशील देशों के औद्योगिकीकरण को रोकने के लिए बड़े सब कुछ कर रही हैं जो वे कर सकती हैं। वे इन देशों को औद्योगिक रूप से विकसित पूँजीवादी विपद के लिए लकड़ी चीरने वालों व पानी खींचने वालों के रूप में बनाये रखने की कोशिश कर रही हैं। पूँजीवादी अर्थशास्त्री, इसके अनुसार विकासशील देशों की सरकार व जनमण को यह समझाने की आशा कर रहे हैं कि उन्हें खनन-उद्योग व उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को वरीयता देते हुए कुछ विज्ञेय उद्योगों का ही विकास करना चाहिए।

साम्राज्यवाद व आंतरिक प्रतिक्रिया के विरुद्ध सघर्ष का तर्क विकासशील देशों के जनवादी क्रान्तिकारी नेताओं को अधिक-से-अधिक व लगातार औद्योगिकीकरण के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। औद्योगिकीकरण के बिना पिछड़े हुई क्षेत्रीय आर्थिक-संरचना तथा विदेशी आधिपत्य को समाप्त करना असंभव है और उत्पादन के समस्त क्षेत्रों में उच्च विकास-दर को पाना तथा गरीबी व गाँवों में जनसंख्या के आधिक्य से सफलतापूर्वक सघर्ष करना भी असंभव है। औद्योगिकीकरण से महत्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन होते हैं और उनसे मजदूर-वर्ग की गुणात्मक व सध्यात्मक वृद्धि होती है।

आज को दुनिया में विकासशील देशों के औद्योगिकीकरण का अर्थ है—अत्यधिक प्रभावी व प्रगतिशील औद्योगिक क्षेत्र तथा उत्पादन-वृद्धतियों पर आधारित राष्ट्रीय, भौतिक एवं तकनीकी आधारों का निर्माण, तकनीकी व आर्थिक स्तरों को ऊँचा उठाने के लिए आधुनिकतम वैज्ञानिक व तकनीकी उपलब्धियों का प्रयोग, आर्थिक पिछड़ेपन पर विजय और पुरानी उपनिवेशी-व्यवस्था की पुनर्संरचना। ये सब उपाय एक साथ मिलकर विकासशील देशों में विदेशी इजारेदारों के आधिपत्य तथा उत्पादन के सामंती रूपों को धारण में सीमित और पूरी तरह समाप्त करना संभव बनाते हैं। औद्योगिकीकरण आर्थिक-स्वतंत्रता पाने और सामाजिक-संरचना में सुधार करने का रास्ता है।

विकासशील देशों ने कुछ हद तक राष्ट्रीय-उद्योगों की स्थापना में सफलता प्राप्त कर ली है। 1971 की तुलना में 1979 में उनका कुल उत्पादन 5.6 गुना अधिक था जबकि विकसित पूँजीवादी देशों में यह 3.6 गुना अधिक था। उच्चतम विकास-दर ऊर्जा, धातु, रसायन और मशीन-निर्माण उद्योगों में थी।

बहुत भिन्न-भिन्न आर्थिक परिस्थितियाँ होने के कारण विकसशील देशों का औद्योगिकीकरण एक समान नहीं हो सकता। किसी एक देश में अर्थव्यवस्था के किसी एक विशेष क्षेत्र में प्रगति आर्थिक विकास के स्तर तथा प्राप्य प्राकृतिक-संसाधनों पर निर्भर है। लेकिन सभी विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण के लिए आधुनिक मशीनों पर आधारित विशाल कारखानों, सयनों आदि के निर्माण की जरूरत होती है।

औद्योगिकीकरण उत्पादक-शक्तियों के विकास को प्रोत्साहित करता है। किन्तु सिर्फ औद्योगिकीकरण विकासशील देशों के हितों की जरूरी रूप में पूर्ति नहीं करता है। उनके हितों की पूर्ति ऐसा औद्योगिकीकरण करना है जो सरकारी क्षेत्र को मजबूत बनाना है व निजी पूंजी को सीमित करता है, जो विदेशी इजारेदारियों की स्थिति को कमजोर करता है व राष्ट्रीय उद्योग को मजबूत बनाता है, जो उच्चतर जीवन-स्तरों को और अंत में गैर-पूंजीवादी रास्ते पर विकास को प्रोत्साहित करता है। समाजवादी दिशा की ओर उन्मुख देशों की अर्थव्यवस्थाएँ ठीक इसी दिशा में आगे बढ़ती हैं।

विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनका संचित-कोष सीमित होता है और उत्पादन के अधिकतर साधनों पर विदेशी इजारेदारियों का स्वामित्व होता है। इससे इजारेदारियों को मुनाफ़ा बाहर भेजने के माध्यम से विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय के एक बड़े हिस्से का दोहन करने का अवसर मिल जाता है। बहुराष्ट्रीय निगमों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के केन्द्र की गणनाओं के अनुसार यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो ये इजारेदार 1980 के दशक के अंत तक विकासशील व पूंजीवादी दोनों तरह के देशों में उत्पादन के 40 प्रतिशत भाग पर नियंत्रण करने लगेंगे।

विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण में इस तथ्य से भी बाधा आती है कि उनकी अर्थव्यवस्थाओं में पूर्व-पूंजीवादी संरचनाएँ अभी भी मौजूद हैं। इसी तरह जमींदारों, उनके नौकर-चाकर तथा जनसंख्या के अन्य मेहनत नहीं करने वाले हिस्सों द्वारा परजीवी उपभोग से राष्ट्रीय राजस्व में कमी आने से भी औद्योगिकीकरण में बाधा आती है। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण संकुचित घरेलू बाजार, अल्प प्रभावी भाग और सांस्कृतिक विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण के निम्न स्तर से भी औद्योगिकीकरण अवग्रह होता है।

विकासशील देशों के औद्योगिकीकरण की मुख्य समस्या वित्त-प्रवण के लिए स्रोत तलाश करना है। विदेशी निवेश, यदि वे सामान्य व्यावसायिक शर्तों पर किये जाते हैं और उनके साथ अन्य शर्तें नहीं जुड़ी होती हैं तो, एक तरीका है। लेकिन विकासशील देशों में उद्योग-निर्माण की वित्त-व्यवस्था के प्रमुख स्रोत घरेलू संसाधन हैं। इनमें विदेशी पूंजी व विदेशी व्यापारिक इजारेदारियों का राष्ट्रीय-

करण, प्राकृतिक संसाधनों का विकास, विश्व बाजार में उचित कीमत अथवा तकनीकी उपकरणों के बदले में अपने उत्पादों की विप्री, बजट-राशियों के उपयोग पर बठोर नियंत्रण स्थापित करके संसाधनों का संरक्षण और प्रगतिशील बराधान के द्वारा एकत्रित संपत्तिशाली वर्गों की आय का एक भाग—शामिल है।

समाजवादी देशों में सभी प्रकार का सहयोग, जिसमें मशीन व उपकरणों का आयात और विशाल उद्यमों के निर्माण व राष्ट्रीय कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए अनुकूल शर्तों पर सहायता शामिल है, विकासशील देशों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरह से आर्थिक-सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करता है।

कृषि-सुधार—भूमि-सुधार विकासशील देशों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का एक मुख्य साधन है और इसके बिना पिछड़ेपन को दूर करना असंभव है। प्रबंध के पूर्व पूंजीवादी रूप और इसके साथ भूमिहीन व भूमि प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाले लाखों-करोड़ों किसान, खाद्य समस्या, घरेलू बाजार के अभी तक संकीर्ण रहने और औद्योगिक विकास के समय-स्तर के अभी तक नीचे बने रहने के मुख्य कारण हैं। कृषि व उद्योग के समग्र स्तर को ऊपर उठाने तथा किसानों के जीवन-स्तर में सुधार करने का उपाय भूमि-स्वामित्व के पुराने रूप व भूमि-प्रबंध के कम उत्पादकता वाले रूपों की समाप्ति, किसानों को सारी भूमि का वितरण, कृषि को तकनीकी ढंग से ढँस करना और सहकारी व राजकीय क्लारों का संगठन है। कृषि संबंधों में परिवर्तन करने में विकासशील देश आर्थिक पिछड़ेपन पर विजय पाने, सचित निधियों के स्रोतों में वृद्धि तथा विस्तार करने और सामाजिक-आर्थिक प्रगति व आर्थिक-स्वतंत्रता की राह खोलने में समर्थ होंगे।

पिछले दो दशकों में अनेक विकासशील देशों ने भूमि-सुधारों का क्रियान्वयन किया है। उन देशों में, जिन्होंने विकास के पूंजीवादी रास्ते को चुना है, ये सुधार आवश्यक रूप से अधूरे व सीमित थे। अधिकांश भूमि अभी भी बड़े जमींदारों के हाथों में केन्द्रित है, जिन्हें किसान लगान देते हैं और अधिकांश किसान अभी भी भूमिहीन व भूमि पाने के इच्छुक हैं। भूमि-सुधार का अर्थ प्रायः सबसे खराब व कृषि के लिए अयोग्य भूमि को ऊँची कीमत पर खरीद कर जमींदारों स्वामित्व को नगण्य रूप में सीमित करना भर रहा है। यह भूमि पूंजीवादी ढंग की कृषि में लगे हुए संपत्तिशाली-वर्ग के हिस्से के द्वारा ही खरीदी जा सकती है जबकि दरिद्रतम किसानों को भूमि को अभी भी बेहद ज़रूरत है। व्यवहार ने दिखाया है कि कुछ विकासशील देशों में भूमि-सुधार के नाम पर जमींदारों की भूमि को आंशिक रूप में ही जप्त किया गया है और किसान उस भूमि के लिए सरकार को ऊँचा क्षति-पूर्ति-शुल्क देते हैं। पूंजीवाद की ओर उन्मुख विकासशील देशों का राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग महत्तमकण किसानों के हित में कृषि समस्या का समाधान करने में असमर्थ है।

लेकिन जिन विकासशील देशों में विकास का गैर-पूंजीवादी रास्ता चुना है,

उनमें स्थिति भिन्न है। उनमें से अनेक सामंजस्यपूर्ण भूमि-मुधारों में अत्यंत सु-गमन रहे हैं और वे सामंजस्यपूर्ण भूमि-स्वामित्व को गठन कर चुके हैं। कृषि-क्षेत्र में काम करने वाली विदेशी कर्मियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है या उन्हें सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया है और राज्य के आर्थिक व संपत्तात्मक दोनों ढांचे के समर्थन में कृषि सहायक समितियों को काफी दृढ़ तक विकसित किया गया है। उदाहरण के लिए, अल्जीरिया में 1962 में कृषि-कार्य की प्रथम अवस्था में विदेशियों की 20 लाख हेक्टर में अधिक भूमि 2000 राजकीय कर्मों व सहायक समितियों को दे दी गई। नवम्बर 1971 के आरंभ में देश ने 'कृषि-कार्य पर कानून' बनाया जिसने समस्त बिना जुनी भूमि को राजकीय संपत्ति बना दिया और निजी रूप से रखी जाने वाली भूमि के आकार को सीमित कर दिया। परिणामस्वरूप किसानों को 15 लाख हेक्टर भूमि मिली जिसने उन्हें कृषि-सहायक समितियों में संयुक्त होने में सहायता दी। अरबों के दशक के आरंभ में समस्त कृषि-योग्य भूमि के आधे से अधिक भाग को राजकीय व सहायक क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया गया था। यमन के लोक जनवादी गणराज्य ने मूलभूत भूमि-मुधारों को पूरा कर लिया है। मूलपूर्व अमीर, मुलतान तथा उनके मंत्रियों की भूमि व संपत्ति बिना किसी भी तरह के मुआवजे के जब्त कर ली गयी है और कृषि मजदूर, भूमि के भूखे व भूमिहीन किसानों में बांट दी गई है। 1979 के आरंभ में यमन में 39 उत्पादन-सहायक समितियाँ थी जिनका समस्त कृषि-योग्य भूमि के 75 प्रतिशत पर नियंत्रण था। इथोपिया में जमींदारों, पादरी-वर्ग और सम्राट व उनके परिवार की सारी जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है और उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया है। अन्य विकासशील देशों ने भी, जिन्होंने विकास के गैर-पूंजीवादी रास्ते को चुना है, मूलभूत भूमि-मुधारों को आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किये हैं।

कृषि-मुधारों का क्षेत्र व गति संबंधित देश की राज्य-शक्ति तथा सामाजिक-संरचना पर निर्भर होती है। किसी भी विकासशील देश ने अभी तक अपने भूमि-मुधारों को पूरा नहीं किया है अथवा कृषि-प्रश्न का पूरा समाधान नहीं किया है। फिर भी, जो कदम उठाये गये हैं, उन्होंने निश्चय ही जमींदारी-स्वामित्व को निर्वल किया है तथा मेहनतकश किसानों व कृषि-मजदूरों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाया है और कुछ देशों में मजदूर-वर्ग व किसानों के बीच गठबंधन को मजबूत किया है। राज्य-कार्यों के तंत्र का निर्माण और सहायक क्रामों का संपन्न वे प्रमुख तरीके हैं, जिन पर चलकर विकासशील देश आर्थिक विकास के गैर-पूंजीवादी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं।

सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों का विकासशील देशों के साथ सहयोग—विकासशील देशों में आर्थिक पिछड़ेपन तथा साम्राज्यवादी शक्तियों पर

निर्भरता के ऊपर विजय पाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने वाले आंतरिक कारकों के साथ बाहरी परिस्थितियाँ—मुख्य रूप से विश्व-समाजवादी व्यवस्था का प्रभाव, दूसरा प्रमुख कारक है। विश्व-समाजवादी व्यवस्था के देश विकासशील देशों को अधिक-से-अधिक आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। साम्राज्यवाद व नवउपनिवेशवाद के विरुद्ध तथा शांति के लिए संघर्ष में विश्व-समाजवादी व्यवस्था तथा राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन के समान हित इस सहयोग के वस्तुनिष्ठ आधार हैं।

भूतपूर्व उपनिवेशों व पराधीन राष्ट्रों के साथ आर्थिक संबंधों पर साम्राज्यवाद की इजारेदारी नष्ट हो गई है। इससे विकासशील देश अपनी आर्थिक-स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के गुणात्मक रूप से नये सिद्धांतों की स्थापना में समर्थ हो गये हैं।

पूंजीवादी विचारक समाजवादी देशों के साथ आर्थिक संबंधों के महत्व को और इस सहयोग तथा साम्राज्यवादी देशों, विकासशील देशों के साथ जिनके आर्थिक संबंध उन्हें पूंजीवादी रास्ते पर निर्देशित करने के लिए लक्षित हैं ताकि वे विकासशील देशों का शोषण जारी रख सकें, के नव-उपनिवेशवादी कार्यों के बीच के मूलभूत अंतर को मलिन करने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं।

समाजवादी व विकासशील देशों के बीच आर्थिक संबंध विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करते हैं। सोवियत संघ ने उन्हें जो कुल राशि दी है उसका 77 प्रतिशत उद्योग में निवेश किया गया है जबकि पूंजीवादी सहायता का सिर्फ 28 प्रतिशत इस कार्य में प्रयोग किया गया। साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपनी 'सहायता' का उपयोग आर्थिक व राजनैतिक दबाव डालने, अपनी इजारेदारियों के लिए अनुकूल स्थितियाँ बनाने और प्रगतिशील शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष में मदद करने के लिए करती हैं। विकासशील देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों में पूंजीवादी-शक्तियाँ नव-उपनिवेशी उद्देश्यों को आगे बढ़ाती हैं जबकि समाजवादी देश बराबरी के सहयोग के सिद्धांत में निर्देशित होने हैं।

समाजवादी देशों ने विकासशील विश्व को जो ऋण व सहायता प्रदान की है, वे उपनिवेशवाद की विरासत को मिटाने, ऋण पाने वालों की अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना करने और औद्योगिक-समूहों का निर्माण के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी सहायता प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। साम्राज्यवादी शक्तियों को उधारों से अलग, उनके साथ कोई राजनैतिक, सैनिक या आर्थिक शक्तें नहीं होती हैं। वे आर्थिक-स्वतंत्रता के लिए परिस्थितियों का निर्माण करते हुए प्रमुख रूप से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के सरकारी क्षेत्र को मजबूत करने में सहायता देने हैं। पूंजीवादी उधारों का उद्देश्य सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध निजी कंपनियों की स्थिति को मजबूत करना है। समाजवादी देश अनुकूल शर्तों पर

उधार देने हैं। सोवियत सघ 2-3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है जिसका पुनर्भुगतान प्रायः 12 वर्ष में करना होता है। पुनर्भुगतान उपकरणों की सुपुर्दगी के पूरा होने के एक वर्ष बाद शुरू होता है। इससे विकासशील देशों को नयी सुविधाओं को चालू करने तथा उनसे आय प्राप्त करने का समय मिल जाता है जिससे वे उधार व ब्याज का पुनर्भुगतान करने में ही समर्थ नहीं हो जाते हैं बल्कि उन्हें नि शुल्क पूंजी भी मिलती है। नियमतः उधार परंपरागत नियान्त्रण योम्य सामान अथवा नवनिर्मित उद्योगों के उत्पादों में चुकाया जाता है।

समाजवादी देश जो आर्थिक व तकनीकी सहायता देने हैं वह विकसमशील देशों की अर्थव्यवस्था के सरकारी क्षेत्र का निर्माण करने व उसे मजबूत करने, आर्थिक-विकास की दरों को बढ़ाने, साम्राज्यवादी प्रभारदारियों के विस्तार के विरुद्ध उनकी रक्षा करने और इसके साथ जीवन-स्तरों को ऊँचा करने तथा उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

समाजवादी देश अब एशिया, अफ्रीका व सातीनी अमेरिका के 60 से अधिक देशों को आर्थिक व तकनीकी सहायता देने हैं और 1500 करोड़ से अधिक की दीर्घकालीन उधार सहायता दे चुके हैं जिसमें 70 प्रतिशत से अधिक सोवियत सघ में दिया है। इन समाजवादी देशों ने 4400 से अधिक औद्योगिक उद्यमों व अन्य आर्थिक-परियोजनाओं के लिए (जिनमें 200 मशीन-निर्माण व धातु-समाधि करने के संयंत्र, 230 तेल-शोधन व रसायन उद्योग और कृषिजन्य उत्पाद, खाद्य व उप-भोग्य सामान बनाने वाले 1120 कारखाने शामिल हैं) वित्त-व्यवस्था की है। विकसमशील देशों में समाजवादी देशों की सहायता में जो सौह-धातु संबंध बने हैं या बन रहे हैं, वे तीन करोड़ टन इस्पात का वार्षिक उत्पादन करने हैं। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद् के सदस्यों ने जिन ऊर्जा-केन्द्रों को बनाने में सहायता दी है या दे रहे हैं, उनही स्थापित क्षमता अब 160 लाख किलोवाट से अधिक है। यह क्षमता इनही मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करने में समर्थ है जो प्रतिवर्ष 250 लाख टन तेल, बाजार में जिसकी कीमत अब 500 करोड़ डॉलर है, की बचत करेगी।

समाजवादी देश जिन उद्यमों के निर्माण में सहायता देने हैं, वे राज्य की पूरी संपत्ति बन जाते हैं। इससे आर्थिक-निर्माण की पूर्वापेक्षाओं का निर्माण होता है।

सोवियत सघ विकसमशील देशों के साथ पारस्परिक लाभदायक साधारण पर आर्थिक व तकनीकी सहयोग करता है। विकसमशील देशों को नयी आर्थिक-सहायता, मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के केन्द्रीय क्षेत्रों में प्राप्त होती है और इससे अधिक रोचकता एवं उत्कृष्टतर जीवन-स्तरों की प्राप्ति मिलती है। बरने में सोवियत सघ अपनी सहायता की बन्तुओं जैसे, अल्पीय खनिज धातु के सांद्रण, तेल, ईंधन, रेडियम, कार्बन, प्राकृतिक रबर, पट्टमन, चावल, चाय, कॉफी, कोका, तैल,

पत्र आदि प्रत्यक्ष करता है।

वैज्ञानिक तकनीकी क्षमियों व अन्य विशेषज्ञों और कुशल श्रमिकों के प्रशिक्षण में समाजवादी देशों की सहायता और इसके साथ तकनीकी-ज्ञान में उनकी साझेदारी भी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परस्पर आर्थिक सहायता परिपक्व के देश लगभग 4 लाख तकनीकी विशेषज्ञों के प्रशिक्षण में सहायता दे चुके हैं और लगभग 40 हजार युवा-जन समाजवादी देशों में उष्णार शिधा पूरी कर चुके हैं और लगभग इतने ही अध्ययन जारी रखे हुए हैं।

उनिवेशी निर्भरता में मुक्त हुए देशों को समाजवादी देश उनकी व्यापपूर्ण भागी के लिए राजनैतिक समर्थन ही नहीं दे रहे हैं बल्कि उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के आधारों की रचना व उनकी मजदूरी के लिए प्रत्यक्ष सहायता भी दे रहे हैं। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस में लियोनिद ब्रेझनेव ने कहा था—“अब यह बिल्कुल साफ है कि विश्व में वर्ग-शक्तियों के वर्तमान सह-संबंधों के रहने मुक्त हुए देश साम्राज्यवादी देशों के निर्दोषों का विरोध करने और व्यापपूर्ण अर्थानुसंग स्तर के आर्थिक-संबंधों को प्राप्त करने में पूरी तरह समर्थ है। यह भी साफ है कि शान्ति और जनपथ की रक्षा के सामान्य संबंधों में उनके पहले से ही काफी योगदान से और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाने की संभावना है।”¹

समाजवादी देश विकासशील देशों की सहायता उनकी रक्षा-सामर्थ्य को बढ़ाकर देने के लिए कर रहे हैं ताकि वे साम्राज्यवादी शक्तियों तथा उनके समर्थकों के आक्रमण और सैनिक दबाव का मुकाबला कर सकें। सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देश किसी प्रकार की विशेष सुविधा, राजनैतिक प्रभुता या सैनिक सहायता नहीं चाहते हैं। इसका अकाट्य प्रमाण अंगोला और इथियोपिया की घटनाओं से मिलता है जहाँ सोवियत संघ तथा क्यूबा की सहायता ने आक्रमण-कारियों की योजनाओं को विफल कर उन्हें बाधित करने की विजय कर दिया। यह सैनिक अन्तर्देशीय समसामयिकों के अतर्गत सोवियत संघ के बाधकों के अनुकूल ही नहीं है अन्तर्देशीय शान्ति व संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के भी अनुकूल है।

अंगोला की सार्वभौम सरकार के अन्तर्देशीय पर क्यूबा की सेना की उपस्थिति के साथ अंगोला की रक्षा करने में सोवियत सहायता भी एक निरपेक्ष सत्य माना जा सकता है। दोनो कारणों से ऐसी स्थिति में देश की स्वतंत्रता को मजबूत करने और उसकी क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा करने में सहायता दी है जबकि दक्षिण अफ्रीका के अफ्रीकावादी अब भी अपनी आक्रामक कार्यवाहियाँ जारी रखे हैं।

¹ एन० सी० ब्रिजनेव, 'सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस' शक्ति की रक्षा और युद्ध के विरोधियों के साथ वैज्ञानिक-सांख्यिक-सांख्यिक, सोवियत संघ, एप्रिल 1976, पृ० 221 (अंग्रेजी में)।

आकाश में अंगोसा गर बमबारी कर रहे हैं और मारपीटिया (जिन पर उन्हें ज़री भी अधिकार किया हुआ है और जिनका वे चीन-राज्य के लिए अर्द्ध-के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं) में नागरिक कर्मियों पर गोलाबारी कर रहे हैं।

दूसरा उदाहरण इथियोपिया को समाजवादी देशों की महापग है। 1978 में और आज, दोनों ही बार इस महापग ने ज़रीफ के मौल प्रदेन में राजनीतिक स्थिति को सामान्य बनाने में मदद की और अब भी मदद कर रही है।

अज़ीजा, एगिया और मानीनी अमरीका में राष्ट्रीय मुक्ति मंचों में मजबूत होना जा रहा है और नयी अवस्था में प्रवेश कर रहा है। विकासशील देशों के आन्तरिक मामलों में 'गोविपन हस्त-लेन' तथा 'गोविपन गाने' की कल्पित-रूप को स्वयं धारण-बिकना ने नष्ट कर दिया है। इन महापगों में प्रगतिशील कल्पित-रूप इस बात से पूरी तरह अज्ञान है कि ये कल्पित-रूप उन लोगों द्वारा मड़ी जाती हैं जिन्हें अपने विचारों को बढ़ाने के लिए बढ़ाने की जरूरत है ताकि वे जाति, समाजवाद तथा राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के विच्छेद मंचों करने और जिन देशों ने उपनिवेशी जुआ उतार फेंका है, उन देशों में राष्ट्रों के गोपन व नूटमार की नव-उपनिवेशी व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विकासशील देशों का अर्द्धों के रूप में इस्तेमाल कर सके।

विकासशील विश्व के सामने प्रस्तुत अत्यंत महत्वपूर्ण मापसों—उपनिवेशी विरामत के अंत, नव-उपनिवेशवाद की बेड़ियों में बाहर निकलने, आर्थिक विच्छेदन पर विजय पाने और अर्थव्यवस्था में उपनिवेशवाद की समाप्ति के कार्य को बढ़ाने के लिए समाजवादी देश मूलतः नये राजनीतिक तरीकों को प्रतिपादित करने में सक्रिय रहे हैं।

सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों ने राष्ट्रों के आर्थिक अधिकार व कर्तव्यों के संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर और नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक-व्यवस्था की स्थापना के घोषणापत्र की प्रगतिशील अंतर्वस्तु तथा साम्राज्यवाद-विरोधी दिशा का समर्थन किया है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 26वीं कांग्रेस में प्रस्तुत केन्द्रीय-समिति की रपट में इस पर बल दिया गया है कि अब से पार्टी विकासशील देशों के साथ सोवियत संघ के सहयोग को विकसित करने और विश्व-समाजवाद व राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के बीच मैत्री को मजबूत करने की नीति पर दृढ़ता से चलेगी। यह बताया जाना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इन दस्तावेजों में निहित सिद्धांतों का समर्थन करने से काफ़ी पहले ही समाजवादी देशों ने उन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस बीच साम्राज्यवादी शक्तियों की नीति विश्व-सूत्रीवादी अर्थव्यवस्था में अपने विशेष सुविधा-प्राप्त स्थान को सुरक्षित रखने, विकासशील देशों को इस व्यवस्था के भीतर बनाये रखने तथा उनके और अधिक मात्रा में शोषण की

दशाओं का निर्माण करने की ओर निर्देशित रही है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पुनर्संरचना सबसे पहले इस पर निर्भर है कि विकासशील देश आर्थिक क्षेत्र में नव-उपनिवेशवाद के विरुद्ध किस प्रकार सुसंगत सपनें करते हैं, अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी-सर्वोच्चता की रक्षा किस सुसंगत रूप में करते हैं और अपनी भूमि में काम करने वाली साम्राज्यवादी इजारेदारियों पर किस सुसंगत तरीके से नियंत्रण करते हैं।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई अस्थिरता और गतिहीनता

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में बढ़ती अस्थिरता तथा गतिहीनता पूँजीवाद के आम-संकट का एक विशिष्ट लक्षण है और यह पूँजीवाद द्वारा अपनी शक्तियों के पूर्ण उपयोग में असमर्थता में स्पष्ट होता है। यह साम्राज्यवाद के भीतर की एक आन्तरिक प्रक्रिया है, जिसका सारतत्त्व यह है कि पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन-संबंध अपने सापेक्ष प्रगतिशील चरित्र को खो चुके हैं और विकास के एक उपकरण की जगह सामाजिक प्रगति को अवरोध करने वाले प्रमुख कारक के रूप में बदल गये हैं। इजारेदारी आधिपत्य पूँजीवाद में अस्थिरता तथा गतिहीनता बढ़ाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उपादान है। उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व के साथ इजारेदारी के सभी रूप गतिहीनता की प्रवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं।

1. उत्पादन-दक्षताओं का स्थायी अपूर्ण-उपयोग

अपनी उत्पादन-शक्तियों के पूर्ण उपयोग में पूँजीवाद की असमर्थता औद्योगिक उद्यमों में स्थायी अपूर्ण-उपयोग के तथ्य से तीव्रता के साथ स्पष्ट होती है। पूर्व-इजारेदार पूँजीवाद तथा आरंभिक साम्राज्यवाद (प्रथम महायुद्ध से पहले) के समय में औद्योगिक-उद्यमों में श्यापक अपूर्ण-उपयोग केवल आर्थिक संकट के समय ही दिखनायी देना था। पूँजीवाद के आम-संकट के युग में यह पूँजीवाद का स्थिर एवं दीर्घकालिक लक्षण बन गया है और इसे आर्थिक-क्षम की सभी अवस्थाओं में—संकट व मंदी के समय तथा अर्थव्यवस्था की गतिवता व भागे बढ़ने के समय—देखा जा सकता है।

पूँजीवादी विश्व में उत्पादन-दक्षताओं का स्थायी अपूर्ण उपयोग इस तथ्य में चित्रित होता है कि तकनीकी प्रगति के द्वारा उत्पन्न प्रौद्योगिक-उत्पत्ति के विकास

के माप विदेशी व घरेलू बाजार का परिमोमन समानांतर रूप में होता है। वस्तुओं के विक्रय का सामना सापेक्ष रूप से सीमित प्रभावी माँग और बढ़ती हुई भ्रमशलीय प्रतियोगिता से होता है। विकास-दरों के ऊँचा होने के समय भी उत्पादन पूर्ण-क्षमता के 90 प्रतिशत से अधिक कभी-कभी ही होता है। उत्पादन की औसत 75-80 प्रतिशत रहती है जबकि कभी-कभी तो कुछ उद्योगों में उत्पादन 40-50 प्रतिशत ही रह जाता है।

दो महापुटों के बीच के सारे समय में अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस तथा अन्य पूँजीवादी देशों के उद्योगों में अपनी क्षमता के 50-66 प्रतिशत तक काम किया। दूसरे शब्दों में, पूँजीवादी विश्व के उद्योगों ने वास्तव में जितना उत्पादन किया, समान उत्पादन संयंत्रों की सहायता से वे डेढ़ गुना गे दो गुना तक अधिक निर्माण कर सके थे। आर्थिक संकट के समय अपूर्ण-उपयोग और भी ज्यादा था। सबसे बड़े पूँजीवादी देश अमरीका में दीर्घकालिक अपूर्ण-उपयोग विशेष रूप से राष्ट्रपंजनक रहा है, जहाँ कि अर्थव्यवस्था में उभार के समय भी उत्पादन कुल क्षमता से बहुत कम रहा। उदाहरण के लिए ब्रिग्स ससधान के अनुसार 1925-29 में उपलब्ध उपकरणों के सिर्फ 80-82 प्रतिशत का उपयोग हुआ। 1948-53 में अमेरिका के निर्माण-उद्योग की उत्पादन-दक्षताओं के 92-95 प्रतिशत और 1954-66 में 75-91 प्रतिशत सामर्थ्य का उपयोग हुआ। 1972-1973 के अपवाद के अलावा 1967 से 1975 तक के समय में अमेरिका के निर्माण-उद्योग में अपूर्ण-उपयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी। 1975 में औद्योगिक उपकरणों में 1966 के 91.1 प्रतिशत की तुलना में 73.6 प्रतिशत सामर्थ्य का उपयोग किया। 1975 में, जिस वर्ष उत्पादन में सबसे अधिक गिरावट दिखाई दी, कुछ के बाद सबसे कम 70.9 प्रतिशत सामर्थ्य का उपयोग हुआ। उसके वर्षों में उत्पादन धीरे-धीरे अधिक सामर्थ्य की ओर बढ़ा। लेकिन उद्योगों के उभार के समय भी (1977-78) उत्पादन-दक्षता का लगभग 17 प्रतिशत भाग बेचिक्य रहा।

विकास पूँजीवादी देशों के निर्माण-उद्योगों में 10-15 प्रतिशत और इसमें किए क्षमता का अनुपयोग प्रत्येक 7-10 वर्ष की अवधि में एक वर्ष के उत्पादन में प्रतिफल करता है।

अमेरिकन अर्थशास्त्री ए० एच० हानसेन ने बताया है—“विगत दो अर्थवर्षों के बीच राष्ट्रीय उत्पादन का मेखा सम्पूर्ण रोजगार के स्तर में 50 अरब डॉलर का रहा है।”

1 ए० एच० हानसेन, 'कुटोन्नत अर्थव्यवस्था : विकास और अक्षमता', द्रष्टु-संस्कृत संशोधन एवं प्रकाशन, न्युयॉर्क, 1964, पृ० 9।

उत्पादन-दक्षताओं का स्थायी अपूर्ण उपयोग पूंजीवादी पुनरुत्पादन को अवरोध करता है, क्योंकि इनके वापस-भुगतान की प्रक्रिया मंद व उत्पादन के साधनों पर की जाने वाली माँग कम हो जाती है तथा बाजार-शामर्ष्य गिर जाती है, जिनके फलस्वरूप पहले मानव-शक्ति और फिर उद्योगिता-वस्तुओं की माँग कम होने लगती है। इसके साथ मौद्रिक-पूँजी का उत्पादन-पूँजी में परिवर्तन और जमा पूँजी का नवीकरण कठिन हो जाता है जिससे नवीन उद्यमों के निर्माण व पचास उद्यमों के विस्तार की प्रेरणाएँ कम होने लगती हैं।

इस प्रकार पूँजीवाद में अंतर्निहित दो विरोधी प्रवृत्तियाँ—(जिन्हें लेनिन ने बनाया था)—उत्पादन-शक्तियों का तीव्र विकास और उनकी अभिवृद्धि में रुकावट—आज भी काम कर रही है। उत्पादन-दक्षताओं का स्थायी अपूर्ण-उपयोग, प्रौद्योगिक प्रगति और पूँजीवादी विश्व में इसके उपयोग को दक्षताओं के बीच अंतर्विरोध का सुस्पष्ट प्रमाण है।

पूँजीवादी विश्व में उत्पादन-दक्षताओं का स्थायी अपूर्ण-उपयोग आधुनिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के गतिहीन होने का सूचक है जो उत्पादन-शक्तियों के एक प्रमुख घटक अर्थात् उत्पादन के साधनों के व्यवस्थित रूप से कम उपयोग को सूचित करता है। इसके साथ यह स्थिर पूँजी के नवीकरण को मन्द करता है। यह पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में आंतरिक अस्थिरता का एक प्रमुख कारक है।

2. बहुसंख्य बेरोजगारी की पुरानी बीमारी

बेरोजगारी पूँजीवादी उत्पादन का अनिवार्य संगी है। प्रथम महायुद्ध से पहले बेरोजगारी प्रमुख रूप से आर्थिक-संकट के समय महत्वपूर्ण रूप में बढ़ती थी और अर्थव्यवस्था में उभार व चक्रीय पुनरुत्थान के समय कम हो जाती थी। लेकिन जैसे-जैसे पूँजीवाद का आम-संकट प्रकट होने लगा, बेरोजगारी पूँजीवादी पुनरुत्पादन के अर्थचक्र की सभी अवस्थाओं में अवश्यभावी हो गयी। उत्पादन-क्षमताओं के स्थायी रूप में कम क्षमता पर संचालन के साथ थप के दीर्घकालिक अल्प-उपयोग की प्रवृत्ति जुड़ी हुई है। ये दोनों, अपनी उत्पादन-क्षमताओं के सम्पूर्ण तथा प्रभावकारी उपयोग करने में आधुनिक पूँजीवाद की असमर्थता की सूचक हैं।

पूँजीवादी देशों के आधिकारिक आँकड़े बेरोजगारों की वास्तविक संख्याओं को प्रतिबिम्बित नहीं करते हैं क्योंकि इनमें सप्ताह के कुछ भाग ही में करने वाले या अंशकालिक काम करने वाले, शिफ्टा पूरी करके काम की तलाश करने वाले युवक और बेरोजगारी के लाभों को धी चूकने वाले मजदूर शामिल नहीं होते हैं।

औद्योगिक रूप से विकसित पूँजीवादी विश्व में आज बेरोजगारी की दर अत्यन्त ऊँची है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार ही 1978 में पूँजीवादी विश्व के देशों में बेरोजगारी की संख्या 150 लाख अथवा कुल सक्रिय श्रम-शक्ति के 5.5

प्रतिशत से भी अधिक थी। यह 1960 के दशक में औसत बेरोजगारी के स्तर से दुगने से भी अधिक है। अमरीका में, कामों की सख्या में वृद्धि के बावजूद, 80 के दशक के आरम्भ में बेरोजगारी बहुत विकट सामाजिक-आर्थिक समस्या बनी हुई थी। 1978 में अमरीका में बेरोजगारी की सख्या 65 लाख अर्थात् कुल सक्रिय श्रम-शक्ति का 6 प्रतिशत थी। पश्चिमी जर्मनी में 1974-78 के बीच लगभग 80 मजदूर तथा कार्यालय-कर्मचारी एक या दूसरी तरह से बेरोजगारी के शिकार हुए। जापान में 1978 में बेरोजगारी की दर युद्ध के बाद के उसके इतिहास में सबसे ज्यादा थी। सिर्फ उस वर्ष में पूरी तरह बेरोजगारी की सख्या में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह सख्या बढ़कर 12 लाख 60 हजार हो गयी।¹

बेरोजगारी श्रम-शक्ति के सभी भागों को प्रभावित करती है, विशेष रूप से सामान्य श्रमिकों व नौजवानों और ज्ञानीय भेदभाव के शिकार लोगों को प्रभावित करती है। साठ के दशक के उत्तरार्द्ध में अमरीका में नौजवानों के बीच बेरोजगारी की दर औसत से तीन गुना ज्यादा रही है। 1978 के अंत में, 16 व 19 वर्ष के बीच के 14 प्रतिशत से अधिक नौजवान बेरोजगार थे जबकि कुल बेरोजगारी की सख्या 6 प्रतिशत थी और बाले व अन्य रंगों के जनगणों के बीच बेरोजगारी की दर 34.6 प्रतिशत थी। इसके साथ कुछ बहुत विकसित पूंजीवादी देश नयी उच्च तकनीक वाले उद्योगों से जुड़े नये व्यावसायिक कार्यों के लिए कुशल मजदूरों को संगीन कमी का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति से जुड़े प्रौद्योगिक व सरचनात्मक परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करती है।

जो एक या दूसरे कारण से उत्तम शिक्षा पाने में असमर्थ रहे हैं, वे ही सिर्फ बेरोजगारी के शिकार नहीं हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त तथा उच्चस्तरीय कुशल विशेषज्ञों की एक बड़ी संख्या भी आज काम से बाहर है। 1979 में अमरीका में निम्न व्यावसायिक वर्ग में बेरोजगारों की सख्या की तुलना में उच्चतर शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञ अधिक सख्या में बेरोजगार थे। उच्चतर शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों में बेरोजगारी की दर अन्य देशों में भी इसी प्रकार बढ़ रही थी। अमरीका के समाचारपत्रों की रपट के अनुसार 1953-65 में बेरोजगारी से हुए नुकसान की राशि 500-700 अरब डॉलर अर्थात् प्रति वर्ष 39 से 54 अरब डॉलर के बीच थी। बेरोजगारी से मेहनतकारों की कुशलता की हानि भी होती है। यह श्रम-शक्ति का अवमूल्यन करती है, नये उद्योगों को कुशल-कर्मों प्रदान करने की समस्या को जटिल बनाती है और पूंजीवादी समाज में सामाजिक द्वंद्वों को तीव्र करती है।

पूँजीवादी उद्योगों में दीर्घकालिक अपूर्ण-उपयोग के समान दीर्घकालिक

1. श्रम-जीवनों की वार्षिक पुस्तक, 1978; अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघटन, 1978, पृ० 241-259 (संशुद्धि से)।

बेरोजगारी का तथ्य भी यह बतलाता है कि पूंजीवादी समाज की उत्पादक शक्तियों के उपयोग में आधुनिक पूंजीवाद असमर्थ है और यह उनके विकास में रकावट बन गया है।

3. अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण

आधुनिक पूंजीवाद की गतिहीनता और परजीविता की सबसे अनर्थकारी अभिव्यक्ति अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण और शस्त्र-दौड़ है। अर्थव्यवस्था के सैन्यीकरण से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि विज्ञान और तकनीक का प्रयोग जीवन-स्तर व काम की अवस्थाओं में सुधार करने तथा सम्पदा के निर्माण करने के लिए न किया जाकर सामूहिक-विनाश के साधन उत्पन्न करने के लिए किया जाने लगता है।

सैन्यवाद इजारेदारी आधिपत्य तथा साम्राज्यवाद के सारतत्व में निहित है। सेनिन ने लिखा है—“साम्राज्यवाद... अपनी मूलभूत आर्थिक विशेषताओं के कारण, शान्ति व स्वतंत्रता के लिए न्यूनतम पसंद और सैन्यवाद के अधिकतम व सार्वभौम विक्रम के द्वारा पहचाना जाता है।”¹ समाजवादी क्रांति से बरते हुए वितीय अल्पतंत्र (साम्राज्यवादी देशों में शासकीय विशिष्ट वर्ग) सैन्यकरण का उपयोग उत्प्रेरित व शोषित मेहनतकारों के आर्थिक-राजनीतिक संघर्ष को दबाने और अपनी सर्वोच्चता को दीर्घजीवी बनाने के लिए करता है।

दुमरी और साम्राज्यवाद के युग की विशेषता वितीय मुठों तथा देशों के बीच बाजारों, कच्चे माल के स्रोत और पूंजीनिवेश के क्षेत्रों के लिए तीखा संघर्ष होता है और यह संघर्ष महासंघर्ष व भिड़नों को बढ़ाता है।

सैन्यवाद, इजारेदार पूंजीवाद से आंगिक रूप से अंतर्निहित उसकी विशेषता है जो विश्व को विभाजित करने के लिए साम्राज्यवादी संघर्ष और महासंघर्ष-वर्ष एवं जनवादी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के सैनिक-दमन की दृष्टि से निर्धारित होता है। इस संबंध में सेनिन ने लिखा है—“आधुनिक सैन्यवाद पूंजीवाद का परिणाम है। अपने दोनों क्रांति में—पूंजीवादी देशों द्वारा अपने बाहरी संघर्षों में प्रमुख सैनिक-सक्ति के रूप में... और सर्वद्वारा के आर्थिक, राजनीतिक व दूर प्रसार के आंदोलनों के दमन के लिए साम्य-वर्ष के हाथ में शस्त्र के रूप में—यह पूंजीवाद की मूलभूत अभिव्यक्ति है।”²

सैन्यवाद के आर्थिक कारणों के कारण शस्त्र की दुमरी अभिव्यक्ति साम्राज्य-

1. डॉ० जॉर्ज सेनिन, 'साम्राज्यवाद और क्रांति का सैन्यीकरण', लंदन, पृष्ठ 28, पृ० 212 (85 की 3)।

2. डॉ० जॉर्ज सेनिन, 'साम्राज्यवाद और क्रांति का सैन्यीकरण', लंदन की सैन्यवादी-विरोधी क्रांति, लंदन, पृष्ठ 12, पृ० 122 (85 की 3)।

इ के युग में विशेष तीव्रता के साथ देखी जा सकती है। पूँजीवाद के आम-सकट अंतर्गत साम्राज्यवादी देशों का बढ़ता हुआ सैन्यवाद प्रमुख रूप से समाजवादी मुदाय और राष्ट्रीय मुनि आंदोलनों के विरुद्ध होता है। सैन्यवाद के विकास केवल राजनैतिक ही नहीं, आर्थिक कारण भी हैं—शस्त्र-दौड़ एक ऐसा तरीका जिससे इजारेदार आरध्वजनक रूप में धनी हो जाते हैं। यह उनके लिए एक ही सैन्य-उत्प्रेषण करता है जिनसे साधों का मुनाफा होता है। राज्य शीतरी का एक विशाल सैन्य-शक्ति के निर्माण के लिए राष्ट्रीय आय (प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष कर, राज्य-ऋण, सामरिक महत्व के कच्चा माल पर नियंत्रण आदि) के परिवर्तन में किया जाता है।

अर्थव्यवस्था के सैन्यकरण का परिणाम अस्त्र-शस्त्र और सेना पर खर्च में तीव्र वृद्धि होता है। उदाहरण के लिए नाटो-संघ के देश, बीस के दशक में पूरा विश्व सैनिक-उद्देश्यों के लिए जितना खर्च करता था, उससे 40 गुना अधिक खर्च करते हैं। संयुक्त के सामरिक-अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय सन्मान के अनुसार 1949-79 में नाटो देशों का सैनिक खर्च 2700 अरब डॉलर था। पूँजीवादी देशों में सैनिक खर्च लगातार बढ़ रहा है—अस्सी के दशक के आरंभ में यह खर्च 100 अरब डॉलर वार्षिक हो गया था। यह स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च से 150 गुना और शिक्षा पर खर्च से 50 गुना ज्यादा है। 1978 में अनेक नाटो-देशों ने अस्त्र-दौड़ पर 190 अरब डॉलर खर्च किये थे।¹

अमेरिका में, जो साम्राज्यवाद का प्रमुख राजनैतिक व सैनिक केन्द्र है, सैनिक-खर्च में तीव्र-वृद्धि एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण संदर्भ है। 1861-65 के गृह-युद्ध के समय और 1930 के दशक तक प्रत्यक्ष सैनिक खर्च प्रायः देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होता था। 1922-37 के बीच वार्षिक कुल खर्च एक अरब डॉलर से कम था। लेकिन दूसरे महायुद्ध के बाद के वर्षों में अमरीका के सैनिक खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जैसा कि इन संख्याओं में दिखाई देता है—1949 में 13.5 अरब डॉलर, 1968 में 79.6 अरब डॉलर और 1980 में 146.2 अरब डॉलर।² इसका अर्थ यह है कि पेंटागन का प्रतिव्यक्ति खर्च 1913 में 2.25 डॉलर, 1952 में लगभग 250 डॉलर और 1980 में 600 डॉलर था।

पूँजीवादी विश्व में सैनिक-तैयारियाँ अप्रत्याशित शांतिवादी स्तर पर पहुँच गयी हैं। अस्सी के दशक के आरंभ में विकसित पूँजीवादी देशों की सेनाओं में 140 लाख आदमी सेवाएँ दे, इनमें से एक करोड़ नाटो देशों की सेवाओं में

1. 'सैन्य व्यय 1978-79', भारत, पृ. 33-39।

2. 'संयुक्त राज्य अमरीका का सैनिक खर्च : विलोचन वर्ष 1981', पृष्ठ 70-71।

थे। इनके अलावा कितने ही लाखों व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सैनिक-उत्पादन में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए अमरीका के शस्त्र-उद्योग में 60 लाख व्यक्ति काम करते हैं। विकसित पूँजीवादी देशों के निर्माण-उद्योगों में काम करने वालों की कुल संख्या के लगभग एक-चौथाई सबसे श्रेष्ठ कार्यकुशल मजदूर और लाखों वैज्ञानिक व अनुभवी इंजीनियर सैनिक-औद्योगिक-ममूहों के लिए काम करते हैं।

साम्राज्यवादी देशों में विज्ञान के विकास को काफी हद तक प्रतिक्रियावादी आक्रामक उद्देश्यों के अधीन कर दिया गया है। अस्सी के दशक के आरंभ में अमरीका में शोध एवं विकास के कुल खर्च का लगभग 75 प्रतिशत सैन्यकरण में संबंधित था। युद्ध-उद्योग अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से पूँजी, कुशल श्रमिक, बच्चा माल तथा उपकरण अपनी ओर खींचता है।

सैन्यकरण विकास को मंद करने और उत्पादक शक्तियों को नष्ट करने वाला एक प्रमुख कारक है। यह तथ्य कि सैन्यवाद अर्थनीति व राजनीति का आगिक घटक बन गया है, इसका सुस्पष्ट प्रमाण है कि पूँजीवाद के अस्तित्व का बने रहना कुल मिलाकर मानवता की सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण हितों की दृष्टि से अगंगत है। ऐसा होने पर ही पूँजीवादी अर्थशास्त्री मेहनतकशों को यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण सिर्फ आर्थिक-संकट पर ही नहीं, पूँजीवाद के आम-संकट पर भी विजय पाने में सहायक हो सकता है। सिमोन कुजनेत्स, प्रसिद्ध पूँजीवादी अर्थशास्त्रियों में एक, कहते हैं कि युद्ध, चाहे सशस्त्र हो या शीत, उस देश को, आर्थिक-विकास के मंद होने के कारण जिसने अपनी आर्थिक स्थिति खो दी हो, ऐसी प्रेरणा दे सकता है कि उसके विकास की प्रवृत्तियाँ पहचान से परे बदल जाएँ। एल्विन एच० हानसेन भी लगभग यही दुहराता है जब वह यह दावा करता है कि सैनिक-खर्च ने अमरीका को गरीब नहीं बनाया है। यद्यपि सैनिक उत्पादन का विस्तार, विशेष रूप से आरंभ में, अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक प्रोत्साहित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप से सैन्यवाद, भारी मात्रा में भौतिक व मानवीय संसाधनों तथा राष्ट्रीय आय के अधिकांश भाग को सैनिक खर्चों में खींचकर विस्तारित पुनरुत्पादन के आधार को नष्ट करता है।

आर्थिक दृष्टि से सैनिक-उत्पादन और सशस्त्र सेनाओं का रख-रखाव सामाजिक-उत्पादन के एक बड़े भाग का अनुत्पादक व्यय है। सैनिक उत्पादन को असैन्य उद्योगों की कीमत पर बढ़ाया जाता है। इससे असैन्य उद्योगों की वृद्धि-दर कम हो जाती है। राष्ट्रीय आय का जो भाग सैनिक-उद्देश्यों पर खर्च किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था में पुनः नहीं लगाया जाता। सैनिक-उत्पाद उत्पादन के तत्त्वों की वस्तु अथवा मूल्य के रूप में क्षतिपूर्ति नहीं करते हैं। संसाधनों की भारी मात्रा को अनुत्पादक सैनिक-खर्चों में लगाकर सैन्यकरण

समग्र अर्थव्यवस्था की वृद्धि-दर को कम करने हुए संसाधनों के परिमाण को, जिसे उत्पादक-सचय के लिए काम में लाया जा सकता है, कम करता है। अल्पधिक सैन्यीकृत अर्थव्यवस्था वाले देशों में पूंजी-सचय और आर्थिक-विकास की दर कम हो रही है। पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों के दावे के विपरीत सैन्यकरण नागरिक-उत्पादन को हानि पहुँचाकर किया जाता है और इसका परिणाम जीवन-स्तरों में ह्रास की दीर्घकालिक बेरोज़गारी होता है।

शस्त्र-दौड़ अधिक ऊँचे सैनिक खर्च और इसके परिणामस्वरूप अधिक ऊँचे करों को जन्म देती है और ये कर उपभोक्ता क्रय-शक्ति में कमी करते हैं। साम्राज्यवादी देशों में विशाल सैनिक खर्च भारी बजट घाटा, राजकीय ऋणों में वृद्धि और कागज़ी-मुद्रा के बढ़ते निस्सरण को जन्म देते हैं। इसका परिणाम होता है—अल्पमूल्यन, अपूर्व मुद्रा-स्फीति और वास्तविक मजदूरी में कमी। मुद्रा-स्फीति की दर में मजदूरी की तुलना में कीमतें अधिक तेज़ी से बढ़ती हैं और इसका अर्थ यह होता है कि राष्ट्रीय आय में मजदूरी के भाग को कम करने की कीमत पर पूंजीपतियों के मुनाफे बढ़ते हैं। मुद्रा-स्फीति पूंजीपतियों के हित में राष्ट्रीय आय के पुनर्वितरण और मेहनतकशों को लूटने का एक तरीका है। परिणामस्वरूप, सैनिक-खर्चों का वित्त-व्यवस्था कैसे भी की जाए, अंत में उसका सारा भार मेहनतकशों के कंधों पर आता है। इसके साथ यह दुजारेदारों को धनवान बनने में भी सहायता देता है।

4. आर्थिक-संकट

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अस्थिरता एक अवधि बाद बार-बार आने वाली अति-उत्पादन के संकटों—जो बढ़ी हुई उत्पादक-शक्तियों पर नियंत्रण करने के लिए पूंजीवाद की असमर्थता एवं पूंजीवादी सामाजिक-संरचना की अल्पकालीनता में बहुत तीव्रता से स्पष्ट करते हैं, के रूपों में स्वयं को प्रकट करती है। इस संबंध में लेनिन ने लिखा है—“संकट यह दिखलाता है कि यदि भूमि, कारखाना, मशीन आदि पर कुछ छोटे से निजी स्वामियों का कब्जा नहीं हो जोकि जनगण की श्रम से साखों के मुनाफे निचोड़ते हैं, तो आधुनिक समाज समस्त मेहनतकशों की जीव दशाओं में सुधार करने के लिए अपार मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है।”¹

पूंजीवाद के प्रमुख अंतर्विरोध—उत्पादन की सामाजिक प्रकृति तथा इसके परिणामों को पाने के निजी पूंजीवादी रूप के बीच अंतर्विरोध में वृद्धि हो जाने के आम-संकट की अवस्था में, इसके आर्थिक-घटकों में परिवर्तन हो गया है। ये छोटे छोटे हो गये हैं, इसके परिणामस्वरूप संकट बार-बार व शीघ्र आने लगे हैं और

1. वी०आई० लेनिन, 'संकट की दिशाएँ'; सङ्कलित रचनाएँ, भाग 5, पृ० 92 (अंग्रेजी में)

अधिक गहरे व विनाशक हो गये हैं, तथा पूंजीवाद के आम-संकट से पहले की तुलना में अब सुधार के दौर में भी उत्पादन-वृद्धि कम सघन होती है।

दो महायुद्धों के बीच पूंजीवाद की आम-संकट की पहली अवस्था में पूंजीवादी विश्व में अति उत्पादन के तीन चक्रीय-आर्थिक-संकट आये—1919-20 में, 1929-33 में और 1937-38 में। पूंजीवाद के आम-संकट से पहले जहाँ दो संकटों के बीच सबसे लंबा अंतराल 12 वर्ष का था, आम-संकट की पहली अवस्था में यह घटकर 7-8 वर्ष हो गया।

पूंजीवाद के आम-संकट की पहली अवस्था में, आर्थिक-संकटों ने पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को काफी प्रभावित किया और उनकी विनाशक शक्ति पहले के आर्थिक-संकटों से बहुत ज्यादा थी। सबसे गंभीर संकट, जिसका पूंजीवाद ने अभी तक अनुभव किया है, 1929-33 का संकट था। बाद में आने वाली मंदी के साथ मिलकर यह 5-7 वर्ष तक रहा और इसने उत्पादक-शक्तियों का अभूतपूर्व विनाश किया। उदाहरण के लिए अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में 202 धमन-भट्टियाँ तोड़ी गयीं। इसके साथ अमरीका में 104 लाख एकड़ में कपास नष्ट की गयी और 64 लाख सूअरों की हत्या की गयी।

दूसरा महायुद्ध शुरू होने के पहले के समय के समान युद्ध-बाद के वर्षों में भी पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था बार-बार आर्थिक-संकटों से प्रभावित हुई। युद्ध-बाद का पहला संकट 1948-49 में आया जिसने मुख्य रूप से अमरीका तथा कनाडा की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया और इन देशों में उत्पादन क्रमशः 18.2 व 12.3 प्रतिशत कम हो गया। चूंकि युद्ध-बाद के आरंभिक वर्षों में अमरीका व कनाडा पूंजीवादी विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादों के आधे से अधिक भाग का उत्पादन करते थे, अतः उनके उत्पादन में कमी से समस्त पूंजीवादी विश्व का औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित हुआ।

बाद के वर्षों में विश्व-पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और अधिक अस्थिर हो गयी। 1957-58 के आर्थिक-संकट के समय आठ देशों—अमरीका, कनाडा, जपान, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस में उत्पादन का सम्पूर्ण ह्रास हुआ और इसके बाद पूंजीवादी विश्व में नयी आर्थिक उपलब्धता हुई।

1974-75 का विश्व-आर्थिक-संकट युद्ध-बाद के पूंजीवादी पुनरुत्पादन में कुछ विशेष स्थान रखता है। इसने सभी विकसित पूंजीवादी देशों को प्रभावित किया और इसकी गहराई व तीव्रता मार्च 1930 के दशक की मंदी से तुलनीय थी। युद्ध-बाद की अर्थव्यवस्था में उन्नत अति-विकसित राजकीय एकाधिकारी अर्थव्यवस्थाकारी उपलब्धता से द्वित्व गयी। 1975 के दूनों अनुपात में जपान में 20.2, फ्रान्स में 15.3, जर्मनी में 14.8, इटली में 13.5 और ब्रिटेन में 10.6 प्रतिशत उत्पादन का ह्रास हुआ। उत्पादन-कटौती और क्षमता में भारी कम उत्पादन के

परिणामस्वरूप बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई। अधिभूत धोकड़ों के अनुसार 1975 के मध्य में विश्वमिल पूंजीवादी देशों में 150 लाख व्यक्ति पूरी तरह बेरोजगार थे। इस मश्या में वे अपजीभूत बेरोजगार शामिल नहीं हैं, जिन्होंने किसी प्रकार के काम पाने की सारी आशा छो दी है। बेरोजगारी ने विदेशी मजदूर, राष्ट्रीय अल्प-संख्यक तथा बृद्ध व नौकरवालों पर विशेष रूप से कठोर प्रहार किया।

1974-75 के विश्व-आर्थिक-संकट और 1980 में शुरू हुए नये गभीर संकट ने इसका और अधिक विश्वमनीय माध्य प्रस्तुत किया कि पूंजीवादी सिद्धांत पूंजीवाद के अनगंत आर्थिक-संकटों को समाप्त करने की आशा नहीं रख सकते। इस संकट ने विश्व-पूंजीवादी अव्यवस्था में निरंतर बढ़ती अस्थिरता का भी और अधिक विश्वमनीय प्रमाण प्रस्तुत किया है। मुधारवादियों तथा पूंजीवादी विचारकों द्वारा गढ़ा गया एक प्रमुख मिथक—यह कि वर्तमान पूंजीवाद संकटों का निवारण करने में समर्थ है—घटित हो गया है। पूंजीवाद की अस्थिरता अधिक-से-अधिक प्रकट होनी जा रही है।

5. बढ़ती हुई मुद्रा-स्फीति और तीव्र वर्ग-मघपं

मुद्रा-स्फीति, जो आर्थिक-विकास की बढ़ती अस्थिरता की एक बहुत विशिष्ट अभिव्यक्ति है, वर्तमान में पूंजीवाद की एक प्रमुख समस्या है। पहले मुद्रा-स्फीति मुख्य रूप से युद्ध और युद्ध-बाद की आर्थिक-अव्यवस्था में बहुत तेजी से बढ़ती थी, आर पूंजीवादी उत्पादन-शक्ति की हर अवस्था में मुद्रा-स्फीति की दर अत्यधिक ऊंची है।

मुद्रा-स्फीति सामान्यतः बजट-घाटा से उत्पन्न होती है। अब पूंजीवादी राज्य कर, श्रम आदि के द्वारा अपने बढ़ते खर्चों को पूरा करने में असमर्थ होकर, विनियत: युद्ध और आर्थिक उथल-पुथल के बाद, अत्यधिक मात्रा में कागजी-मुद्रा छापने लगता है, तब परिणामस्वरूप यह मुद्रा स्वर्ण, वस्तुएं व विदेशी-मुद्राओं की तुलना में तेजी से कीमत खोने लगती है। उत्पादन में गिरावट के कारण, अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक जरूरत से बहुत अधिक कागजी-मुद्रा से मुद्रा-वितरण की प्रणालियाँ अति-मनुष्य हो सकती हैं, जिसका अर्थ यह होता है अतिरिक्त बैंक-मुद्रा छापे बिना भी धन की कीमत कम होने लगती है। पूंजीवाद के आम-संकट और इसके अंतर्विरोधों की संपूर्ण-वृद्धि के समय, जब स्वर्ण को वितरण से हटा लिया जाता है और उधार धन स्वर्ण से परिवर्तनीय नहीं रह जाता है, मुद्रा-स्फीति साधारण और दीर्घकालिक हो जाती है।

पूंजीवाद के आम-संकट के समय मुद्रा-स्फीति को प्रोत्साहित करने वाले बहुत-से कारक सक्रिय हो जाते हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली है सैन्यवाद, जो युद्ध के समय और युद्ध-बाद की आर्थिक दुर्व्यवस्था में ही नहीं, शांतकाल में पूंजीवादी अर्थ-

व्यवस्था के सामान्य विकास के समय भी मुद्रा-स्फीति के तंत्र को प्रोत्साहित करना है। शस्त्र-दौड़ सैनिक-उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय आय के अनुत्पादक उपभोग को और सामाजिक-मपदा के एक भाग की प्रत्यक्ष हानि को बढ़ाती है। शस्त्र-दौड़ के कारण शस्त्र-उत्पादक क्षेत्रों में और सैनिक-सेवा में लगे व्यक्तियों के पाम अधिक-से-अधिक धन जाने लगता है। इसका परिणाम होता है किसी प्रकार के अनुकूल वस्तु-समर्थन के बिना ही वाण्यजी-मुद्रा की राशि में वृद्धि। उच्चतर सैनिक-व्यय पूंजीवादी देशों के बजट-घाटा और बढ़ते हुए राज्य-ऋणों का प्रमुख कारण है। कर और ऋणों के अतिरिक्त मुद्रा-स्फीति सैनिक-व्ययों के लिए वित्त-व्यवस्था का एक तरीका है।

बढ़ती मुद्रा-स्फीति आधुनिक पूंजीवादी विश्व की विशेषता है जैसाकि निरंतर चढ़ती कीमतों और तेजी से दौड़ती मुद्रा-स्फीति (जिसे के समय कीमतों तेजी से उत्तरोत्तर बढ़ती हैं) से स्पष्ट होता है। उत्पादन में गिरावट और बढ़ती बेरोजगारी (जिसे अब गतिहीनता कहा जाता है) के साथ मुद्रा-स्फीति 1960 के दशक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नयी परिघटना हो गयी है। 1974-75 के संकट के समय यह प्रवृत्ति विशेष रूप से स्पष्ट थी जबकि उत्पादन में हास व बेरोजगारी में वृद्धि के साथ कीमतों व मुद्रा-स्फीति में भी वृद्धि हुई थी। आज इजारेदारों की नीतियाँ ही, आर्थिक-संकट के दिनों में, कीमतों में वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं क्योंकि संकट के दिनों में भी वस्तुओं के मूल्यों को उच्च-स्तर पर बनाये रखने के लिए वे राज्य की सहायता-प्राप्त अनेक उपायों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ आर्थिक-संकट को नियंत्रित करने के लिए पूंजीवादी राज्य द्वारा उठाये गये कुछ कदम भी उच्चतर कीमतों को प्रोत्साहित करते हैं।

मुद्रा-स्फीति का पूंजीवादी पुनरुत्पादन पर भारी प्रभाव होता है। एक तरफ यह कुछ हद तक उत्पादन की गति को तेज करती है लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक-संकट को भी बढ़ावा देती है। मुद्रा-स्फीतिजन्य तेजी के समय निम्न अतिरिक्त मुनाफ़ा कमाने व निवेश में वृद्धि करने के लिए अपने उत्पादों की कीमत बढ़ा देते हैं। इससे उत्पादन के साधनों के बाजार का विस्तार व उत्पादक-पूँजी का संचय होने लगता है, परिणामस्वरूप उत्पादन के साधनों तथा उपभोगता उपकरणों का अधिक उत्पादन होता है। फिर भी राज्य-इजारेदार पूंजीवाद के उपायों की व्यवस्था मेंहनसकणों की ऋण-शक्ति बढ़ाने में सहायक नहीं होती। परिणामस्वरूप मुद्रा-स्फीति उत्पादक-पूँजी के संचय को सुविधापूर्ण बनाते और उत्पादन व अन्तिम उपभोग के बीच अंतर को बढ़ाते हुए पूंजीवादी-पुनरुत्पादन के अंतर्विरोधों को तीव्र करती है। इस प्रकार लगातार जारी मुद्रा-स्फीति, आर्थिक-सामाजिक

को तीव्र करते हुए पूंजीवादी-पुनरुत्पादन की अस्थायी प्रेरक शक्ति की कमजा अवरोध बन जाती है।

मुद्रा-स्फीति का तारनसव यह है कि इसमें मजदूर-वर्ग और सारे मेहनतगर्जों

की कीमत पर प्रभावी मांग-व्यय के हित में राष्ट्रीय आय का अनुप्रेषण शामिल है। नाममात्र की मजदूरी की तुलना में कीमतों ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। वास्तविक मजदूरी में ह्रास के समानुपात में पूँजीवादी उत्पादन की लागत में ह्रास होता है, इसमें मेहनतकों के शोषण में वृद्धि होती है। मुद्रा-स्फीति शोषण का एक छुपा हुआ तरीका है। इसका प्रयोग एक पूँजीपति व्यक्ति नहीं, बल्कि राज्य-तंत्र की सहायता से पूँजीपति-वर्ग करता है। इसके साथ अपने लाभ के लिए पूँजीवादी राज्य, मुख्य रूप से मेहनतकों को हानि पहुँचाने हुए मुद्रा-स्फीति के द्वारा अनेक वस्तुओं को वितरण से हटा लेता है। मुद्रा-स्फीति का भार पेंशन-न्यायताओं को शामिल करते हुए सभी मेहनतकों के कंधों पर आना है क्योंकि कीमतों में वृद्धि के बावजूद पेंशन या तो पुराने स्तर पर रखी रहती है या कीमतों की तुलना में उतनी ज्यादा और उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है।

मन्तर के दशक के बाद मुद्रा-स्फीति की दरें बहुत बढ़ गयी हैं और कीमतों में तीव्र वृद्धि एक स्थायी परिपटना बन गयी है। 1974-75 का आर्थिक संकट विशेष रूप से बाद की गहरी व दीर्घकालिक गतिहीनता की विशिष्टता लगभग सभी खरूरी वस्तुओं में जैसे खाद्य-पदार्थ व रोजमर्रा की सेवाओं की कीमतों में उच्चतर वृद्धि थी। उदाहरण के लिए 1979 में आवश्यक वस्तुओं की कीमत अमरीका में 80, कनाडा में 90, ब्रिटेन में लगभग 200, फ्रांस में 100, इटली में लगभग 200, जापान में 100 से अधिक और जर्मनी में 70 प्रतिशत अधिक बढ़ी।¹ नाममात्र की मजदूरी की तुलना में कीमतों में वृद्धि बहुत तेज थी और युद्ध के बाद के वर्षों में औद्योगिक रूप से विकसित देशों में मजदूर-वर्ग की त्रय-शक्ति में ह्रास हुआ। यू० एस० न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार अमरीका में 1977-78 में ही उपभोक्ता वस्तुओं की खुदरा कीमतों में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई। दूसरे शब्दों में 1977 में अमेरिकियों ने त्रय मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए 71 डॉलर खर्च किये थे, उसी के लिए 1978 में उन्हें 111 डॉलर खर्च करने पड़े।²

मुद्रा-स्फीति पूँजीवादी देशों में लाखों मनुष्यों की आर्थिक स्थितियों व विगाहनी है और उनके भविष्य पर संदेह की छाया डालती है। मेहनतक पूँजीवादी राज्यों द्वारा किसी तरह के वेतन-नियंत्रण से जब उपभोक्ता वस्तुओं में कीमत लगातार बढ़ रही हो तब 'मजदूरी-जाम' की कोशिशों से—छास तौर चिहित होते हैं।

मुद्रा-स्फीति अब मुद्रा-संकट के, जो स्वयं को राष्ट्रीय मुद्रा के अवमूल्यन का अधिकांश पूँजीवादी देशों द्वारा अनुभव किये जाने वाले व्यापार व भुगतान

1. मुख्य आर्थिक संदर्भक, जनवरी, 1980।

2. यू० एस० न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, मार्च 13, 1978।

विगड़ने संयुक्त के रूप में प्रकट करना है, मगरागर विभिन्न श्रेणियों के कारण तीव्र हो रही है। पूँजीवादी सरकारें, मुख्य रूप से मेहनतकशों के मूलभूत हितों की कीमत पर अपने आर्थिक संसाधन व विदेशी साधनों तथा राज्य व अर्थशास्त्र के बीच मौद्रिक-संयुक्त करने की कोशिश कर रही है। मेहनतकशों के लिए इसका अर्थ है नती कठिनाइयों क्योंकि इन नीतियों में मजदूरी पर रोक और उत्पादन में कटौतियाँ शामिल होती हैं।

आर्थिक अस्थिरता के अन्तर्गत, पूँजीवाद के आम-मार्ग की वर्तमान अवस्था की विरोधता पूँजीवादी राजनीति-व्यवस्था में अमूल्य अस्थिरता भी है। पूँजीवादी देशों में सरकारों के बार-बार परिवर्तन साधारण बात है। संघीय बहुमत, जिन पर शासकीय विनिष्ठ बर्तनियमन: विचार्य करना है, साधारणत: महत्वहीन और अविश्वसनीय हो गया है।

आश्चर्य की बात नहीं है कि आधुनिक पूँजीवादी राजनीति शास्त्री पूँजीवादी राजनीतिक-व्यवस्था में सौर-प्रचलित अविश्वास को दूर करने की आवश्यकता का प्रायः बढ़ते रूप में उल्लेख करते हैं। जुलाई, 1979 में तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने अमरीका की स्थिति के बारे में यह कहा था—“यह विश्वास का संकट है। यह ऐसा संकट है जो हमारी राष्ट्रीय इच्छा-शक्ति के प्राण-तत्व, ठीक हृदय और आत्मा पर प्रहार करता है “और अमरीका की राजनीतिक-सामाजिक बुनावट को नष्ट करने की धमकी दे रहा है।”

विगड़ती हुई जीवन-शर्तों और मुद्रा-स्थिति व आर्थिक संकट के तारे भार को मेहनतकशों के कंधों पर डालने की पूँजीवादी इजारेदारों की इच्छा ने पूँजीवादी विश्व में मेहनतकशों के मजबूत प्रतिरोध को बढ़ाया है। आधुनिक पूँजीवादी समाज के आर्थिक-सामाजिक मुद्दों का सामना करने में पूँजीवादी देशों की सरकारों की असमर्थता ने वर्गीय अंतर्विरोधों को तीव्र कर दिया है।

हड़तालें मेहनतकशों के असंतोष का एक प्रमुख संदर्शक हैं। पृष्ठ 77 पर दी गयी सारणी उनकी वृद्धि को स्पष्ट करती है।

1970 के दशक में हड़तालों के प्रमुख संकलन, उनका बेहतर संगठन और व्यापक चरित्र थे। मेहनतकशों द्वारा अधिन-से-अधिक कार्यवाहियों की गयीं, जिनमें एक उद्यम के ढाँचे से आगे बढ़कर समस्त उद्योगों को घेरने वाली आर्थिक-मार्गें शामिल थी और वे राजनीतिक कार्यवाहियों के रूप में विकसित हो गयीं। शोषण के विरुद्ध प्रतिवाद, इजारेदारी आधिपत्य के खिलाफ तथा आधारभूत सामाजिक-आर्थिक सुधारों के लिए संघर्ष का एक संघटक हिस्सा हो गया। 1970 के दशक में सभी हड़तालों हुईं और उनमें समाज के विभिन्न क्षेत्र व्यापक रूप में

सारणी-3

प्रमुख पूंजीवादी देशों में हड़तालें

वर्ष	हड़ताओं की संख्या	हड़तालियों की संख्या	हड़ताल के मानव-दिनों की संख्या
1970	21,456	12,788,000	110,570,000
1971	24,585	15,974,000	93,847,000
1972	21,588	14,138,000	87,193,000
1973	25,870	17,702,000	74,204,000
1974	29,051	20,106,000	106,233,000
1975	23,518	22,988,000	87,286,000
1976	23,193	29,420,000	88,960,000
1977	23,479	14,148,000	68,705,000
1978	33,840	25,254,000	99,262,000

स्रोत—थ्रम-आईडों की वापिसी—1978, संयुक्त राष्ट्रसंघ 1979

शामिल हुए। मजदूर-वर्ग की शक्ति तथा प्रतिष्ठा बढ़ी, साथ ही मेहनतकारों के हितों तथा वास्तविक राष्ट्रीय हितों के लिए संघर्ष के हरावल दस्तों के रूप में उसकी भूमिका भी बढ़ी।

हड़ताली कार्यवाहियों की निरन्तरता एवं बढ़ता हुआ व्यापक चरित्र, मेहनतकारों की अधिक बढ़ी एकता, संघर्ष के रूपों की विविधता और राजनैतिक दिशावाली नयी माँगों का उठाया जाना—1970 के दशक में हड़ताली-आन्दोलन के ये महत्वपूर्ण घटक थे।

हड़तालियों ने वेतन में कटौती के बिना काम के कम घंटों, पूरी मजदूरी के बराबर बेरोजगारी भत्ते, प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी आदि की माँग की। शस्त्र-निर्माण करने वाले उद्योगों को नागरिक उत्पादन में बदलवाने के लिए मेहनतकारों का आन्दोलन बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ सार्थक रूप में बढ़े हुए नये काम ही उत्पन्न नहीं करेगा बल्कि शस्त्र-शोध पर भारी मात्रा में खर्च किये जाने वाले संसाधनों में कुछ हद तक कटौती करेगा ताकि उनका उपयोग जनगण की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में किया जा सके।

राज्य-इजारेदार पूंजीवाद का विकास

राज्य-इजारेदार पूंजीवाद का जन्म और विवास, पूंजीवाद के आम-सकट तथा पूंजीवादी विश्व की राजनीति; अर्थनीति वव सामाजिक-संरचना में बहुत व्यापक परिवर्तनों से अभिल्ल जुड़े हुए हैं। राज्य-इजारेदार पूंजीवाद स्वयं को, नयी विश्व-स्थिति—दो व्यवस्थाओं के बीच वर्तमान सघर्ष की दशाओं तथा वैज्ञानिक-प्रौद्योगिक क्रांति के अनुकूल ढाल रहा है।

1. इजारेदार पूंजीवाद का राज्य-इजारेदार पूंजीवाद के रूप में विकास

पूंजीवाद के आंतरिक नियमों के परिणाम-स्वरूप इजारेदार पूंजीवाद ने पहले महायुद्ध के समय राज्य-इजारेदार पूंजीवाद के रूप में, जो इसकी अंतिम अवस्था—साम्राज्यवादी अवस्था—की विशेषता है, विकसित होना शुरू किया।

साम्राज्यवाद के अपने अध्ययन में लेनिन ने यह स्थापित किया कि पूंजीवाद अहस्तक्षेपकारी पूंजीवाद से इजारेदार-पूंजीवाद की ओर तथा इजारेदार पूंजीवाद से राज्य-इजारेदार पूंजीवाद की ओर बढ़ गया है। इजारेदार पूंजीवाद तथा राज्य की संयुक्त शक्ति राज्य-इजारेदार पूंजीवाद की विशेषता है।

पूंजीवादी राज्य अर्थनीति या अर्थव्यवस्था में कभी विमुक्त नहीं रहा है, यद्यपि पूंजीवादी विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की प्रकृति और क्षेत्र एक समान नहीं रहे हैं। इजारेदार पूंजीवाद ने पहले की अवधि में राज्य मौद्रिक-व्ययन, उधार और ऋणों की व्यवस्था के द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना था। राज्य ने पूंजीगतियों को भू-क्षेत्र और आर्थिक सहायता दी तथा नैतिक सघर्ष, शस्त्रागार, रेल एवं संचार-मुद्रिणाओं के निर्माण के लिए प्रायः विश्व-प्रवाह किया। फिर भी, तब अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप घटा था।

जा था और अर्थव्यवस्था के वैयक्तिक-क्षेत्रों को ही प्रभावित करता था। मुक्त तंत्रियता तथा पूंजीवादी उत्पादन की विद्यारी व असंबद्ध प्रकृति, पूंजीवादी-वस्था के कार्य करने की तत्कालीन दशाओं को बनाये रखते हुए, राज्य की थिक भूमिका को सीमित करती थी। पूंजीपति राज्य से पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता ले की आशा रखते थे, जिसे (उनके शब्दों में) 'राज का प्रहरी' बनने तक सीमित न जा पाहिए।

साम्राज्यवाद के युग में और विशेष रूप से पूंजीवाद के आम-सकट के समय राज्य का हस्तक्षेप संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैल गया है तथा व्यवस्थित महारा हो गया है। आधुनिक राज्य अनेक आर्थिक कार्य करता है और स्वयं एक शक्तिशाली आर्थिक ताकत हो गया है। यह पूंजीवादी-युनरत्थान की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करता है तथा समस्त उद्योगों में उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी है। अर्थव्यवस्था में इसका स्थान बड़े मालिक, उपभोक्ता, ऋणदाता व कर्जदार के है।

साम्राज्यवाद के युग में इजारेदार पूंजीपति-वर्ग सारे समाज में प्रबलशक्ति न गया है। पूंजीपति-वर्ग के आंतरिक प्रतियोगी लक्ष्य में राज्य की तटस्थता राज्यतंत्र में शासकीय विक्षिप्त वर्ग के आधिपत्यवाद में बदल गयी है जो बड़े वृत्तीय पूंजीपतियों के हितों की उत्साह के साथ रक्षा करता है। इस प्रकार राज्य इजारेदार पूंजीपति-वर्ग के कारोबार की व्यवस्था करने वाली समिति बन गया है।

पूंजीवादी-इजारेदारियों और राज्यतंत्र मुख्य रूप से निजी सघों के द्वारा चलकर एक व निकटता से अंतर्भूत हो गये हैं। इन सघों में सरकारी मंत्रियों सहित उच्च-अधिकारी ध्यापारिक दुनिया से अपने सम्बन्धों को मजबूत करते हैं और निगमों के बोर्डों में साध के पद प्राप्त करते हैं। इजारेदार ऐसे उच्च अर्थनिक अधिकारियों को, जो राज्य-तंत्र के रहस्यों से भली प्रकार परिचित होते हैं और सरकारदार तरीके से उसे प्रभावित करने में समर्थ होते हैं, शीघ्रता से नौकरी देते हैं। इससे भी आगे इजारेदार, जो राज्यतंत्र की बड़ी हुई आर्थिक-राजनीतिक शक्ति में अच्छी तरह परिचित हैं, महत्त्वपूर्ण सरकारी पदों पर बन्धा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने सेवकों के माध्यम से राज्य-तंत्र के जाल में घुस जाते हैं। राज्य-तंत्र को प्रभावित करने के लिए निगम विविध प्रकार के ध्यापारिक-समूहों, जन-संगठनों और पूंजीवादी राजनीतिक दलों के अधिकारियों का प्रयोग करते हैं। निजी सघों के अलावा राज्य के आर्थिक क्रियाकलाप भी राज्य व इजारेदारों के परस्पर विलयन के महत्त्वपूर्ण रूप हैं।

राज्य-इजारेदार पूंजीवाद का सारतत्त्व यह है कि पूंजीवादी राज्य की शक्ति इजारेदारों के साथ एक तंत्र में संयुक्त हो जाती है। यह तंत्र इजारेदार पूंजी के

लिए अधिनतम संभव मुनाफा निर्गमन करने के लिए काम करता है और साथ ही जनवादी व मजदूर आन्दोलनों तथा राष्ट्रीय मुक्ति गणनों के समर्थन के लिए अवसर प्रदान करता है। यह संभव भूतपूर्व जानिवेगों व पराधीन देशों के सम्पन्न जनपणों को अपने राष्ट्रनिर्णय-आर्थिक दिनों के अधीन करने के लिए और समाजवादी विश्व के विरुद्ध सहाई से इजारेदारों के पक्ष में भी काम करता है। आज राज्य-इजारेदार पूंजीवाद का प्रमुख उद्देश्य पूंजीवादी-व्यवस्था की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए तय्य करना है।

राज्य-इजारेदार पूंजीवाद की आर्थिक उत्पत्ति पूंजी के उच्चस्वरीय संकेन्द्रण व इजारीकरण और अपने अत्यन्त अन्तर्विरोधी व विरोधमूलक रूप में पूंजीवादी-उत्पादन के समाजीकरण पर आधारित है। उत्पादन के उच्चस्वरीय संकेन्द्रण और समापूँजी के हिस्सों में वृद्धि होने के कारण विज्ञान मात्रा में निवेश की जरूरत होती है। कुछ उद्योगों में विस्तारित उत्पादन के लिए वैयक्तिक पूंजीपतियों के ही नहीं, निगमों के संग्रहण भी अपर्याप्त हो जाते हैं। तब राज्य पूंजी के संकेन्द्रण को प्रोत्साहित करने और शोध व विकास की परियोजनाओं के लिए (धाम तौर से उन क्षेत्रों के लिए जहाँ परिणाम मद गति से मिलने हैं तथा विज्ञान संसाधनों की जरूरत होती है) वित्त-निवेश करने में उनकी सहायता करता है।

पूंजीवादी उत्पादन के इजारीकरण व समाजीकरण से वैषम्य में वृद्धि होती है। इजारेदार अर्थव्यवस्था के अतितामकारी क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं और फिर आधुनिक वैज्ञानिक व प्रयोगिक आधारों पर उनका तेजी से विस्तार करते हैं। वे क्षेत्र, जिनमें कम मुनाफा होता है, विकास में पीछे रह जाते हैं। किन्तु सामाजिक पूंजी के पुनरुत्पादन के लिए अर्थव्यवस्था के सभी घटकों में एक निश्चित सम्बन्ध की जरूरत होती है। अलाभप्रद क्षेत्रों अथवा जो क्षेत्र विशेष लाभप्रद नहीं हैं उनमें प्रवेश करके तथा अलाभकारी परियोजनाओं में वित्त-निवेश करके राज्य देश के आर्थिक ढाँचे में निश्चित परिवर्तन करता है और अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को प्रोत्साहित करता है।

इजारेदारियों की सर्वोच्चता उत्पादन व उपभोग के बीच अंतर्विरोध को बढ़ाती है और माल-उत्पादों की समस्या को गंभीर बना देती है। वित्तीय अल्पतंत्र राजकीय माँग, विशेष रूप से सैनिक-उपयोग में काम आने वाले उत्पादों की माँग को बढ़ाकर बाजार की सामर्थ्य में वृद्धि करने का तथा इन अंतर्विरोधियों का समाधान करने का प्रयत्न करता है।

उत्पादन का समाजीकरण निजी पूंजीवादी स्वामित्व की सीमाओं से आगे बढ़ गया है और पूंजीवादी-सम्बन्धों को तोड़ने की जरूरत को निर्देशित कर रहा है। लेकिन इजारेदार पूंजी विस्तारित उत्पादन-शक्तियों पर मजबूत अधिकार पाने और निजी पूंजीवादी स्वामित्व को बनाये रखने के लिए राज्यतंत्र का उपयोग

करती है।

इजारेदार पूंजीवाद राज्य-इजारेदार पूंजीवाद में क्यों विकसित होता है, इसके कारण केवल साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था में ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता तथा वर्गीय व सामाजिक अंतर्विरोधों की वृद्धि में भी है। राज्य पूंजी व श्रम के बीच सम्बन्धों में हस्तक्षेप करता है और इजारेदारों को मजदूर-वर्ग व कुल मिलाकर मेहनतकों पर बढ़ा-चढ़ाकर आर्थिक तथा राजनैतिक दबाव डालने की छूट देने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक कानूनों का प्रयोग करता है।

इजारेदार पूंजीपति-वर्ग उपनिवेशी व पराधीन देशों में अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग करता है और राज्य की शक्ति के माध्यम से विकासशील देशों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश करता है।

इस प्रकार पूंजी व उत्पादन के सकेन्द्रण में भीमकाय वृद्धि, इजारेदारों की बढ़ती हुई शक्ति और साम्राज्यवाद के आर्थिक-राजनैतिक अंतर्विरोधों का तीव्र रूप में गभीर होना—ये सब राज्य-इजारेदार पूंजीवाद के विकास के घटक हैं। इनके साथ अंतर्राष्ट्रीय व आंतरिक कारणों तथा साम्राज्यवाद की राजनीति व अर्थनीतियों में नयी परिघटना के कारण नें राज्य-इजारेदार पूंजीवाद, विशेष रूप से पूंजीवाद के आम-संकट की तीसरी अवस्था में आगे बढ़ा।

राज्य-इजारेदार पूंजीवाद का बढ़ता हुआ तीव्र विकास उत्पादक-शक्तियों के और अधिक विकसित हो जाने का प्रत्यक्ष परिणाम है। केंद्रीकृत समन्वय और शोध व विकास के लिए विराट संसाधनों की जरूरत होती है, इस कारण इजारेदार पूंजी राज्य की सहायता का आश्रय लेती है। वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक क्रांति ने भी अर्थव्यवस्था के सकेन्द्रण व इजारीकरण के मजबूत करने में सहायता दी है। उत्पादन का समाजीकरण ऐसे स्तर पर पहुँच गया है जब राज्य आर्थिक-जीवन के सभी पक्षों में प्रत्यक्ष भाग लेना जरूरी समझने लगा है। राज्य के इस प्रकार शामिल हुए बिना आधुनिक उत्पादक-शक्तियाँ अधिक समय काम नहीं कर सकती।

दूसरा महत्वपूर्ण कारक बढ़ता हुआ वर्ध-मुद्द है जो साम्राज्यवादियों को चाल चलने तथा मजदूर वर्ग व समग्र रूप से मेहनतकों को कुछ छूट देने के लिए विवश करता है। मेहनतकों पर दबाव डालने के लिए पूंजीपति-वर्ग राज्य के विधानों का प्रयोग करने की कोशिश करता है और अर्थव्यवस्था के राजकीय नियंत्रण के द्वारा वर्ध-विरोधों पर परदा डालने तथा अराजकता, संकट व बेरोजगारी जैसी सामाजिक रूप से खतरनाक परिघटनाओं को रोकने की कोशिश करता है।

साम्राज्यवाद की उपनिवेशी व्यवस्था का अंत, इजारेदार पूंजीवाद के राज्य-इजारेदार पूंजीवाद के रूप में विकास को तीव्र करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। विदेशी अल्पतंत्र विकासशील देशों में अपनी आर्थिक सर्वोच्चता को बनाने रखने और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को दबाने के लिए राज्य-तंत्र का बढ़ता हुआ

व्यापक उपयोग कर रहा है। अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य साम्राज्यवादी देश औद्योगिक रूप से अ विकसित अनेक देशों में अभी भी अपने सैनिक व सैनिक अड्डे बनाये हुए हैं और 'आर्थिक-सहायता' के बहाने से उनकी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं।

विश्व-समाजवादी व्यवस्था के उदय ने साम्राज्यवाद की स्थिति को बहुत कमजोर कर दिया है। राज्य-तंत्र से सहायता प्राप्त करके वित्तीय अल्पतंत्र कुछ देशों के पूंजीवाद से अलग हो जाने से साम्राज्यवादी विश्व पर पड़े नकारात्मक परिणामों को निष्प्रभावित करने, समाजवाद के मुकाबले आर्थिक प्रतियोगिता में डटे रहने, उत्पादन-श्रमों को तेज करने और कुल मिलाकर पूंजीवादी व्यवस्था को बचाये रखने के लिए अपनी सारी क्षमता को सामंजस्य करने की कोशिश कर रहा है।

2. राज्य-इजारेदार पूंजीवाद के प्रमुख रूप

राज्य-इजारेदार पूंजीवाद के सुस्पष्ट सङ्गण हैं जो प्रत्येक देश-विशेष की ऐतिहासिक रूप से विभिन्न आंतरिक व बाह्य-दशाओं पर निर्भर होते हैं। लेकिन अब हम अधिकांश देशों में अंतर्निहित प्रमुख रूपों की विवेचना करनी चाहिए।

राज्य-स्वामित्व और राज्य-व्यापार में वृद्धि—पूंजीवादी-व्यवस्था इति के भीतर राज्य-स्वामित्व का विकास और उसके दुर्बोधन के विविध रूप राज्य-इजारेदार पूंजीवाद के विकास की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। किन्तु राज्य-स्वामित्व का क्षेत्र समान नहीं है तथा आंतरिक व बाहरी कारकों पर निर्भर होता है। फिर भी, सामान्य रूप में मुख्यतः औद्योगिक, परिवहन, बैंकिंग तथा अन्य उद्यमों के राज्य-स्वामित्व के रूप में प्रकट होते हुए, पूंजीवाद के आम-संगठ के दौरान राज्य-स्वामित्व बढ़ा है। ब्रिटेन में कोयला उद्योग, रेल, गैस-व्यवस्था और ऊर्जा-केन्द्र राज्य के अधीन हैं। फ्रांस में कुल उत्पादन के लगभग 15 प्रतिशत का उत्पादन सरकारी क्षेत्र करता है—उद्योग उद्योग का 80 प्रतिशत, लकड़हन शारा कोयला उद्योग और ऊर्जा उत्पादन राज्य के हाथों में केन्द्रित है। जर्मनी में लकड़हन 25 प्रतिशत कोयला-पूँजी राज्य के पास है।

पूँजीवाद के अंतर्गत राज्य-स्वामित्व अपनी ही पूँजीवादी-प्रवृत्ति बचवा करती सामाजिक आर्थिक प्रवृत्ति को सही बदलता है और यह जितनी भी तरह लोक-स्वामित्व नहीं है। पूँजीवाद के अंतर्गत राज्य-स्वामित्व का परिण पूँजीवादी राज्य के बर्तमान सामाजिक के द्वारा निर्धारित होता है। यह सामान्य में पूँजीवादी सवर्ण होता है क्योंकि यह राज्य-स्वामित्व का प्रयोग करने वाले पूँजीवादी वर्ग के अर्थीन होता है और उद्योगी श्रम के शोषण के माध्यम के रूप में काम आता है।

राज्य-इजारेदार स्वामित्व का निर्माण उत्पादन के साधनों के समाजीकरण के

द्वारा होता है। इसका निर्माण राज्य द्वारा प्रदत्त धन से नये उद्योगों की स्थापना, कुछ उद्यमों अथवा संपूर्ण उद्योग के राष्ट्रीयकरण और इसके साथ राज्य द्वारा पूंजीवादी स्वामित्व की कपनियों के शेयर खरीदने से होता है।

राज्य-बजट में वित्त-निवेश के माध्यम से बने उत्पादन के साधनों के स्वामित्व का बड़ा हुआ परिमाण इजारेदारी हितों का खटन नहीं करता है। इसके विपरीत राज्य-संपत्ति इजारेदारों को लाभ पहुँचाने के लिए राष्ट्रीय आय एवं अतिरिक्त मूल्य के पुनर्वितरण के एक हथियार के रूप में प्रमुख भूमिका अदा करती है। जैसा पहले बताया गया है, राज्य प्रमुख रूप से उन क्षेत्रों में निवेश करता है जिन्हें विशेष रूप से बड़े निवेश की जरूरत होती है और जिनसे बहुत निवट भविष्य में आय की संभावना नहीं होनी है। इससे भी आगे, जब शोध व विकास की बेहद महँगी परियोजनाएँ एक बार पूरी हो जाती हैं और जमा पूंजी के रूप में लगाये गये आरंभिक निवेश की दाति-पूर्ति हो जाती है तो अनेक मामलों में, राजकीय उद्यम बहुत अनुकूल शर्तों पर इजारेदार पूंजीपतियों को लौटा दिये जाते हैं अथवा ठेके पर दे दिये जाते हैं। परमाणु एवं अतिरिक्त उद्योग और आज के ऊर्जा उद्योग के विकास का प्रतिमान यही है।

सरकारी निकायों द्वारा निजी निगमों के शेयरों की खरीद के द्वारा भी राज्य संपत्ति प्राप्त करता है। इसके समानांतर दूसरी प्रवृत्ति भी है—राजकीय निगमों द्वारा निजी उद्यमों को अपने शेयरों की बिक्री। राज्य एवं इजारेदारों के संयुक्त उद्यम भी दिखायी देते हैं और इससे यह तथ्य स्पष्टता से प्रमाणित होता है कि उत्पादन के साधनों का राज्य स्वामित्व अनिवार्यतः पूंजीवादी स्वामित्व है।

प्रायः मालिकों की क्षति-पूर्ति करते हुए निजी उद्यमों का राष्ट्रीयकरण एक दूसरा तरीका है जिससे राज्य संपत्ति उत्पन्न होती है। आधुनिक सुधारवाद के वैचारिक समर्थक यह समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पूंजीवादी उत्पादन संबंधों के सचि के भीतर राष्ट्रीयकरण समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए तथाकथित रूप में राह खोलता है। लेकिन वास्तव में, कुछ उद्यमों अथवा समस्त उद्योग का भी पूंजीवादी राष्ट्रीयकरण पूंजीवादी-स्थवस्था के धरिण को नहीं बदलता है। उद्यम राज्य-पूँजीवादी हो जाते हैं और उनका सामाजिक सारतत्त्व रती भर नहीं बदलता क्योंकि विरोधमूलक वर्ग-संबंध और पूंजीवादी-शोषण समाज में जारी रहता है।

पूँजीवादी राष्ट्रीयकरण प्रायः इजारेदारों के तात्कालिक अथवा दीर्घकालिक हितों से जुड़ी आवश्यकताओं का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकी पिछड़ेपन के कारण दिवालियापन का सामना करने वाले और प्रतियोगिता में असमर्थ हो जाने वाले उद्यमों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। राष्ट्रीयकरण बढ़ते हुए सामाजिक अंतर्विरोध, युद्ध या आर्थिक-संकट के समय मजदूर-वर्ग के दबाव का परिणाम भी हो सकता है। लेकिन अंतिम रूप से पूँजीवादी—राष्ट्रीय-

करण की मूलभूत प्रेरक शक्ति इजारेदारी—आधिपत्य की व्यवस्था को मजबूत करना, निजी संपत्ति की वित्तीय भारों व दिवालियापन से रक्षा करना और कुं मिलकर पूंजीवादी-व्यवस्था की स्थिति को दृढ़ करना है। हमारे महायुद्ध के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा कुछ अन्य पश्चिमी यूरोप के देशों में राष्ट्रीयकरण इन्हीं उद्देश्यों की ओर निर्दिष्ट था।

ऐसा होने पर भी, इजारेदार पूंजीपति वर्ग भीतर में सरकारी-क्षेत्र की वृद्धि को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। इजारेदार व्यापक राष्ट्रीयकरण से भयभीत है (जैसे कि उन्हें यह भय है कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में अन्य तरीकों से बनी हुई राज्य-संपत्ति के साथ प्रतियोगिता में प्रबल सिद्ध हो सकती है) क्योंकि उत्पादन के साधनों का व्यापक समाजीकरण पूंजीपति वर्ग की आवश्यकता को सिद्ध करता है। इसलिए पूंजीवाद के अंतर्गत राज्य-संपत्ति, चाहे वह किसी भी प्रकार उत्पन्न हो, स्वामित्व का सामान्य प्रचलित रूप नहीं बन पायेगी।

इस मान्यता का कि इजारेदारों को समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रीयकृत क्षेत्र का व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है, यह अर्थ नहीं है सर्वहारा वर्ग को राष्ट्रीयकरण के लिए आंदोलन नहीं करना चाहिए। पूंजीवादी समाजीकरण में द्वन्द्वात्मक अंतर्विरोध निहित हैं। एक तरफ इजारेदार पूंजीपति वर्ग अपनी सर्वोच्चता को मजबूत करने व मेहनतकशों पर नियंत्रण रखने के लिए राष्ट्रीयकरण का उपयोग करता है, दूसरी तरफ राष्ट्रीयकरण वास्तव में उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व के सिद्धांत को हानि पहुंचाता है और यह दिखलाता है कि बिना पूंजीपतियों के भी सामाजिक विकास संभव है। इसी कारण, पूंजीवादी देशों में कम्युनिस्ट तथा मजदूर दल जनवादी राष्ट्रीयकरण (मालिकों को हराकर बिना और मजदूरों के अनिवार्य प्रतिनिधित्व के साथ प्रबंध का राजकीय नियमों को हस्तान्तरण) के नारे को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह के राष्ट्रीयकरण की माँग भी समाजवादी नहीं है (यद्यपि प्रगतिशीलता की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है) क्योंकि इससे पूंजीवादी व्यवस्था की प्रकृति नहीं बदलती है।

पूंजीवादी राज्य द्वारा राष्ट्रीय आय के भाग का वितरण और पुनर्वितरण—राज्य-इजारेदार पूंजीवाद के विकास के साथ पूंजीवादी राज्य राष्ट्रीय आय का बड़ा हुआ हिस्सा पाने लगता है। राष्ट्रीय आय के इस बड़े हुए हिस्सा का, बड़े-व्यापार को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य द्वारा पुनर्वितरण पूंजीवादी पुनरुत्पादन का एक विशेष लक्षण और इजारेदारों को समृद्ध करने का एक प्रमुख तरीका बन गया है। राष्ट्रीय-आय के पुनर्वितरण के तंत्र में सबसे प्रमुख तत्व राज्य बजट है जो विभिन्न स्रोतों से (प्रमुख रूप से करारोपण के द्वारा) मौद्रिक-साधनों का संवय करता है।

राज्य-बजट के माध्यम से राष्ट्रीय आय के पुनर्वितरण के लिए आधिपतियों-

सबसे अर्थात् इजारेदारी को विभिन्न प्रकार के अनुदानों, एवं आर्थिक सहायता, पुनर्-
 भी व्यापक प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष सहायता के साथ-साथ इजारेदारी राज्य-
 बजट में अग्रतः प्राथमिकता भी—मुख्य रूप से नये उपकरण पर कर-रियायत, शीघ्र हुए
 धनित्र-सहायनों पर करीयता क्रम के आधार पर करारोपण, व्याजरहित उधार,
 उत्पादों की आपूर्ति से पहले अक्षिप्त भुगतान आदि के रूप में धनराशि प्राप्त करते
 हैं। राज्य-शोध एवं विकास परियोजनाओं के लिए भी बड़े स्तर पर वित्त-व्यवस्था
 करना है। राज्य निजी निगमों द्वारा वैज्ञानिक शोध, जिसमें सैन्य-शोध भी शामिल
 है, में भी भारी मात्रा में निवेश करता है। कमस्वरूप इजारेदारियाँ नयी तकनीक,
 निगुणता और वैज्ञानिक उपलब्धियों का अधिकांश मूल्य चुकाने के लिए मोचनधि
 के प्रयोग का अवसर अपने लिए प्राप्त कर सकती हैं।

अधिकांश राष्ट्रीय-आय के व्यय की व्यवस्था करने हुए पूंजीवादी देशों की
 सरकारें राज्य-बजट द्वारा विनीय सहायनों का व्यापक पुनर्वितरण करती हैं।
 मजदूर तथा छोटे स्तर के बस्तु-निर्माता जो कुछ पैदा करते हैं और जो कर के रूप
 में राज्य-बजट में आता है, उसका एक बड़ा भाग इजारेदारियों के लिए अनिश्चित
 लाभ का स्रोत बन जाता है।

अर्थव्यवस्था का संन्धीकरण—युद्ध के बाद आर्थिक सैनिक-व्यय बहुत से
 पूंजीवादी देशों की विशेषता रही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ संन्धी-
 करण पूंजीवाद के आम-संबंध के गहरा होने का संदर्भक है। यह विश्व-समाजवादी
 व्यवस्था के विकास, साम्राज्यवाद की उपनिवेशी-व्यवस्था का पतन और विश्व के
 क्रांतिकारी व राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों में आए उभार के परिणामस्वरूप साम्राज्य-
 वादी-आधिपत्य क्षेत्र के सिकुड़ने की प्रतिक्रिया है। पूंजीवादी देशों में अर्थव्यवस्था
 के संन्धीकरण को तेज करने के लिए, राजनैतिक स्थितियों के निर्माण को प्रति-
 क्रियावादी केन्द्रों द्वारा पालित-पोषित 'शीत-युद्ध' के वातावरण ने प्रोत्साहित
 किया।

अर्थव्यवस्था का संन्धीकरण राज्य-इजारेदार पूंजीवाद की व्यवस्था का और
 आगे विकास करता है। प्रमुख साम्राज्यवादी देशों में इस व्यवस्था के नाभिक केन्द्र
 सैन्य-औद्योगिक-समूह हैं जिनमें सैनिक-उत्पादों का निर्माण करने वाली इजारे-
 दारियाँ, सैन्य-शक्ति के प्रतिनिधि, राज्य-संघ के उच्च-अधिकारी, सैनिक-शोध व
 विकास में जुड़े कुछ बुद्धिजीवी, मजदूर-संघों के कुछ नेता आदि शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था के संन्धीकरण का उद्योग पर गहरा तथा प्रतिकूल प्रभाव होता
 है। सैनिक क्षेत्र का विकास अर्थनीतियों द्वारा नहीं, सैनिक एवं राजनैतिक
 कारणों से निर्धारित होता है। यह विकास अनिवार्यतः अगमान व अनियमित होता
 है और पुनरुत्पादन की प्रक्रिया को अस्थिर करता है। आम तौर से उन साम्राज्य-
 वादी देशों में आर्थिक-विकास भी दर न्यून होती है, सैनिक व्यय जिनके सफल

राष्ट्रीय उत्पाद के बड़े हिस्से का उपयोग कर लेता है।

सैन्यीकरण का प्रमुख आर्थिक उद्देश्य इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वी के लिए भारी मुनाफ़े निश्चिन करना है। सैन्य-औद्योगिक निगमों द्वारा प्राप्त किये मुनाफ़े की औसत दर, अन्य सभी निगमों द्वारा प्राप्त औसत मुनाफ़े से काफी ऊंची है। अमेरिका के वित्तीय अभिकरण के लेखा के अनुसार निर्माण-उद्योग में मुनाफ़े का कुल मानक 20 प्रतिशत की सीमा में घटता-बढ़ता रहा जबकि उसी समय सैनिक ठेकों पर काम करने वाले निगमों ने 100 प्रतिशत तक मुनाफ़ा कमाया।

साम्राज्यवादी देशों की सरकारें सैन्यीकरण का प्रयोग आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले उपकरण के रूप में करती हैं। सैनिक तकनीक बहुत जल्द पुरानी हो जाती है। इसलिए शस्त्रों का सतत सतत पुनर्स्थापन जरूरी होता है। इसमें सैन्य-औद्योगिक निगमों की ओर ठेकों तथा विस्मयकारी मुनाफ़ों का नियमित प्रवाह बना रहता है।

अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण आर्थिक स्थिति और औद्योगिक चक्र को भी कुछ हद तक प्रभावित करता है। सैनिक-उत्पादन में सरचनात्मक परिवर्तन तथा उसका एव उसके अनुकूल शस्त्र-बाजार का विस्तार व संकुचन आर्थिक-चक्र की विशेष अवस्थाओं के आगमन, प्रकृति और दीर्घता को प्रभावित करता है। यद्यपि ये परिवर्तन पूंजीवादी पुनरुत्पादन के चक्रीय विकास के स्वतः प्रवर्तित नियमों को रद्द नहीं करते हैं।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण एक ऐसा कारक है जो पूंजीवाद के प्रमुख अंतर्विरोध—उत्पादन की सामाजिक प्रकृति तथा उसका फल प्राप्त करने के निजी पूंजीवादी रूप के बीच का अंतर्विरोध—को और अधिक तीव्र व गहरा बनाता है। उस प्रसंग में उत्पादन तथा उपभोग के बीच बढ़ती विसंगति ध्यान देने योग्य है। उच्चतर सैनिक-व्यय का परिणाम उच्चतर कर होते हैं और यह व्यय मेहनतकशों के उपभोग में बाधा डालता है, कुछ मामलों में तो उसमें पूर्ण हास भी करता है। भौतिक संसाधन व मानव-शक्ति के काफी अंश का अनुप्रेषण लोक-आवास, परिवहन, संचार की जरूरतों को सतुष्ट करने, पर्यावरण की सुरक्षा और स्वास्थ्य व शिक्षा की व्यवस्था में उन्नति की सम्भावनाओं को संकुचित करता है। इसी वजह से अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण सामाजिक सुरक्षा को क्षति पहुंचाता है और लोक-सेवकों के वेतनों को कम करता है।

सैनिक व्यय की पूति करने के लिए राज्य कागजी-मुद्रा की स्फीति-मात्रा में निकासी सहित अनेक तरह के मौद्रिक-स्रोतों का उपयोग करता है। सैन्यीकरण और मुद्रा की तैयारियाँ साम्राज्यवादी देशों के राज्य-बजटों एवं भुगतान-संतुलन में घाटा होने के प्रमुख कारण हैं। सैन्यीकरण मौद्रिक-वित्तीय संकट को भी बढ़ाता है। यह अबाधित शस्त्र दौड़ की—जो सैनिक-उत्पादन की मात्रा को विराट रूप

मे बढ़ाती है—कीमत और पूँजीवाद के धाय की सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का राज्य-इजारेदारी नियंत्रण—यहाँ हमारा आशय आर्थिक-संकट को हल्का करने, आर्थिक-विकास की दरों को स्थिर करने व बढ़ाने, उत्पादन के संकेन्द्रण को तीव्र करने, अर्थव्यवस्था में सरचनात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने और निश्चित सामाजिक-समस्याओं से निपटने के लिए किए गए सरकारी उपायों के समस्त समूह से है।

दोनों महायुद्धों के समय अर्थव्यवस्था का बटोर राज्य-नियंत्रण प्रभावी था। किन्तु यह केवल युद्धकालीन उपाय नहीं था, दोनों महायुद्धों के बीच के समय में भी (विशेष रूप से 1929-33 के आर्थिक-संकट के समय) पूँजीवादी देशों में अर्थव्यवस्था का राज्य नियंत्रण मौजूद था। हाल के दशकों में साम्राज्यवादी देशों के आर्थिक विकास में यह स्थायी उपादान रहा है।

आधुनिक विश्व में राज्य-इजारेदार नियंत्रण का क्षेत्र और गहराई दोनों बढ़ गये हैं। अधिकांश साम्राज्यवादी देशों में आर्थिक-नियंत्रण के विस्तार-निकाय और सस्याएँ काम कर रही हैं। नियंत्रण के बहुत से उपाय सीधे उत्पादन की ओर लक्षित हैं तथा वे संचय व उपभोग के बीच संबंधों और सामाजिक-आर्थिक आधारभूत ढाँचे के विकास पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं।

राज्य-इजारेदार-नियंत्रण को स्थापित करने के अनेक उपाय हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उत्तोलक राजकीय निवेश है। इन निवेशों में कोई भी राजकीय-निर्माण उद्योग, कच्चा काल व ऊर्जा-संसाधनों के विकास, यातायात, आवास व नगरीय निर्माण के लिए निवेश और पिछले दो दशकों में शोध व विकास के लिए निवेश को छूट सकता है। सारे साम्राज्यवादी देशों का एक लक्षण कुल निवेश में राज्य का हिस्सा बढ़ना है। राज्य संस्थाओं और कम्पनियों की मंथ निजी निवेश की मात्रा तथा दिशा को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती है। इसके अलावा प्रायः राज्य विविध प्रकार के कर लाभ, बड़े हुए मूल्य-हास-चक्र आदि के द्वारा निजी निवेश को प्रोत्साहन देता है।

कृषि-उत्पादों की माँग, आपूर्ति तथा कीमतों को नियमबद्ध करके और फिर कृषि-उत्पादन के ढाँचे पर इसके प्रभाव के माध्यम से राज्य की नियंत्रक-गति-विधियों का कृषि-क्षेत्र में भी विस्तार होता है। कृषि-क्षेत्र में उत्पादन व पूँजी के संकेन्द्रण को प्रोत्साहित करके पूँजीवादी राज्य प्रायः कृषि योग्य भूमि के आकार को कम करने की नीति पर चलता है। कृषि-मूल्यों के एक निश्चित-स्तर को बनाए रखने के लिए राज्य-संगठन किसानों से उनका अतिरिक्त उत्पादन खरीद लेते हैं। वे कृषि तथा पशु-पालन में सरचनात्मक परिवर्तन के लिए वित्त-व्यवस्था करने के अनेक तरीके काम में लाते हैं और भूमि-प्रबन्ध के प्रश्नों में भी हस्तक्षेप करते हैं। कुल मिलाकर कृषि-क्षेत्र में राजकीय-उपायों की व्यवस्था उत्पादन के

साधनों के निजी स्वामित्व के आधारों को प्रभावित नहीं करती है। यह अंग्रेजना और प्रतियोगिता को समाप्त नहीं कर सकती जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनिवार्य गुण-धर्म हैं।

साम्राज्यवादी देशों की सरकारें सामाजिक-आर्थिक अनिवार्यताओं के कारण अपनी अर्थव्यवस्थाओं को नियोजित करती हैं। वैज्ञानिक प्रौद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादक-शक्तियों का बढ़ा हुआ समाजीकरण, पूंजीवादी पुनरुत्पादन के अंत-विरोधों में और अधिक वृद्धि तथा दो विरोधी व्यवस्थाओं के बीच संघर्ष—ये सब विकास कार्यक्रमों को पूरा करने एवं उनका विस्तार करने की जरूरत उत्पन्न करते हैं। इजारेदार पूंजीपतियों की रणनीति का भी निश्चित महत्व है जो बढ़ते हुए सामाजिक द्वन्द्वों की स्थिति में अपनी सर्वोच्चता को इस तरह के उपायों से बनाये रखने की कोशिश करते हैं।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नियोजन आर्थिक जीवन का एक स्थायी उपादान बनता जा रहा है। इसका उद्देश्य आर्थिक प्रगति की दरो को स्थिर बनाने व ऊपर उठाने के लिए पूंजीवादी पुनरुत्पादन को प्रभावित करना, औद्योगिक सतुलन प्राप्त करना, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना आदि है। दीर्घकालीन विकास कार्यक्रमों, विशेष रूप से निवेश परियोजनाओं और साथ ही भावी अनुमानों को बनाते समय राष्ट्रीय लेखाविधि तथा निवेश व निर्गम सारणियों की प्रणाली और जटिल समष्टि अर्थशास्त्रीय प्रतिमानों का व्यापक प्रयोग किया जाता है।

राज्य-इजारेदार कार्य नियोजन को समाजवादी अर्थव्यवस्था के नियोजन के समान नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनों की सामाजिक-आर्थिक आधार-शिक्षाएँ पूरी तरह भिन्न हैं। पूंजीवादी देशों में कार्य-नियोजन का प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था के केवल राजकीय क्षेत्र पर होता है। जहाँ तक निजी कंपनियों का सबाल है, सरकार का आर्थिक कार्य-नियोजन सिर्फ अनुसंधान के रूप तक सीमित रहता है। वह किसी भी तरह बाह्यकारी नहीं होता। पश्चिमी यूरोप में आर्थिक विकास के अधिकांश स्वीकृत कार्यक्रम कभी भी संपूर्ण रूप में पूरे नहीं हुए। निजी स्वामित्व और मुनाफे की खोज, जो पूंजीवाद की प्रेरक शक्तियाँ हैं, वास्तविक वैज्ञानिक नियोजन को दणित करती हैं जो कि विभिन्न उद्योगों के बीच तथा समग्र अर्थव्यवस्था में भी सही सतुलन स्थापित कर सकती है।

राज्य-इजारेदारी नियंत्रण और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कार्य-नियोजन अनिवार्यतः वर्गीय-प्रकृति के हैं। वे सबसे पहले कुल मिलाकर इजारेदार पूंजीपतियों के हितों को पूरा करते हैं और व्यवहार में बहुधा उनका प्रयोग मेहनतकारों के जीवन-स्तर व अधिकारों पर प्रहार करने के लिए किया जाता है। राज्य-इजारेदारी नियंत्रण पूंजीवाद में अंतर्निहित संकट तथा उसकी अन्तर्गत पड़ती का अन्त

नहीं कर सकता और न ही वह पूंजीवाद की अतन्त्र आर्थिक-वृद्धि को सुनिश्चित कर सकता है क्योंकि वह पूंजीवाद के स्वतः प्रसूत चरित्र एवं उत्पादन के विषम अनुपाती विकास को समाप्त नहीं कर सकता। वह पूंजीवादी समाज के उन सामाजिक अंतर्विरोधों को मुक्तज्ञान में भी असमर्थ है जो उग्र होकर राज्य को शिधा, मजदूरों के लिए विधेय प्रशिक्षण, 'शरीबी के विरुद्ध युद्ध' आदि उपाय अपनाते को प्रेरित करते हैं। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होने का तथ्य यह बतलाता है कि आधुनिक पूंजीवाद की शक्तियाँ अब इस व्यवस्था के उत्पादन संबंधों की प्रोत्सुहेत की शीघ्रता के अनुरूप नहीं रह गई हैं और आर्थिक समूहों के अधिक प्रगतिशील समाजवाद सिद्धान्तों की दिशा में परिवर्तन चाहती हैं।

3. राज्य-इजारेदार पूंजीवाद और समाजवाद के लिए परिस्थितियों का निर्माण

उत्पादक-शक्तियों का विकास स्वाभाविक रूप में ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जब पूंजीवादी उत्पादन अधिक-से-अधिक समाजीकृत हो जाता है। राज्य-इजारेदार पूंजीवाद इस प्रक्रिया को तेज करता है। उत्पादन के सर्वेक्षण को प्रोत्साहन, सरकारी क्षेत्र का विस्तार और राष्ट्रीय आय के अधिचाधिक प्रविष्टता का केंद्रित उपयोग पूंजीवादी पुनरुत्पादन को प्रभावित करता है। ये सब साफ-साफ समाजीकरण के विभिन्न पक्ष हैं। इस बीच लाभ का अधिग्रहण निम्नी ही बना रहता है। लाखों-करोड़ों व्यक्तियों के श्रम में उत्पादित संपदा का अधिकांश भाग इजारेदार पूंजीपति-वर्ग द्वारा हृष्य लिया जाता है जबकि समाजीकृत उत्पादन की वस्तुनिष्ठ आवश्यकता यह होती है कि वह संपदा समग्र रूप में समाज की सम्पत्ति बन जाये। इस प्रकार पूंजीवादी उत्पादन की प्रक्रिया रथच अनिवार्य रूप से पूंजीवादी-व्यवस्था के विनाश की आवश्यकता के परिणाम तक पहुँच जाती है।

लेनिन ने राज्य-इजारेदार पूंजीवाद का विश्लेषण किया और यह बताया कि पूंजीवादी-उत्पादन के समाजीकरण के समय आर्थिक-जीवन को नियंत्रित करने वाले राज्य-तंत्र का जाल विस्तृत होता है। इस तंत्र का उपयोग मजदूर-वर्ग समाजवादी-उत्पादन को संगठित करने के लिए कर सकता है। लेनिन ने राज्य-इजारेदार पूंजीवाद में इस तथ्य का भारी साक्ष्य देखा कि पूंजीवादी-व्यवस्था समाजवादी शक्ति के लिए पूरी तरह परिपक्व हो चुकी है और इसमें उन्होंने अंतीम ऐतिहासिक महत्त्व का यह निष्कर्ष निकाला—“राज्य इजारेदार पूंजीवाद समाजवाद की परिपुष्प औरिक हैदारी है, समाजवाद की देहरी है, इतिहास की गर्मनी

1. लेनिन—इसका एक ही भाग का एक अन्वयार्थी भाग को अपने दिशानों को अब तक करने अपने देखा के अनुपूरु बना देना का।—अनुपूरु

पूँजीवादी राजनीति और विचारधारा का बढ़ता हुआ संकट

पूँजीवाद के आम-संकट का गहरा होना, सामग्र राजनैतिक प्रतिक्रियावाद की अभूतपूर्व तीव्रता, पूँजीवादी-जनवादी स्वतंत्रताओं की अस्वीकृति और पूँजीवादी विचारधारा के गहन संकट के रूप में प्रकट होता है।

1. पूँजीवादी देशों में बढ़ा हुआ राजनैतिक प्रतिक्रियावाद

पूँजीवाद के आम-संकट के समय पूँजीवादी देशों में राजनैतिक प्रतिक्रियावाद का तेज हो जाना, बार-बार होने वाली महत्वपूर्ण परिघटना है। अगनी सधोष्णता को बनाये रखने के लिए इजारेदार पूँजी मेलनतकशों को उन जनवादी अधिकारों से बचिन करने की कोशिश करती है, जो मजदूर-वर्ग की अनेक पीढ़ियों के दुर्द-निश्चयी सघर्षों के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए थे। पूँजीवाद के आम-संकट के अंतर्गत राजनैतिक प्रतिक्रियावाद की उभता प्रजातन्त्र-विरोधी व फातिस्ट शासनो के रूप में पूरी तरह प्रकट होती है।

प्रजातन्त्र में प्रतिक्रियावाद की ओर परिवर्तन साम्राज्यवाद की चरेलु व विदेश, सेतों ही नीतियों की विवेचना है। चरेलु नीति में प्रतिक्रियावादी दिशा विदेशनीति में भी आकासक-दिशा को निर्धारित करती है। यही वह जान है जिसमें कोई भी साम्राज्यवाद के आन्तरिक व बाहरी कार्यों में अविभाज्य सङ्घ, जो इजारेदार पूँजी के सघर्ष के अनुकार निर्धारित होता है, को पटवान सकता है। तैरिन में निधा है—चरेलु व विदेशनीति, सेतों में साम्राज्यवाद प्रजातन्त्र के उन्मचन का तथा प्रतिक्रियावाद की ओर उन्मुख होने का प्रयास करना है। इस अर्थ में साम्राज्यवाय विदेशवाद रूप में प्रजातन्त्र के साम्राज्य रूप का निषेध है, संपूर्ण प्रजातन्त्र का

निवेद्य...।¹

पूँजीवाद के आम-संकट के साथ इजारेदार पूँजीपति वर्ग में बढ़ती हुई प्रजातंत्र-विरोधी आकांक्षाओं का विकास हुआ। इसका कारण यह था कि सर्वहारा और पूँजीपति वर्ग के बीच अंतर्विरोध उच्च बिंदु तक पहुँच गया था और उसने पूँजीपति वर्ग की सर्वोच्चता के लिए सीधा खतरा उत्पन्न कर दिया था। साम्राज्यवादी पूँजीपति वर्ग पूँजीवादी प्रजातंत्र के पुराने तरीकों से अब अधिक समय शासन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पूँजीवादी प्रजातंत्र तथा संसदवाद को धाँसो कम करना अथवा पूरी तरह नष्ट करना शुरू कर दिया। लेनिन ने लिखा है कि पहले महायुद्ध की विशेषता थी—“...पूँजीवादी संसदवाद और पूँजीवादी प्रजातंत्र के पतन की शुरुआत...।”² यह वास्तव में राजनीति तथा विचारधारा के क्षेत्र में पूँजीवाद के आम-संकट की शुरुआत थी।

पूँजीवाद के आम-संकट के दौरान साम्राज्यवादी पूँजीपति-वर्ग द्वारा संसदवाद तथा पूँजीवादी प्रजातंत्र के त्याग की इच्छा, तीव्र वर्ग-संघर्ष, पूँजीवाद की स्थिति में बढ़ता हुआ कटान, और समाजवाद से (जिसकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं) भय का परिणाम है। इन परिस्थितियों में साम्राज्यवादी पूँजीपति वर्ग विश्व पूँजीवादी व्यवस्था के बढ़ते विनाश को पूँजीवादी-प्रजातंत्र के तरीकों से अधिक समय नहीं रोक पाता। क्रासीवाद प्रतिक्रियावाद का सर्वाधिक भयावह परिणाम है। यह इजारेदार पूँजीपति वर्ग की तानाशाही का सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी रूप है जिसे पूँजीपति वर्ग मेहनतकशों के क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के एक साधन के रूप में समाज पर धोपता है। यह पूँजीपति वर्ग तथा सर्वहारा के बीच सर्वाधिक तीव्र संघर्ष के दौरान उत्पन्न होता है जबकि पूँजीपति वर्ग पुराने संसदीय तरीकों से अधिक समय तक अपनी सत्ता बनाये रखने में असमर्थ होकर आतंकवादी तानाशाही, मजदूर वर्ग व समस्त जनवादी आंदोलन के दमन और उत्तेजक सामाजिक लड़क़ाजी का सहारा लेता है। क्रासीवाद साम्राज्यवादी देशों के वित्तीय अल्पतंत्र के सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी व आक्रामक-क्षेत्रों की खुली तानाशाही है। यह धरेलू मामलों में जनवादी अधिकार व स्वतंत्रताओं को धरम करके पूँजीवादी-व्यवस्थाओं को बनाये रखने का प्रयत्न करता है और अंधराष्ट्रवादी बिदेशनीति का अनुसरण करता है। क्रासीवादी तानाशाहों की आतंरिक नीति के मूलतत्त्व कम्युनिस्ट एवं मजदूर दलों की समाप्ति, मजदूर-संघ व अन्य प्रगतिशील जनवादी संगठनों का नाश और आधारभूत पूँजीवादी-जनवादी स्वतंत्रताओं को नष्ट करना है।

1. वी० हार्ड० लेनिन, 'साम्राज्यवाद का विद्रुप और साम्राज्यवादी संघर्षवाद', सटलिज रचनाएँ, भाग 23, पृ० 43 (अध्याय 1)।

2. वी० हार्ड० लेनिन, 'पूँजीवादी संसदवाद के पतन के लिए मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग'।

जर्मनी में 1920 के दशक के आरम्भ में क्रासीवादी संगठन प्रभूट हुए। 1920 में जर्मनी की राष्ट्रीय समाजवादी मजदूर पार्टी बनी। जर्मनी के इजारेदार पूंजीपति वर्ग ने नाज़ियों को भारी वित्तीय सहायता दी। 1929-33 के विश्व आर्थिक संकट के दिनों में जीवन-स्तर में भयंकर गिरावट ने नाज़ियों को अपनी उत्तेजक सफ़ावादी में जनगण को (धाम तोर में मध्यवर्गीय क्षेत्रों को) प्रभावित करने में सहायता दी। नाज़ियों द्वारा सत्ता पर कब्ज़े की प्रतिव्रियावादी सामाजिक जनवादी नेनाओं के विश्वासघात से भी मदद मिली। 1929-33 के आर्थिक संकट के दिनों में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अधिकारों के लिए मेहनतकशों के संघर्ष तथा वर्गीय अंतर्विरोधों के तीव्र हो जाने में जर्मन-पूँजीवाद के अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो गया था। इजारेदार पूँजीपति वर्ग ने अपनी सत्ता को बचाये रखने के लिए वित्तीय पूँजी की आत्मबवादी तानाशाही स्थापित कर दी। पुनरुत्थानवादी मार्क्सकता वाले छोटी पूँजी के मालिकों में भी जर्मनी में फासीवाद का समर्थन किया। इस स्थिति में फासीवाद ने मजदूर-वर्ग के क्रांतिकारी आन्दोलन को कुचल दिया।

1933 में जर्मनी के प्रभावशाली वित्तीय वर्ग तथा विदेशी इजारेदार पूँजी से सहायता पाकर हिटलर के फासीवादी दल ने सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया और दूषित तानाशाही स्थापित कर दी। जर्मनी में सत्ता पर नाज़ियों द्वारा अधिकार को सिर्फ सामाजिक-जनवादियों के विश्वासघात और मजदूर वर्ग की कमबोरी का चिह्न ही नहीं समझा जाना चाहिए, यह पूँजीपति वर्ग की निर्वन्तता का भी चिह्न था जो संसदवाद तथा पूँजीवादी प्रजातंत्र के पुराने तरीके से अधिक समय शासन करने में समर्थ नहीं रह गया था।

दूसरे महायुद्ध का अंत फासीवादी शक्तियों की पराजय से हुआ, लेकिन फासीवाद में संघर्ष नहीं छोड़ा। अनेक साम्राज्यवादी देशों में वित्तीय अस्पृश्य ने सशस्त्र अनुषंगों की मंडली का संघटन करके तथा उनके चालाकीपूर्ण उपयोग से फासीवादी शासनों की स्थापना कर दी। यद्यपि जर्मनी एवं इटली का धूमिल फासीवाद पराजित हो गया किन्तु बहुत से देशों में फासीवादी शासन नये रूपों में पुनर्जीवित होने लगे। कुछ पूँजीवादी देशों में अब-फासीवादी संगठन खुले रूप में काम कर रहे हैं।

समाचार-पत्रों के अनुसार पश्चिमी जर्मनी में 100 से अधिक नव-नाज़ी तथा दक्षिणपंथी संगठन काम कर रहे हैं। वे सब 1964 में बने नव-फासीवादी जर्मनी के राष्ट्रीय प्रजाशासिक दल से सम्बन्धित हैं। इसके नेतृत्व का संगठन लगभग पूरी तरह से पूर्व-नाज़ियों से हुआ है। पश्चिमी जर्मनी के पुनरुत्थानवादी एवं नव-नाज़ी कर्मियों के प्रवृत्त एटोल्फ बान बाहेन ने स्वयं को गुरुहर घोषित कर दिया है। अपने कार्यक्रम सशस्त्र-सामन्ती विद्रोह और अहिंसक ही अहिंसकियों के सम्बन्ध

पर राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक दल निश्चय ही नव-नाज़ी दल है। यह जर्मन जगणतंत्र के साथ निकट सम्बन्धों के पक्षधर, तनाव-शैथिल्य के समर्थक और सो विरोध एवं साम्यवाद-विरोध का विरोध करने वाली प्रजातांत्रिक शक्ति विरुद्ध भौतिक-आत्मिक का प्रयोग करने के लिए सब दक्षिण-पंथी संगठनों का अ करता है। सारे नव-क्रांतीवादी तथा उपवादी, जो पश्चिमी जर्मनी में छुपक छुले रूप में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक दल के धारों तरफ़ सगठित

इटली में अनेक सक्रिय नव-क्रासिस्ट उपवादी संगठन और गुट हैं। उन एक इटली का सामाजिक आन्दोलन (एम० एस्० आई०) है जिसकी नीति की कम्युनिस्ट पार्टी को (जो मेहनतकशों के हित में नव-क्रासिस्ट छुनरे के स समर्थ का नेतृत्व कर रही है) नष्ट करना है। एम० एस्० आई० अकेला क्रासि समर्थक संगठन नहीं है—दूसरा बहुत महत्वपूर्ण संगठन राष्ट्रीय मोर्चा (ए एफ०) है। इटली में आज क्रासिस्ट-समर्थक संगठन देश में प्रजातांत्रिक शक्ति और गणतांत्रिक सविधान के लिए खतरा बन गये हैं। इसी कारण क्रासि समर्थक संगठनों की योजनाओं को विफल करने के लिए इटली की कम्युनिस्ट प व दूसरे वामपथी दल, प्रजातांत्रिक संगठन और प्रगतिशील जन एक साथ ि गये हैं।

अमरीका में जान बर्च सोसायटी, कम्युनिस्ट-विरोधी ईसाई-क्रूसेड, यु प्रतिरक्षा संघ, अमेरिकन लीजन (सेना), अमेरिकन राइफल संघ और ऐसे संगठन सक्रिय हैं। अन्य क्रासिस्ट तत्त्वों के साथ जान बर्च सोसायटी सामा अमरीकी जन की प्रजातंत्र के लिए भावना के साथ बेशर्मी से खिलवाड़ करती। वे अमरीका की कम्युनिस्ट पार्टी को 'विदेशी-दलाल' कहकर बदनाम करती और यह दावा करती हैं कि साम्यवाद अपने सारतत्त्व में प्रजातंत्र विरोधी है अमरीका में अति दक्षिण-पंथी तत्त्व सरकार पर शीत-युद्ध को वास्तविक यु में बदलने के लिए दबाव डाल रहे हैं। बर्चवादी जैसे क्रासिस्ट गुट छुले और छु दोनों ही तरीकों से विनाशक गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं और अमरीक निगमों द्वारा उनके लिए उदारता से वित्त-प्रबन्ध किया जाता है।

सतर के दशक की घटनाओं ने यह दिखाया है कि जब साम्राज्यवाद का संक गहरा होता है और जब प्रतिक्रियावादी, जनवादी एवं क्रांतिकारी शक्तियों के विरु अत्यधिक हिंसात्मक दमन के तरीकों का प्रयोग करने के लिए विशेष कठोर प्रयत्न करते हैं, तब क्रांतीवाद की गतिविधियाँ तीव्र होती हैं।

सितम्बर, 1973 में बिनी के वैधानिक रूप से निर्वाचित मोक्षप्रिय मोर्चा

को उखाड़ कर सैन्य-क्रासिस्ट जनता ने सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया।

ने बिनी के देशभक्तों के साथ जो क्रूर आतंकवादी व्यवहार किया है, वह

सत्तार के एक और संकेत है। बिनी की घटनाओं ने यह दिखाया

है कि जैसे ही स्वाधीनता की सोचप्रिय आकांक्षा पूंजीपतियों के वर्गहितो के लिए बनना बनने लगती है, पूंजीपति वर्ग पूंजीवादी-प्रजातंत्र के मुछोटे को फेंक देता है और अपनी सर्वोच्चता की रक्षा तथा जनगणों द्वारा प्राप्त लाभों को नष्ट करने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी की मदद सहित सब प्रकार के तरीके प्रयोग में लाता है।

हाम के वर्गों में नव-कासिस्टों की सर्वाधिक व्यापक कार्य-नीति आतङ्कवादी बायो द्वारा तनाव, बिन्ना व भय पैदा करना, आर्थिक-अव्यवस्था को प्रोत्साहन देना आदि रही है। इस कार्य-नीति का एक उद्देश्य तनाव की परिस्थितियों का लाभ उठाने हुए और 'अव्यवस्था पुनर्स्थापित करने' के बहाने से अतिवादी दक्षिणपथी शैव्यवाहियों को सत्ता पर कब्जा करने का अवसर देना है। नव-कासिस्ट सगठनों को (जो या तो पुनर्जीवित हो गये हैं या नये सगठनों की स्थापना की गई है) कार्य करने से रोकने के लिए यदि जनवादी शक्तिर्था अधिक दृढ़ता से सघर्ष नहीं करती है तो वे सगठन शक्ति एव तनाव-अहित्य के लिए गभीर खतरा बन सकते हैं।

विशेष पूंजी के सर्वाधिक प्रतिशानिधारी तरकों के राजनीतिक शस्त्र के रूप में, कुछ के बाद के समय में कासिस्ट सगठनों का उदय हो मूल रूप ग्रहण करता है, कुछ सगठन हिटलर एवं मगोलिनी के धुगिन विचारों में धुनेआम विश्वास प्रकट करते हैं जबकि कुछ अन्य पूंजीवादी दलों व सगठनों (सत्तासीन दलों व सगठनों सहित) में भीतर बुसब र छुपे रूप में ऐसा करते हैं और उन सगठनों का अपने पक्ष में आमाजीपूर्ण उपयोग करने का प्रयत्न करते हैं। युद्धोत्तर काल में विशेष रूप से पूंजीवाद के आम-सकट की तीसरी अवस्था में, प्रजातंत्र के विरुद्ध डॉक्ट्रिनावाद का हमला सर्वप्रथम व्यवहार एव बुनाबी-परम्पराओं के धुने-बदोस के रूप में विवर्तित हो रहा है। इसे सभी पूंजीवादी देशों में देखा जा सकता है। कुछ देशों में सरकार की शक्ति को मजबूत करने तथा उसकी शक्ति-विधियों पर विधायिका के नियन्त्रण को निर्बल करने के लिए अनेक सर्वप्रथम बदोस प्रयत्न किए गये हैं। कुछ अन्य देशों में जनगण के अधिकारों का अन्वयन करने के लिए बुनाबी कानूनों को अन्वयित किया गया है जिसका परिणाम मजबूत दलों को शक्ति पहुँचाकर दक्षिणपथी पूंजीवादी दलों के पक्ष में अन्वयन का भारी झुकाव हुआ है।

जिन विशेष तरीकों में डॉक्ट्रिनावाद प्रजातंत्र का अन्वयन करता है, उनमें से एक 'कानूनवाद के विरुद्ध लड़ने' के बहाने से आरम्भ करता है। कासिस्ट दलों को एक पार्टी जैसी ही देखा ही हुआ और आज कुछ दलों के देशों के तथा अन्वयित के डॉक्ट्रिनावादी, साम्राज्यवादी क्षेत्र उसका अनुसरण कर रहे हैं। प्रजातंत्र का अन्वयन करने वाले तथा अन्वयकों को अन्वयित करना है, इतिहास ही की जाती है।

में प्रजातंत्र के पक्ष में संघर्ष करने के लिए एक ग्रापक-मोर्चा बनाने की कम्युनिस्ट संभावनाएँ उलान्न होनी हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि पूंजीवादी गणतंत्र का बेहतर अपने पीछे वित्तीय-पूँजी के वर्ग-आधिपत्य के तंत्र को छुगाये रहता है और पूंजीपति वर्ग समस्त प्रजातांत्रिक संस्थाओं का नियंत्रण अपने हितों की दृष्टि से करने का प्रयत्न करता है, लेनिन ने बताया है—“अपनी मुक्ति के लिए पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष में मजदूर वर्ग के लिए प्रजातंत्र का बहुत भारी महत्त्व है।” मजदूर वर्ग के नेतृत्व में प्रजातंत्र एवं शांति की शक्तियों का मोर्चा साम्राज्यवादी शक्तियों के शासकीय क्षेत्रों को स्थानीय युद्ध न उकसाने, एक नये युद्ध के लिए तैयारियाँ रोकने और अर्थव्यवस्था को नागरिक-आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए विवश कर सकता है। यह मोर्चा फ़ासिस्ट प्रतिक्रियावाद को भी रोक सकता है और शांति, राष्ट्रीय स्वाधीनता, जनवादी अधिकार तथा उच्चतर जीवन-स्तरों के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए साम्राज्यवादी सरकारों को मजबूर कर सकता है।

मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान कम्युनिस्ट दलों के नेतृत्व में मजदूर वर्ग का आंदोलन साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावाद के आक्रमण को रोकने और किसान एवं मेहनतकशों के अग्य क्षेत्रों को (जो मजदूर वर्ग के स्वाभाविक साथी हैं) संघर्ष में शामिल करने के लिए जनवादी अधिकार तथा स्वतंत्रताओं का उपयोग करने का प्रयत्न कर रहा है। मेहनतकश संसद के लिए ऐसे प्रतिनिधि चुन सकते हैं जो संसद में साम्राज्यवादी पूंजीपति वर्ग की प्रतिक्रियावादी नीतियों का पर्दाफाश करेंगे और प्रतिक्रियावादी कानूनों को स्वीकृत होने से रोकेंगे।

मजदूर वर्ग के लिए प्रजातंत्र का महत्त्व केवल इस तथ्य से ही निर्धारित नहीं होता है कि यह साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष में इसका प्रयोग करता है, बल्कि इस तथ्य से भी होता है कि वास्तविक प्रजातंत्र की माँग मजदूर वर्ग के आंदोलन के अंतिम उद्देश्य और वर्ग-आधिपत्य को पूरी तरह नष्ट करने में उसकी ऐतिहासिक भूमिका को पूरा करती है। इस सम्बन्ध में लेनिन ने बताया है—“यह सोचना अतिवादी भूल होगी प्रजातंत्र के लिए संघर्ष समाजवादी क्रांति से सर्वहारा का ध्यान हटाने में या इस उद्देश्य को छुपाने, धुंधला कर देने आदि में समर्थ है। इसके विपरीत, जैसे ऐसा कोई विजयी समाजवाद नहीं हो सकता जो पूर्ण प्रजातंत्र पर हो, उसी तरह प्रजातंत्र के लिए संपूर्ण, लगातार और क्रांतिकारी सर्वहारा पूंजीपति वर्ग पर विजय के लिए तैयारियाँ भी नहीं कर

सकना।" प्रजातंत्र के लिए सघर्ष मजदूर वर्ग को समाजवादी क्रांति के लिए तयार करा है।

रुसिया की व सामग्री अवसरवादियों से अलग कम्युनिस्ट तथा मजदूर दल सामाजिक आर्थिक-सामाजिक माँगों तथा उन्नत प्रजातंत्र के लिए सघर्ष का (समाजवाद के लिए सघर्ष से उसकी तुलना करते हुए) विरोध नहीं करते हैं बल्कि उसे समाजवाद के लिए सघर्ष का हिस्सा मानते हैं। इजारेदार तथा उनकी आर्थिक सर्वोच्चता व राजनीतिक शक्ति के विरुद्ध सघर्ष करते हुए जो मूलगामी जनवादी पुष्प शास्त्र विचे जायेंगे, वे व्यापक जनसमूहों को समाजवाद आवश्यकता अनुभव बनाने में बड़ी हुई मात्रा में सहायता करेंगे।

2 पूँजीपति वर्ग की विचारधारा का गहरा होता संकट

पूँजीवाद का आम-भ्रष्ट केवल अर्थव्यवस्था तथा राजनीति को ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि विचारधारा और पूँजीवादी समाज में जिंदगी के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। पूँजीपति वर्ग ऐसे विचार प्रस्तुत करने में अब अधिक तय्य नहीं है जो जनवण के दिल और दिमाग को जीत सके। पूँजीवादी देशों में बहिष्कृत जनवण पूँजीवादी विश्व दृष्टि की अस्वीकार कर रहे हैं और पूँजीपति वर्ग की विचारधारा एक गभीर संकट में पड़ गयी है।

कुछ पूँजीवादी देशों में, विशेषतः अफ्रीका में पूँजीवादी राजनीतिक नेता और निदाशरर इस विचार को लोकप्रिय बना रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूँजीवाद का 'बाना फलट' हो गया है और 'पुराना पूँजीवाद' एक नये 'पूँजीवाद' से प्रतिस्थापित हो गया है। नये पूँजीवाद ने अपने भूटमार करने वाले शोषक स्वरूप को त्याग दिया है और अब यह, यह कहा जा सकता है कि 'जनता का पूँजीवाद' 'एक कार्बोस बन्धन शास्त्र' और एक 'प्रचुरता का समाज' हो गया है जिसका उद्देश्य 'असौख्य' एवं 'व्यसन' के हितों की सेवा करना है। अमेरिका के विषय में विल्लिंग्टन के जी० हार० जे० मानसेन बय देकर कहते हैं—'पूँजीवाद का अन्त की बहुत ही जल्द ही समाप्ति का इन्तेंद में विश्वनी एक शताब्दी में सम्पन्न (एडि वही उमर का बलिष्ठ रहा हो) नहीं रहा है।'

अन्तर्गत पूँजीवाद की हारपूर्व पूँजीवाद के बढ़ते विरोधमुखक अवरोध का हलका-भ्रष्ट की बढ़ती मह्यता पर परमा बनने और इजारेदारी युग के

द्वितीय भाग १।

अर्थात् पूँजीवाद व अर्थशास्त्र, जबकि मनुष्यन उद्यम व्यापक रूप में है, पूँजी के
द्वारा (विशेष की गयी शक्ति से अनुभव) स्वाभाविक वा विभाजन विशाल क्षेत्र में
होता है। कार्य कार्य के रूप पर बहुत पहले ही ध्यान दिया था। पूँजीवादी
विचारों को यह कहना है कि मनुष्यन-उद्यम उद्यम राष्ट्रीय है, स्वाभाविक के रूप के
रूप में उद्यम का प्रवर्धन के रूप में प्रजन को रख देने हैं। वे इस तथ्य को भी भूल
कर कि उद्यम की प्रवृत्ति प्रवर्धन के रूप पर निर्भर होती है।

पूँजीवादी विचारों व पूँजीवादी मयात्र में प्रवर्धन की भूमिका को भी उल्लेख
नहीं किया गया है। उद्यम रूप में प्रवर्धन को कोई विशेष वर्ग नहीं है। जो
उद्यम उद्यम की शक्ति वाले रूप में है अर्थात् जो भौतिक-उत्पादन में प्रत्यक्ष
कार्य में है। वे उद्यमकर्ता हैं। वे नीति-अवधि निर्णय नहीं करते हैं और साम
के रूप में उद्यम को प्रवृत्त करती हैं। जहाँ तक नीति-प्रवर्धन का संबंध
है कि उद्यम की नीति-निर्णयों का निर्देशन नहीं कर सकते हैं जब उनके पास SI
द्वारा उद्यम को नियंत्रण है अर्थात् अब वे पूँजीवादी हैं।

उद्यम उद्यम अर्थशास्त्र के रूप में उद्यम-विचारों से घेर नहीं खाते हैं। वे वित्तीय
रूप में ही उद्यम-विचारों को अपने उद्यम उद्यमों को सुनाने के लिए लड़ते जाते हैं।

उद्यम के उद्यम के पूँजीवादी अर्थशास्त्र में उद्यम-अर्थशास्त्र का मित्रात व्यापक
रूप में उद्यम का। यह मित्रात अर्थशास्त्र को दावा करता है, यह यह है कि
उद्यम उद्यम उद्यम उद्यम-विचारों का विचार होता है, वे दोनों बहुत ही मात्रा में
उद्यम-विचारों को उद्यम-विचारों हैं और दोनों के बीच का अंतर धीरे-धीरे
होता जाता है। पूँजीवादी विचारों यह है, यह उद्यम तथ्य के कारण होता है कि
उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र उद्यम-विचारों और अर्थशास्त्र उद्यम-विचारों-से-
उद्यम-विचारों को उद्यम-विचारों का मित्रात स्वाभाविक के घिन
का उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र उद्यम-विचारों की उद्यम-विचारों की कुछ सामान्य
उद्यम-विचारों का उद्यम-विचारों का उद्यम-विचारों उद्यम-विचारों का उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र
उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र
उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र
उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र

उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र
उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र
उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र उद्यम-विचारों के अर्थशास्त्र

माधिपत्य को छुटाने के लिए गड़ी जाती है। इजाजतदार पूंजीपति वर्ग सब जगह यह धम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि मेहनतकश जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब वर्तमान व्यवस्था के कानिबारी रूपान्तरण के बिना भिन मचना है। अने शोषक व आक्रामक सारतत्व को छुटाने के लिए पूंजीवाद अनेक प्रकार की पत्र-गमर्षक धारणाओं का सहारा लेता है।

'पूंजीवाद के रूपान्तरण' की आधारभूमि के रूप में 'पूंजी के जनवादीकरण' की कल्पित रूपा का उपयोग किया जाता है। पूंजीवादी अर्थशास्त्री दावा करते हैं कि सार्वजनिक निगम तथा जनता के बीच शेरों के व्यापक वितरण का अर्थ यह है कि पूंजी का जनवादीकरण हो गया है और सभी शेरधारारी पूंजी के सह-स्वामी हैं तथा लाभान्ग प्राप्त करने वाले हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री एडोल्फ बर्न ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मेहनतकश वास्तव में पूंजीवादी उद्यमों के मालिक हैं और निजी स्वामित्व का अस्तित्व समाप्त हो गया है। ये 'विद्वान' समाज के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच धनराशि तथा मूल्य के आधार पर शेरों के वितरण की पूरी तरह उपेक्षा करते हैं। इस बात के साक्ष्य हैं कि समस्त शेरों का दो-तिहाई से अधिक भाग (मूल्य के अनुसार) ऊंची आमदनी वालों, नाम लिया जाये तो पूंजीपति, बड़े जमींदारी आदि के हाथों में संकेन्द्रित है। मजदूरों के पास बड़ी बचत नहीं होती है और जो कुछ संसाधन वे बचा पाते हैं, उसे मुसीबत के दिनों के लिए (अर्थ-मिक रूप से उन दिनों के लिए जब वे बेरोजगार हो जाते हैं) सुरक्षित रखते हैं। बड़े पूंजीपति छोटे व मध्यम शेरधारकों की क्रीमत पर अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए स्टॉक-एक्सचेंज की सट्टेबाजी का घालाकी भरा उपयोग करते हैं।

लेनिन ने इस संबंध में लिखा है—“शेरों के स्वामित्व का जनवादीकरण जिससे पूंजीवाद कुतकों और अवसरवादी तथाकथित 'सामाजिक जनवादी' पूंजी के जनवादीकरण तथा छोटे स्तर के उत्पादन के महत्त्व एवं भूमिका के मजबूत हो जाने आदि की आशा रखने हैं (या कहें कि वे आशा करते हैं) वास्तव में विनाश अल्प-तंत्र की शक्ति में वृद्धि करने का एक तरीका है।” इस प्रकार पूंजी के जनवादीकरण और 'स्वामियों के क्षेत्र विस्तार' की जगह वास्तविकता में पूंजीपतियों के एक छोटे समूह के हाथों में पूंजी का केन्द्रीकरण हो रहा है।

'पूंजीवाद के रूपान्तरण' के पक्ष में दूसरा तर्क तथाकथित 'प्रबंध-कृति' का है। यहाँ इसका मतलब यह है कि आधुनिक परिस्थिति में, पूंजीपतियों के उत्प-कथित रूप में अर्थव्यवस्था पर से नियंत्रण छो दिया, नियंत्रण का भार किराये पर रने गये (वेतनभोगी—अनु०)

प्राधिकार हो गया है।

आधुनिक पूंजीवाद के अंतर्गत, जबकि समुक्त उद्यम व्यापक रूप में है, पूंजी के भीतर (निवेश की गयी राशि के अनुकूल) स्वामित्व का विभाजन विशाल क्षेत्र में फैल गया है। कार्ल मार्क्स ने इस पर बहुत पहले ही ध्यान दिया था। पूंजीवादी विचारक जो यह कहते हैं कि संयुक्त-स्टाक उद्यम राष्ट्रीय है, स्वामित्व के रूप के प्रश्न के स्थान पर प्रबंध के रूप के प्रश्न को रख देते हैं। वे इस तथ्य को भी भूल जाते हैं कि उद्यम की प्रकृति प्रबंध के रूप पर निर्भर होती है।

पूंजीवादी विचारक व पूंजीवादी समाज में प्रबंधक की भूमिका को भी शलत रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्पष्ट रूप में प्रबंधकों का कोई विशेष वर्ग नहीं है। जो प्रबंध व्यवस्था के नीचे वाले क्रम में है अर्थात् जो भौतिक-उत्पादन में प्रत्यक्ष शामिल होते हैं, वे वेतनभोगी हैं! वे नीति-संबंधी निर्णय नहीं करते हैं और लाभ के बंटवारे में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जहाँ तक शीर्षस्थ प्रबंधकों का सवाल है, वे उद्यम की गतिविधियों का निर्देशन तभी कर सकते हैं जब उनके पास 51 प्रतिशत शेयरों का नियंत्रण हो अर्थात् जब वे पूंजीपति हों।

इसलिए 'प्रबंध-शक्ति' के दावे वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं। वे वित्तीय अल्प-संख्य की सर्वोच्चता और उनके बढ़ने मुनाफ़ों को छुपाने के लिए गढ़े जाते हैं।

1960 के दशक में, पूंजीवादी साहित्य में सम-अभिरूपता का सिद्धांत व्यापक प्रचलित हो गया था। यह सिद्धांत अनिवार्यतः जो दावा करता है, यह यह है कि जैसे-जैसे पूंजीवाद तथा समाजवाद का विकास होता है, वे दोनों बढ़ती मात्रा में समान विशेषताओं को अपनाते लगते हैं और दोनों के बीच का अंतर धीरे-धीरे मिटने लगता है। पूंजीवादी विचारक कहते हैं, यह इस तथ्य के कारण होता है कि दोनों व्यवस्थाओं में औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दशाएँ अधिक-से-अधिक समान होनी जा रही हैं। सम-अभिरूपता का सिद्धांत स्वामित्व के भिन्न रूपों—समाजवादी व निजी पूंजीवादी—में उत्पन्न आधारभूत अंतर की उपेक्षा करता है। न तो प्रौद्योगिक विकास और न ही सघटन व प्रबंध की कुछ सामान्य विशेषताएँ इस अंतर को समाप्त कर सकती हैं। पूंजीवाद के अंतर्गत प्रौद्योगिक विकास व अधिक कार्य-क्षमता का उपयोग अधिक तीव्र धम, मजदूर वर्ग के बढ़े हुए शोषण में होना है और इसका परिणाम पूंजीवाद के अंतर्बिरोधों में अधिक सहूलता होती है। समाजवाद के अंतर्गत तकनीकी प्रगति समस्त जनगण के जीवन-स्तरों में सुधार की आधारभूतता के रूप में और धम के भार को कम करने के लिए काम आती है।

सम-अभिरूपता का सिद्धांत इस तथ्य का भी विशेष अनिश्चित है कि एक के रूप में पूंजीवाद स्वयं को प्रतिष्ठाहीन बना चुका है।

जो वे हड़तालों की बढ़ी संख्या और वर्ग-संघर्षों का वधीर होना

आधिपत्य को छुपाने के लिए गढ़ी जाती है। इजारेदार पूँजीपति वर्ग सब जगह यह ध्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि मेहनतकश जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वह सब वर्तमान व्यवस्था के क्रांतिकारी रूपांतरण के बिना मिल सकता है। अपने शोषक व आक्रामक सारतत्त्व को छुपाने के लिए पूँजीवाद अनेक प्रकार की पस-समर्थक धारणाओं का सहारा लेता है।

'पूँजीवाद के रूपांतरण' की आधारभूमि के रूप में 'पूँजी के जनवादीकरण' को कल्पित कथा का उपयोग किया जाता है। पूँजीवादी अर्थशास्त्री दावा करने हैं कि सार्वजनिक नियम तथा जनता के बीच शेरयो के व्यापक वितरण का अर्थ यह है कि पूँजी का जनवादीकरण हो गया है और सभी शेरघारी पूँजी के सह-स्वामी हैं तथा लाभान्वित प्राप्त करने वाले हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री एडोल्फ बर्ले ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मेहनतकश वास्तव में पूँजीवादी उद्यमों के मानिक हैं और निजी स्वामित्व का अस्तित्व समाप्त हो गया है। ये 'सिद्धांत' समाज के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच धनराशि तथा मूल्य के आधार पर शेरयों के वितरण की पूरी तरह उपाशा करते हैं। इस बात के साक्ष्य हैं कि समस्त शेरयों का दो-तिहाई से अधिक भाग (मूल्य के अनुसार) ऊँची आमदनी वालों, नाम लिया जाने तो पूँजीपति, बड़े जमींदारों आदि के हाथों में संकेन्द्रित है। मजदूरों के पास बड़ी बचत नहीं होती है और जो कुछ ससाधन वे बचा पाते हैं, उसे मुसीबत के दिनों के लिए (प्राथमिक रूप से उन दिनों के लिए जब वे बेरोजगार हो जाते हैं) सुरक्षित रखते हैं। बड़े पूँजीपति छोटे व मध्यम शेरघारकों की कीमत पर अपनी पूँजी बचाने के लिए स्टॉक-एक्सचेंज की सट्टेबाजी का सामाजी भरा उपयोग करते हैं।

सेनिन ने इस संबंध में लिखा है—“शेरयों के स्वामित्व का जनवादीकरण त्रिमणे पूँजीवाद कुतकों और अवसरवादी तथाकथित 'सामाजिक जनवादी' पूँजी के जनवादीकरण तथा छोटे स्तर के उत्पादन के महत्व एवं भूमिका के मजबूत हो जाने आदि की आशा रखने हैं (या कहें कि वे आशा करने हैं) वाग्य में विलीय जन-संघ की शक्ति में वृद्धि करने का एक तरीका है।” इस प्रकार पूँजी के जनवादीकरण और 'स्वामियों के बीच वित्तार' की जगह वास्तविकता में पूँजीपतियों के एक छोटे समूह के हाथों में पूँजी का केन्द्रीकरण हो रहा है।

'पूँजीवाद के रूपांतरण' के पक्ष में दूसरा तर्क तथाकथित 'व्यवस्था-वादि' का है। वही इसका मतलब यह है कि आधुनिक परिस्थितियों में पूँजीपतियों के तथाकथित रूप से अर्थव्यवस्था पर से नियंत्रण छोड़ दिया है और अब वितरण का कार्य विचारों पर रहे बने (विचारधारा—अनु०) सैनवरी, 'जनसम के प्रतिनिधियों का

प्राधिकार हो गया है।

आधुनिक पूंजीवाद के अंतर्गत, जबकि समुक्त उद्यम व्यापक रूप में हैं, पूंजी के भीतर (निवेश की गयी राशि के अनुकूल) स्वामित्व का विभाजन विशाल क्षेत्र में फैल गया है। कार्ल मार्क्स ने इस पर बहुत पहले ही ध्यान दिया था। पूंजीवादी विचारक जो यह कहते हैं कि संयुक्त-स्टाक उद्यम राष्ट्रीय हैं, स्वामित्व के रूप के प्रश्न के स्थान पर प्रबंध के रूप के प्रश्न को रख देते हैं। वे इस तथ्य को भी भूल जाते हैं कि उद्यम की प्रकृति प्रबंध के रूप पर निर्भर होती है।

पूंजीवादी विचारक व पूंजीवादी समाज में प्रबंधक की भूमिका को भी उलट रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्पष्ट रूप में प्रबंधकों का कोई विशेष वर्ग नहीं है। जो प्रबंध व्यवस्था के नीचे वाले क्रम में है अर्थात् जो भौतिक-उत्पादन में प्रत्यक्ष शामिल होते हैं, वे वेतनभोगी हैं। वे नीति-संबंधी निर्णय नहीं करते हैं और लाभ के बंटवारे में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जहाँ तक भौतस्य प्रबंधकों का सवाल है, वे उद्यम की गतिविधियों का निर्देशन तभी कर सकते हैं जब उनके पास 51 प्रतिशत शेयरों का नियंत्रण हो अर्थात् जब वे पूंजीपति हो।

इसलिए 'प्रबंध-क्रांति' के दावे वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं। वे वित्तीय बल्प-तंत्र की सर्वोच्चता और उनके बढ़ते मुनाफों को छुपाने के लिए मढ़े जाते हैं।

1960 के दशक में, पूंजीवादी साहित्य में सम-अभिरूपता का सिद्धांत व्यापक प्रचलित हो गया था। यह सिद्धांत अनिवार्यतः जो दावा करता है, वह यह है कि जैसे-जैसे पूंजीवाद तथा समाजवाद का विकास होता है, वे दोनों बढ़ती मात्रा में समान विशेषताओं को अपनाने लगते हैं और दोनों के बीच का अंतर धीरे-धीरे मिटने लगता है। पूंजीवादी विचारक कहते हैं, यह इस तथ्य के कारण होता है कि दोनों व्यवस्थाओं में औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टाएँ अधिक-से-अधिक समान होनी आ रही हैं। सम-अभिरूपता का सिद्धांत स्वामित्व के भिन्न रूपों—समाजवादी व निजी पूंजीवादी—से उत्पन्न आधारभूत अंतर की उपेक्षा करता है। न तो प्रौद्योगिक विकास और न ही सघटन व प्रबंध की कुछ सामान्य विशेषताएँ इस अंतर को समाप्त कर सकती हैं। पूंजीवाद के अंतर्गत प्रौद्योगिक विकास व अधिक कार्य-दायता का उपयोग अधिक तीक्ष्ण धर्म, मजदूर वर्ग के बड़े हुए शोषण में होता है और इसका परिणाम पूंजीवाद के अतिविरोधी में अधिक गहनता होती है। समाजवाद के अंतर्गत तकनीकी प्रगति समस्त जनगण के जीवन-स्तरी में सुधार की आधारशिला के रूप में और धर्म के भार को कम करने के लिए काम आती है।

सम-अभिरूपता का सिद्धांत इस तथ्य का भी विशेष प्रतिबिम्ब है कि एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में पूंजीवाद स्वयं को प्रतिष्ठाहीन बना चुका है।

पूंजीवादी देशों में हड़तालों की बढ़ी संख्या और वर्ग-संघर्षों का गभीर होना

